रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED No. D. (D.N.)—73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 24, 1982/श्रावण 2, 1904

No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 24, 1982/SRAVANA 2, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचना

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1982

स्टाम्प

का०आ० 2609—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अम्बालाल साराभाई इन्टर-प्राइजेज लि० को सात लाख पचास हजार रुपए के उस समेकित स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने की अनुमति देती है, जो उक्त कम्पनी द्वारा जारी किए जाने वाले नौ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ रुपए के अंकित मूल्य के ऋण पत्रों के रूप में बंधपत्रों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क के रूप में प्रभार्य है।

[संख्या 23/82-स्टाम्प/फा०सं० 33/21/82-बि०क०]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 3rd July, 1982

STAMPS

S O. 2609.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Ambalal Sarabhai Enterprises Limited to pay consolidated stamp duty of seven lakhs fifty thousand rupee only, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of debentures of the face value of nine crores, ninety-nine lakhs, ninety-nine thousand, nine hundred of rupees to be issued by the said Company.

[No 23/82-Stamps]

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1982

स्टाम्प

का० आ० 2610—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 29 अप्रैल, 1982 की अधिसूचना संख्या 19/82 स्टाम्प, फा० संख्या 33/1/82 बि० क० (स० का० आ० 1958) में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् —

उक्त अधिनियम की सारणी में क्रम संख्या 16 के सामने, स्तम्भ 3 में "20 35" अंकों के स्थान पर "21.68" अंक रखे जाएंगे।

[संख्या 24/82-स्टाम्प/फा०संख्या 33/1/82 बि०क०]

भगवान दास, अवर सचिव

New Delhi, the 9th July, 1982

STAMPS

S.O. 2610.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. 19/82-Stamps F. No. 33/1/82-ST (No. S.O. 1958), dated the 29th April, 1982, namely :—

In the Table to the said notification against serial number 16, in column 3, for the figures "20.35" the figures "21.68" shall be substituted.

[No. 24/82-Stamps/F. No. 33/1/82-ST]

BHAGWAN DAS, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 मई, 1982

आयकर

का० आ० 2611.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम एजेंसी, अहमदाबाद" को निर्धारण वर्ष 1975-76 से 1982-83 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4625/फा०सं० 197/19/80 आ०क (ए 1)]

New Delhi, the 22nd May, 1982

(INCOME-TAX)

S.O. 2611.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Drought Prone Area Programme Agency, Ahmedabad" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1975-76 to 1982-83.

[No. 4625/F. No. 197/19/80-IT (AI)]

का० आ० 2612.—केन्द्रीय सरकार, आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, "साबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन एण्ड मेमोरियल ट्रस्ट" को निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के अंतर्गत [redacted] के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती

[सं० 4626/फा० सं० 197/17/82 आ० क० (ए 1)]

S.O. 2612.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 4626/F. No. 197/17/82-IT (AI)]

नई दिल्ली, 25 मई, 1982

(आय कर)

का०आ० 2613.—केन्द्रीय सरकार, आय कर आधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री व्यास राजा मट्ठ" को निर्धारण वर्ष 1980-81 से 1982-83 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4636/फा० सं० 197/109/81 आ० क० (ए 1)]

New Delhi, the 25th May, 1982

(INCOME-TAX)

S.O. 2613.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Vyasaraja Mutt' for the purpose of the said section for the preiod covered by the assessment years 1980-81 to 1982-83.

[No. 4636/F. No. 197/109/81-IT (AI)]

का० आ० 2614.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "चिल्ड्रन्स लिटल थियेटर" को निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1983-84 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4637/फा० सं० 197/148/81 आ०क० (ए 1)]

S.O. 2614.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Children's Little Theatre" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 to 1983-84.

[No. 4637/F. No. 197/148/81-IT (AI)]

नई दिल्ली, 2 जून, 1982

(आय-कर)

का. आ. 2615.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उप धारा (23-ग) के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "गंगा-जलि निधि न्यास" को निर्धारण वर्ष 1978-79 से 1982-83 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं. 4652/फा. सं. 197/53/80-आ क. (ए 1)]

New Delhi, the 2nd June, 1982

(INCOME-TAX)

S.O. 2615.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Gangajali Fund Trust" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1978-79 to 1982-83.

[No. 4652/F. No. 197/53/80-IT (AI)]

का. आ. 2616.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "दि अहमदाबाद टैक्सटाइल मिल्स फाउंडेशन" को निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं. 4653/फा. सं. 197/122/81-आ.क. (ए 1)]

S.O. 2616.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Ahmedabad Textile Mills Foundation" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 4653/F. No. 197/122/81-IT (AI)]

का. आ. 2617.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री अमरेश्वर स्वामी मंदिर अमरावती" को निर्धारण वर्ष 1981-82 और 1982-83 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं. 4654/फा. सं. 197/114/81-आ.क. (ए 1)]

S.O. 2617.—In exericse of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Amareswaraswami Temple, Amravathi" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 and 1982-83.

[No. 4654/F. No. 197/114/81-IT(AI)]

नई दिल्ली, 5 जून, 1982

का. आ. 2618.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उप-धारा (23-ग) के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेन्टर (रजि.)" को निर्धारण वर्ष 1982-83 और 1983-84 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं. 4667/फा. सं. 197/34/82-आ.क (ए 1)]

New Delhi, the 5th June, 1982

S.O. 2618.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "India Islamic Cultural Centre (Regd.)" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 and 1983-84.

[No. 4667/F. No. 197/34/82-IT (AI)]

नई दिल्ली, 9 जून, 1982

का. आ. 2619.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 की 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'सर होमी मेहता पूर्त न्यास' को निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं. 4673/फा. सं. 197/71/81-आ.क. (ए 1)]

New Delhi, the 9th June, 1982

S.O. 2619.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sir Homi Mehta Charity Trust" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 to 1982-83.

[No. 4673/F. No. 197/71/81-IT (AI)]

का. आ. 2620.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री रामचन्द्र मिशन" को निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 वर्ष के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं. 4674/फा. सं. 197/218/81-आ.क. (ए 1)]

S.O. 2620.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Ram Chandra Mission" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 4674/F. No. 197/218/81-IT (AI)]

का. आ. 2621.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "मराठी मिशन" को निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1982-83 वर्ष के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं 4675/फा. सं. 197/155/78-2 आ।.क. (ए 1)]

मिलाप जैन, अवर सचिव

S.O. 2621.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Marathi Mission" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1979-80 to 1982-83.

[No. 4675/F. No. 197/155/78-IT (AI]

MILAP JAIN, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 26 जून, 1982

का० आ० 2622.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री बी०बी० पटेल को कच्छ ग्रामीण बैंक, भुज का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1-7-1982 से प्रारम्भ होकर 30-6-1985 को समाप्त होने वाली अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री बी०बी० पटेल अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं० एफ० 2-50/82—आर०आर०बी०]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 26th June, 1982

S.O. 2623.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government appoints Shri B. B. Patel as the Chairman of the Kutch Gramin Bank, Bhuj and specifies the period commencing on the 1-7-1982 and ending with the 30-6-1985 as the period for which the said Shri B. B. Patel shall hold office as such Chairman

[No. F. 2-50/82-RRB]

का०आ० 2623.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री डी०के० पाल को मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुबनी का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1-4-1982 से प्रारम्भ होकर 31-3-1985 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री डी०के० पाल अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 2-56/82-आर०आर०बी०]

S.O. 2623.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri D. K. Paul as the Chairman of the Madhubani Kshetriya Gramin Bank, Madhubani and specifies the period commencing on the 1-4-1982 and ending with the 31-3-1985 as the period for which the said Shri D. K. Paul shall hold office as such Chairman.

[No. F-2-56/82-RRB]

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1982

का०आ० 2624.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 31 दिसम्बर, 1982 तक की अवधि के लिए तिरुकोईलूर कोआपरेटिव बैंक लि० तिरुकोईलूर पर वहां तक लागू नहीं होंगे जहां तक इनका संबंध इस बैंक द्वारा गैर बैंकिंग आस्ति अर्थात् तिरुकोइलूर राजस्व ग्राम आर०एस० संख्या 373/3 में 0.45 एकड़ सिंचित भूमि की धारिता से है।

[संख्या 8-22/82 ए०सी०]

राम बेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 5th July, 1982

S.O. 2624.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act shall not apply to the Tirukoilur Co-operative Urban Bank Ltd., Tirukoilur so far as they relate to its holding of a non-banking asset viz. 0.45 acre of wet land at Tirukoilur Revenue Village, R. S. No. 373/3 for the period from the date of publication of this notification in the Gazette of India to 31-12-1982.

[No. 8-22/82-AC]

RAAM BEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जून, 1982

का०आ० 2625.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खंड 8 के उपखंड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् श्री बी० रत्नाकर को 30 जून, 1982 से आरम्भ होने वाली और 29 जून, 1985 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ० 9/23/82-बी० ओ०-1(1)]

New Delhi, the 30th June, 1982

S.O. 2625.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri B. Ratnakar as the Managing Director of the Canara Bank for a period commencing on 30th June, 1982 and ending with 29th June, 1985.

[No. F. 9/23/82-BO.I(1)]

का०आ० 2626.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 7 के साथ पठित खण्ड 5 के उपखण्ड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् श्री बी० रत्नाकर को, जिन्हें 30 जून, 1982 से केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से केनरा बैंक के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ० 9/23/82-बी०ओ०-1(2)]

अशोक नारायण, निदेशक

S.O. 2626.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri B. Ratnakar, who has been appointed as Managing Director of Canara Bank with effect from 30th June, 1982 to be the Chairman of the Board of Directors of the Canara Bank with effect from the same date.

[No. F. 9/23/82-BO.I(2)]

ASHOK NARAYAN, Director

नयी दिल्ली, 7 जुलाई, 1982

का. आ. 2627.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उप धारा (4) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एम. रामकृष्णैया को 2 जनवरी 1983 से आरम्भ होने वाली और 31 जुलाई, 1983 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनर्नियुक्त करती है।

[सं. एफ. 7/1/82-बी.ओ.1(1)]

New Delhi, the 7th July, 1982

S.O. 2627.—In pursuance of clause (a) of sub-section (1) read with sub-section (4) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby re-appoints Shri M. Ramakrishnayya as a Deputy Governor of the Reserve Bank of India for the period commencing on 2nd January, 1983 and ending with 31st July, 1983.

[No. F. 7/1/82-BO. I(1)]

का. आ. 2628.—राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 6 की उपधारा (2) के साथ पठित उसकी उप-धारा (1) के खण्ड (क) और धारा 7 की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, एतद्द्वारा श्री एम. रामकृष्णैया को 12 जुलाई, 1982 से आरम्भ होकर 31 जुलाई, 1983 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के लिए निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. एफ. 7/1/82-बी.ओ.1(2)]

च. वा. मीरचन्दानी, उप-सचिव

S.O. 2628.—In pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 6 read with sub-section (2) thereof and sub-section (1) of section 7 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri M. Ramakrishnayya as the Chairman of the Board of Directors of the National Bank for Agriculture and Rural Development for the period commencing on 12th July, 1982 and ending with 31st July, 1983.

[No. F. 7/1/82-BO.I(2)]

का.आ. 2629.—राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 6 की (2) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) के खण्ड (क) और धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, एतद्द्वारा श्री संत दास को 12 जुलाई, 1982 से आरम्भ होने वाली और 9 जून, 1985 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं. एफ. 7/1/82-बी.ओ.1(3)]

S.O. 2629.—In pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 6 read with sub-section (2) thereof and clause (a) of sub-section (1) of section 8 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981, (61 of 1981), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri Sant Dass as the Managing Director of the National Bank for Agriculture and Rural Development for the period commencing on 12th July, 1982 and ending with 9th June, 1985.

[No. F. 7/1/82-BO.I(3]

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1982

का०आ० 2630.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 53 की उप धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 12 जून, 1962 की अधिसूचना स० सा० नि० 1906 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न फार्म 'क' के स्थान पर, इस अधिसूचना के साथ विनिर्दिष्ट अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी ।

यह अधिसूचना 12 जुलाई, 1982 से प्रभावी होगी ।

[सं०एफ० 10/4/82-बी.ओ- 1]

अ० आ० मीरचन्दानी, उप सचिव

फार्म क

अनुसूची

की स्थिति के अनुसार बैंकिंग विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकलापों का विवरण

देनदारियां	रुपये	परिसम्पत्तियां	रुपये
प्रदत्त पूंजी		नोट	
प्रारक्षित निधि		रुपया सिक्के	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		छोटे सिक्के	
जमा राशियां :-		खरीदे तथा भुनाए गए बिल	
(क) सरकार : —		(क) अन्तरिक	
(1) केन्द्रीय सरकार		(ख) बाह्य	
(2) राज्य सरकारें ।		(ग) सरकारी खजाने के बिल ।	
(ख) बैंक :—		विदेशों में रखे गए बकाया शेष	
(1) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक		निवेश	
(2) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक		निम्नलिखित को दिये गए ऋण तथा अग्रिम : —	
(3) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक		(1) केन्द्रीय सरकार	
(4) अन्य बैंक ।		(2) राज्य सरकारें* ।	
(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की जमाएं :—		निम्नलिखित को दिये गए ऋण तथा अग्रिम —	
(1) एन०आर०सी० (एल०टी०ओ०) निधि		(1) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	
(2) एन०आर०सी० (स्थिरीकरण) निधि ।		(2) राज्य सहकारी बैंक	
(घ) अन्य :		(3) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	
देय बिल		(4) अन्य ।	
अन्य देनदारियां ।		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से ऋण,	
		अग्रिम तथा निवेश :—	
		(क) निम्नलिखित को दिये गए ऋण तथा अग्रिम : —	
		(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	
		(2) भारतीय निर्यात-आयात बैंक ।	
		(ख) निम्नलिखित द्वारा जारी किये गए बाण्डों/डिबेंचरों में निवेश :—	
		(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	
		(2) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	
		अन्य परिसम्पत्तियां	
रुपये.....			रुपये

*राज्य सरकारों के साधन तथा स्रोत अग्रिम एवं अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल है।

दिनांक :

गवर्नर :

New Delhi, the 9th July, 1982

S.O. 2630.—In pursuance of Sub-Section (1) of Section 53 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby directs that following amendment shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. S.O. 1906, dated the 12th June, 1962, namely :—

For form 'A' annexed to the said notification, the form specified in the schedule to this notification shall be substituted.

This notification shall come into force on the 12th of July, 1982.

[F.10/4/82-BO.I]
C.W. MIRCHANDANI, Dy Secy.

SCHEDULE

FORM A

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the

Liabilities Rs.	Assets Rs.
Capital Paid up	Notes
Reserve Fund	Rupee Coin
National Industiral Credit	Small Coin
(Long Term Operations) Fund	Bills Purchased and Discounted:—
	(a) Internal
	(b) External
	(c) Government Treasury Bills.
Deposits:—	
(a) Government:—	Balances Held Abroad
(i) Central Government	Investments
(ii) State Governments.	Loans and Advances to:—
(b) Banks:—	
(i) Scheduled Commercial Banks	(i) Central Government
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	(ii) State Governments*
(iii) Non-Scheduled State Cooperative. Banks	Loans and Advances to:—
(iv) Other Banks.	(i) Scheduled Commerical Banks
(c) NABARD Deposits:	(ii) State Co-operative Banks
(i) NRC (LTO) Fund	(iii) NABARD
(ii) NRC (Stabilis tion (Fund)	(iv) Others
(d) Others	Loans, Advances and Investments from National Industrial Crdit (Long term operations) fund
Bills Payable	(a) Loan and Advances to:—
Other Liabilities	(i) Industrial Development Bank of India
	(ii) Export Import Bank of India
	(b) Investments in bonds/debentures issued by:—
	(i) Industrial Development Bank of India
	(ii) Export Import Bank of India.
	Other Assets
RUPEES	RUPEES

* Includes ways & means advances and temporary overdrafts to State Governments.

Dated the :

GOVERNOR

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1982

का. आ. 2631.—राजनयिक तथा कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) के खण्ड 2 की धारा (क) के अनुपालन में केन्द्र सरकार, इसके द्वारा भारत का सहायक हाई कमीशन, लिवरपूल, यूनाइटेड किंगडम में सहायक श्री कुलदीप चन्द्र को तत्काल से कौंसली एजेन्ट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[सं. टी-4330(2)/82]

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

S.O. 2631.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948) the Central Government hereby authorise Shri Kuldip Chandra, Assistant in the Assistant High Commission of India, Liverpool, U. K., to perform the duties of Consular Agent with immediate effect.

[No. T-4330 (2)/82]

का. आ. 2632.—राजनयिक तथा कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41 वां) के खंड 2 की धारा (क) के अनुपालन में केन्द्र सरकार, इसके द्वारा भारत का हाई कमीशन, पोर्ट लुई में सहायक श्री आई. एस. बेणि-

बाल को तत्काल से कोंसली एजेन्ट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[सं. टी-4330(2)/82]

जे. हजारी, उप सचिव

S.O. 2632.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948) the Central Government hereby authorise Shri I. S. Beniwal, Assistant in the High Commission of India, Port Louis to perform the duties of a Consular Agent with immediate effect.

[No. T-4330(2)/82]

J. HAZARI, Dy. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1982

का.आ. 2633.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स डा. रमन सी. अमीन (कार्गो सुपरिन्टेन्डेन्स सर्वेयर्स, सैम्पलर एण्ड एनालाइजर्स) 61, चीनाथम्बी स्ट्रीट- मद्रास-600001 को इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज तथा अयस्क ग्रुप-1 का निर्यात से पूर्व निरीक्षण के लिए अभिकरण के रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता देती है ।

अनुसूची

1. मैंगनीज डायआक्साइड रहित कच्चा मैंगनीज धातु
2. कच्चा लोहा
3. फैरोमैंगनीज की धातुमल सहित फैरोमैंगनीज
4. निस्तप्त बोक्साइड सहित बोक्साइड ।

[संख्या 5(2)/75-ई आई तथा ई पी]

स. प्रकाश, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

New Delhi, the 24th July, 1982

S.O. 2633.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby recognises for a period of one year M/s. Dr. Raman C. Amin (Cargo Superintendents Surveyors, Samplers and Analysers) 61, Chinnathambi Street, Madras-600001, as an agency for the inspection of Minerals and Ores Group I specified in Schedule annexed hereto prior to export.

SCHEDULE

1. Manganese Ore, Excluding manganese dioxide.
2. Iron Ore.
3. Ferromanganese, including ferromanganese slag.
4. Bauxite, including calcined bauxite.

[No. 5(2)/75-EI&EP]

S. PRAKASH, Under Secy.

संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय

(केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र)

निरस्त-आदेश

नई दिल्ली, 29 मई, 1982

का०आ० 2634.—मैसर्स चन्दोक एण्ड कं० 575, गांधी क्लाथ मार्किट, चांदनी चौक, दिल्ली को एक आयात लाइसेंस सं० पी/जेड/0311598/सी दिनांक 16-6-81 वास्ते 169108 रु० मूल्य मेवा (काजू और खजूर के अतिरिक्त) के आयात हेतु जारी किया गया था। उक्त फर्म ने यह सूचित किया है कि उपरोक्त लाइसेंस की एक्सचेंज हेतु कापी अमृतसर कस्टम (अटारी रोड) पर पंजीकृत हुए तथा बिना इस्तेमाल किए ही खो गई है ।

आवेदक फर्म ने अपने कथन के समर्थन में अब शपथ-पत्र आयात-निर्यात की कार्य विधि पुस्तिका 1982-83 के पैरा 352-354 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। मैं सन्तुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल एक्सचेंज-हेतु कापी खो गई है ।

अतः आयात व्यापार नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 (यथा संशोधित) की धारा 9(घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उपरोक्त लाइसेंस की मूल एक्सचेंज कापी को निरस्त करने का आदेश देता हूं ।

आवेदक की प्रार्थना पर अब आयात निर्यात की कार्यविधि पुस्तिका 1981-82 के अनुसार उपरोक्त लाइसेंस की एक्सचेंज कापी की अनुलिपि (डुप्लीकेट कापी) जारी करने पर विचार किया जायेगा ।

[सं० ड्राई फ्रूट्स /556/ए० एम०सी०82/डी० एफ०/ सी० एए०]

कु० माया दास गुप्ता, उप मुख्य नियंत्रक-आयात-निर्यात

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

Office of the Jt. Chief Controller of Imports & Exports

(Central Licensing Area)

Cancellation Order

New Delhi, the 29th May, 1982

S.O. 2634.—M/s. Chandhok and Company, 575, Gandhi Cloth Market, Chandni Chowk, Delhi was granted Import licence No. P/Z/0311598/C dt. 16-6-81 for Rs. 169108 for import of Dry Fruits (excluding Cashew Nuts and Dates). The firm have reported that Exchange Contract purpose copy same has been lost/misplaced after having been registered tered with Amritsar Custom House, Attari Road and not utilised at all.

The applicant firm has filed an affidavit in support of the above statement as required under para 352-354 of Hand Book of Import-Export Procedure 1982-83. I am satisfied that the original Exchange Control purpose copy of the said licence has been lost/misplaced.

In exercise of the powers conferred on me under Section 9(d) of Import Trade Control Order, 1955 dt. 2-12-1955 as amended. I order the cancellation of the Exchange Purpose copy of the said licence.

The applicants cases will now be considered for the issue of Duplicate licence (Exchange Purpose copy) in accordance with para 352-354 of Hand Book of Rules and procedure 1982-83.

[No. Dry Fruits|556|A.M. 82|D|F|CLA]

MISS MAYA DASS GUPTA, Dy. Chief Controller of Imports and Exports

For Jt. Chief Controller of Imports & Exports

(मुख्य नियंत्रक आयातनिर्यात कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली 22 जून, 1982

का०आ० 2635.—सर्वश्री अपर्णा आश्रम, मन्तालाई, पी०ओ० मन्तालाई जिला ऊधमपुर, जम्मू और कश्मीर (भारत) को हस्तचालित बिजली से चलने वाली स्नोकटर मशीन का यू०एस०ए० से आयात के लिए 80,000 रुपए के लिए एक सीमाशुल्क निकासी परमिट सं० पी/जे/0390038/एन/एम एस/82/एच/81/ए एल एस दिनांक 16-3-1982 प्रदान किया गया था। आवेदक ने उपर्युक्त सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रति उनसे खो गई है या अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह भी बताया गया है कि सीमाशुल्क निकासी परमिट किसी भी सीमाशुल्क अधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराया गया था और इस प्रकार उसका मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है।

2. अपने इस तर्क के समर्थन में, लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित स्टाम्प पेपर पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार, मैं संतुष्ट हूं कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट सं० पी०/जे/0390038/एन/एम एस/82/एच/81/ए एल एस, दिनांक 16-3-82 आवेदक से खो गया है/अस्थानस्थ हो गया है। यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की उपधारा 9 (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री अपर्णा आश्रम को जारी किए गए सीमाशुल्क निकासी परमिट सं० पी०/जे/0390038/एन/एम एन/82/एच/81/ए एल एस, दिनांक 16-3-1982 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

3. सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति आवेदक को अलग से जारी की जा रही है।

[सं० 7/59/ए एम-82/ए एल एस/574]

जे० पी० सिंघल, उपमुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

New Delhi, the 22nd June, 1982

S. O. 2035.—M/s. Aparna Ashrama, Mantalai, P.O. Muntalal, District Udhampur, J&K (India) were granted a CCP No. P|J|0390038|N|MN|82|H/81/ALS dated 16th March, 1982 for Rs. 80,000 for one number Hand Guided Power Driven Snow Cutter from USA. The applicant have applied for issue of a Duplicate copy of the above mentioned CCP on the ground that the original CCP has been lost or misplaced. It has further been stated that the CCP was not registered with any Customs authority and as such the value of CCP has not been utilised at all.

2. In support of this contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly notarised properly. I am accordingly satisfied that the original CCP No. P/J/0390038/N|MN|82|H|81|ALS dated 16th March, 1982 has been lost/misplaced by the applicant. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7th December, 1955 as amended from time to time, the said original CCP No. P|J|0390038|N|MN|82/H/81/ALS dated 16th March, 1982 issued to M/s. Aparana Ashrama is hereby cancelled.

3. A duplicate copy of CCP is being issued to the party separately.

[No. 7|59|AM-82|AIS|574]

J. P. SINGHAL, Dy. Chief Controller of Imp.-Exp.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1982

का०आ० 2636.—सर्वश्री प्रोग्रेसिव प्रिन्टर्स, 99, कोरल मर्चेन्ट स्ट्रीट, मद्रास को मुक्त विदेशी मुद्रा के अन्तर्गत पूंजीगत माल (मुद्रण मशीन) के आयात के लिए 3,76,258/-रु० (डीएम 86163) के लिये एक आयात लाइसेंस सं० पी०/सीजी 2081899/सी/एक्स एक्स/77/एच/80/सीजी-3, दिनांक 5-12-1980 प्रदान किया गया था जो बाद में विधिवत 4,01,367 रुपए तक बढ़ा दिया गया था (चार लाख, एक हजार तीन सौ सड़सठ) (डीएम 91913 जिसमें भारतीय अभिकर्ता का डीएम 7902 का कमीशन भी शामिल है, जो भारतीय रुपए में भारत में देय है) अब फर्म ने उपर्युक्त आयात लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह भी कहा गया है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराई गई थी और इस प्रकार सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं हुआ है।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक, मद्रास और जिला चेंगलपट्टू के सामने विधिवत शपथ लेकर स्टाम्प पेपर पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार, मैं संतुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस सं० पी/सीजी/2081899/सी/एक्सएक्स/77/एच/80/सीजी-3, दिनांक 5-12-1980 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है/अस्थानस्थ हो गई है। यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9 (सीसी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर उपर्युक्त मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति सं० पी/सीजी/2081899/सी/एक्स-एक्स/77/एच/80/सीजी-3, दिनांक 5-12-1980 जो सर्वश्री प्रोग्रेसिव प्रिन्टर्स, मद्रास को जारी की गई थी, एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

3. उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति पार्टी को अलग से जारी की जा रही है।

[सं० सी जी-3/1340/80/48]

शंकर चन्द, उपमुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात

कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 1982

S.O. 2636.—M/s. The Progressive Printers, 99, Coral Merchant Street, Madrah were granted an import licence No. P|CG|12081899/C/XX/77/H|80|CG. III dated 5-12-1980 for Rs. 3,76, 258|- (DM 86163) subsequently duly enhanced to Rs. 4,01,367 (DM 91,913 inclusive of Indian Agents Commission of DM 7902 to be paid in Indian Rupees in India) for import of capital goods (Printing machine) under Free Foreign Exchange. The firm has applied for issue of Duplicate copy of Customs Purposes copy of the above mentioned licence on the ground that the original Customs Purposes copy of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Customs Purposes copy of the licence was not registered with any Customs authority and as such the value of Customs purpose copy has not been utilised at all.

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public Madras and Chengalpattu Distt. I am accordingly satisfied that the original Customs purposes copy of import

licence No P|CG|2081899/C/XX/77/H|80|CG III dated 5-12-1980 has been lost or misplaced by the firm In exercise of the powers conferred under sub clause 9 (cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Customs purposes copy No P|CG|2081899|C|XX|77|H|80 CG III date 5 12-1980 issued to M S The Progressive Printers Madras is hereby cancelled

3 A duplicate Customs purposes copy of the said licence is being issued to the party separately

[No. CG III/1340|80/48]

SHANKAR CHAND, Dy. Chief Controller of Imports and Exports

for Chief Controller of Imports & Exports

नागरिक पूर्ति मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 जून, 1982

का०आ० 2637.—केन्द्रीय सरकार अग्रिम संविदाएं (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन रोहतक कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी लि० रोहतक द्वारा मान्यता के लिये किए गए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कम्पनी को गुड़ के अग्रिम संविदाओं के बारे में भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये मान्यता प्रदान करती है।

2 एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त कम्पनी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिये जायें।

[मिसिल सं० 12/1/आई०टी०/80]

श्रीमती सुरिन्दर कौर उप सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

New Delhi, the 28th June, 1982

S.O. 2637—The Central Government, in consultation with the Forward Markets Commission, having considered the application for recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Rohtak Krishna Trading Company Ltd, Rohtak, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said company for a period of three years from the date of publication of the notification in the Gazette of India in respect of forward contracts in gur

2 The recognition hereby granted in subject to the condition that the said company shall comply with such directions as may, from time to time be given by the Forward Markets Commission

[F No 12/1/IT|80]

(SMT) SURENDER KAUR, Dy Secy.

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 1982-06-25

का० आ० 2638.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम/एल-1045128 जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची मे दिए गए है। फर्म की लाईसेंस जारी रखने मे रुचि न होने के कारण 1982-04-20 से रद्द कर दिया गया है।

अनुसूची

क्रम संख्या	लाईसेंस संख्या और तिथि	लाईसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक
1	2	3	4	5
1	1045128 1982-02-26	मैसर्स जी० आर० स्टील्स एण्ड एलाइज प्रा० लि०, के० आर० पुरम वाईट फील्ड रोड बंगलौर जिला इनका कार्यालय 130/3 कैलासी पल्लियम, न्यू एक्सटेंशन बंगलौर 560002	संरचना इस्पात (साधारण किस्म)	IS 1977-1975 संरचना इस्पात (साधारण किस्म) की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)

[सीएमडी/55 1045128]

ए० पी० बनर्जी, अपर महानिदेशक

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, 1982-06-25

S.O. 2638—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955 as amended from time to time the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-1045128 particulars of which are given in the Schedule below has been cancelled with effect from 1982-04-20 as the firm is not interested to operate the licence

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process covered by the Licence Cancelled	Relevant Indian Standards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1045128 1982-02-26	M/s. G.R Steels & Alloys Pvt Ltd, K R Puram—Whitefield Road, Whitefield, Bangalore Dist (Office 130/3, Kalasipalyam New Extension, Bangalore-560002	Structural steel (Ordinary Quality)	IS 1977—1975 Specification for structural steel (ordinary quality) (*Second Revision*)

[CMD/55 : 1045128]

A. P. BANERJI

Additional Director General, ISI

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली 23 जून, 1982

का०आ० 2639.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में मथुरा से जलन्धर (पंजाब) तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए पाईप लाइन इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों के बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग के अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, इंडियन आयल कारपोरेशन लि०, मथुरा जालन्धर पाईप लाइन प्रोजेक्ट, 2066/4 अर्बन स्टेट गुड़गांवां को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यावसायी की मार्फत।

अनुसूची

तहसील : थानेसर जिला : कुरुक्षेत्र राज्य : हरियाणा

नाम ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		है०	ए०	वर्ग मी०
1	2	3	4	5
मसाना	42/16 मिन	0	00	76
ह०नं० 96	42/25 मिन	0	06	58
	51/5 मिन	0	10	12
	51/6 मिन	0	10	12
	51/15	0	10	12
	52/21 मिन	0	00	25
	55/1 मिन	0	04	05
	55/10 मिन	0	09	11

[सं० 12020/6/82-प्रोड०]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZER

(Department of Petroleum)

New New, the 23rd June, 1982

S.O. 2639.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum products from Mathura in Uttar Pradesh to Jullundur in Punjab pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Mathura-Jullundur Pipeline New House, Kunjpura Road, Karnal (Haryana).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Tehsil : Thanesar District : Kurukshetra State : Haryana

Name of Village	Khasra No.	H.	A.	Sq.M
MASANA H. NO. 96	42/16 Min.	0	00	76
	42/25 Min.	0	06	58
	51/5 Min.	0	10	12
	51/6 Min.	0	10	12
	51/15 Min.	0	10	12
	52/21 Min.	0	00	25
	55/1 Min.	0	04	05
	55/10 Min.	0	09	11

[No. 12020/6/82-Prod.]

का०आ० 2640.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में मथुरा से जलन्धर (पंजाब) तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए पाईप लाइन इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों के बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, मथुरा जलन्धर पाइप लाईन प्रोजेक्ट, न्यू हाउस, कुन्जपुरा मार्ग, करनाल (हरियाणा) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यावसायी की मार्फत।

अनुसूची

तहसील करनाल	जिला करनाल	राज्य हरियाणा		
नाम ग्राम	खसरा नं	क्षेत्रफल		
		हे	ऐ०	वर्ग मी०
1	2	3	4	5
बरोटा ह०न०51	621 मिन	0	00	00
	624 मिन	0	10	62
	661 मिन	0	07	08
	1238 मिन	0	00	51

[क्रमांक 12020/7/82-प्रो०]

S.O. 2640.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum products from Mathura in Uttar Pradesh to Jullundur in Punjab pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Mathura-Jullundur Pipeline New House, Kunjpura Road, Karnal (Haryana).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Tehsil : Karnal	District : Karnal	State : Haryan		
Name of village	Khasra No.	H.	A.	Sq.M.
1	2	3	4	5
BAROTA H. NO. 51 .	621 Min.	0	00	00
	624 Min.	0	10	62
	661 Min.	0	07	08
	1238 Min.	0	00	51

[No. 12020/7/82—Prod.]

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 26 जून, 82

का० आ० 2641.—पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमिका में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के अनुसरण भारत सरकार, पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना का० आ० सं० 755 संख्या 12020/3/82-प्रो० दिनांक 12-2-1982 की संलग्न अनुसूची में भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3 उपखंड (ii) दिनांक 27-2-82 में प्रकाशित तहसील फिल्लौर जिला जालन्धर राज्य पंजाब के लिए।

	के स्थान पर				पढ़ें			
नाम ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल			खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		हे०	ए०	वर्गमी०		हे०	ए०	वर्गमी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
खाडीयां ह० नं० 209	272/2 मिन	00	11	13	272/2 मिन	00	11	89
	273 ,,	00	09	87	273 ,,	00	10	38
	274 ,,	00	07	08	274 ,,	00	07	33
	276 ,,	00	12	14	276 ,,	00	17	71
कौटली खाड़ीयां								
ह० नं० 199	555 ,,	00	01	01	555 ,,	00	00	76
	611 ,,	00	12	40	614 ,,	00	11	89
	644 ,,	00	00	76	644 ,,	00	00	51

[सं० 12020/3/82 प्रो०

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th June, 1982

S. O. 2641.—In the schedule appended to the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Petroleum) S.O. No. 755 (No. 12020/3/82-Prod.) dated 12-2-1982 issued under sub-section (i) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Act 1962 (50 of 1962) published at pages 866-69 dated the 27-2-82 of the Gazette of India, Part II Section 3, Sub-section (i) for Tehsil: Phillaur, District: Jullundur, State of Punjab.

FOR					READ			
Name of village	Khasra No.	H.	A.	Sq.M	Khasra No.	H.	A.	Sq M
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LADIAN H.No.209	272/2 Min	00	11	13	272/2 Min	00	11	89
	273 Min	00	09	87	273 Min	00	10	38
	274 Min	00	07	08	274 Min	00	07	33
	276 Min	00	12	14	276 Min	00	17	71
KOTLI KHAKHIAN H.No. 199	555 Min	00	01	01	555 Min	00	00	76
	614 Min	00	12	40	614 Min	00	11	89
	644 Min	00	00	75	644 Min	00	00	51

[No. 12020/3/82—Prod.]

शुद्धि-पत्र

का०आ० 2642.—भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3 उपखंड (ii) के पृष्ठ 3507 पर प्रकाशित भारत सरकार, पेट्रोलियम, रसायन, एवं उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) का०आ० सं० 2923 दिनांक 24-10-1981 (अधिसूचना नं० 12020/8/81-प्रो० दिनांक 6-10-81) पेट्रोलियम एवं खनिज पाईप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) बावत तहसील व जिला लुधियाना राज्य पंजाब के ग्राम बमा-कलां ह०नं० 205 पृष्ठ नं० 3504 लाईन नं० 29 के नीचे खसरा नं० 46/14, क्षेत्रफल, है० ऐ० वर्गमी०/00000 दर्ज होने से छूट गया है इस स्थान पर सन्निविष्ट हुआ पढ़ा जावे और पृष्ठ नं० 3507 ग्राम ढोलन वाला ह०नं० 34 की लाईन नं० 22, 23, 24 और 25 पर खसरा नम्बरान 22/1, 2, 3, 8 की जगह खसरा नम्बरान 23/1, 2, 3, 8 पढ़ा जावे।

[सं० 12020/8/81-प्रोड०]

ERRATA

S.O. 2642.—In the schedule appended to the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer (Department of Petroleum) S.O. No. 2923 dated 24th October, 1981 (Notification No. 12020/8/81-Prod. dated 6th October, 1981 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) published in the Gazette of India Part II, Section 3 of sub-section (ii) for Tehsil & District Ludhiana of Punjab State, in village Bhaman Kalan H. No. 205 at page 3508, Khasra Nos. 46/14 00H 00A 00 Sq. M. has been omitted, the same should be read as inserted and in village Dholanwal H. B No. 34 at page No. 3510 Col. II, line Nos. 8, 9, 10 & 11 instead of Khasra Nos. 22/1, 2, 3, & 8 the same should be read as Khasra Nos. 23/1, 2, 3/8.

[No. 12020/8/81-Prod.]

शुद्धि-पत्र

का० आ० 2643.—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के अन्तर्गत भारत सरकार पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय (पैट्रोलियम विभाग) द्वारा अधिसूचना का० आ० सं० 440 सख्या 12020/13/81-प्रो० दिनांक 15-1-82 की सलंग्न अनुसूचियों भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3 उपखंड (ii) दिनांक 6-2-1982 में पृष्ठ नं० 455-460 में प्रकाशित तहसील फगवाड़ा जिला कपुरथला राज्य पंजाब के लिए।

के स्थान पर					पढ़ें			
नाम ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल			खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		है०	ए०	वर्गमी०		है०	ए०	वर्गमी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
फगवाडा ईस्ट ह० नं० 73	1886 मिन	00	02	03	1886 मिन	00	01	86
नागलमजा ह० नं० 86	16/20 मिन	00	11	64	17/20 मिन	00	11	64
	21/2 मिन	00	00	51	21/2 मिन	00	00	51
	22 मिन	00	09	36	22 मिन	00	09	36
	23 मिन	00	04	05	23 मिन	00	04	05
	30/13/2 मिन	00	06	81	30/13/2 मिन	00	06	83
	219 मिन	00	01	52	219 मिन	00	01	01
	220 ——मिन 1 से 6	00	01	02	220 ——मिन 1 से 6	00	01	01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
माधापुर								
ह० नं० 81	1216 मिन	00	02	71	—	—	—	—
	1219 मिन	00	00	00	—	—	—	—
	1220 मिन	00	10	33	1220 मिन	00	02	20
	1221 मिन	00	02	88	1221 मिन	00	10	67
	1222 मिन	00	07	45	1222 मिन	00	00	51
	1223 मिन	00	00	31	—	—	—	—
	1226 मिन	00	01	69	—	—	—	—
	1227 मिन	00	09	39	1227 मिन	00	07	96
	1235 मिन	00	05	93	1235 मिन	00	05	25
	1236/2 मिन	00	01	58	1236/2 मिन	00	06	10
	1240 मिन	00	00	17	1240 मिन	00	03	22
	1241 मिन	00	08	63	1241 मिन	00	10	16
	1242 मिन	—	—	—	1242 मिन	00	00	85
	1257 मिन	—	—	—	1257 मिन	00	08	29
	1265 मिन	—	—	—	1265 मिन	00	07	28
	1266 मिन	00	07	96	1266 मिन	00	04	24
	1267 मिन	00	03	73	—	—	—	—
	1268 मिन	00	07	96	1268 मिन	00	05	76
	1269 मिन	—	—	—	1269 मिन	00	05	76
	1271 मिन	—	—	—	1271 मिन	00	04	24
	1273 मिन	00	05	59	—	—	—	—
	1274 मिन	00	06	27	1274 मिन	00	09	11
	1275 मिन	00	09	14	1275 मिन	00	01	02
	1283 मिन	00	01	58	—	—	—	—
	1337 मिन	00	00	00	—	—	—	—
	1348 मिन	00	07	62	1348 मिन	00	01	02
	1349 मिन	00	04	91	1349 मिन	00	09	48
	1349/1 मिन	00	09	65	1349/1 मिन	00	01	74
	1349/2 मिन	—	—	—	1349/2 मिन	00	04	74
	1350 मिन	—	—	—	1350 मिन	00	00	17
	1351 मिन	—	—	—	1351 मिन	00	01	35
	1354 मिन	00	01	21	1354 मिन	00	10	16
	1365 मिन	00	03	22	1365 मिन	00	08	16
	1366 मिन	00	08	63	1366 मिन	00	02	71
	1368 मिन	00	09	48	1368 मिन	00	05	08
	1369 मिन	00	02	51	1369 मिन	00	06	27
	1371 मिन	00	10	16	1371 मिन	00	07	11
	1372 मिन	00	01	69	1372 मिन	00	04	24
	1373 मिन	00	10	50	1373 मिन	00	09	31
	1374 मिन	00	00	17		—	—	—
	1383 मिन	00	00	34	1383 मिन	00	00	00
	1401 मिन	—	—	—	1401 मिन	00	02	54
	1544 मिन	00	00	51	1544 मिन	00	01	35
	1550 मिन	00	10	50	1550 मिन	00	10	67
	1551 मिन	00	00	51	1551 मिन	00	01	02
	1553 मिन	00	00	85	1553 मिन	00	00	51
	1556 मिन	00	08	68	1556 मिन	00	08	63
	1697 मिन	00	06	91		—	—	—
	1717 मिन	00	02	37	1717 मिन	00	02	71

[फा०स० 12020/13/82-प्र०]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th June, 1982

S. O. 2643—In the schedule appended to the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum, Chemicals Fertilizers (Department of Petroleum) S.O. No. 440 (No. 12020/13/81-Prod. dated 15-1-82 issued under sub-section (i) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 (50 of 1962) published at page 460-464 dated 6-2-82 of the Gazette of India Part II—Section 3, sub-section (ii) for Tehsil Phagwara District Kapurthala State of Punjab.

	FOR				READ			
Name of Village	Khasra No.	H.	A.	Sq.M.	Khasra No.	H.	A.	Sq.M
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PHAGWARA EAST H. No. 73	1886 Min	00	02	03	1886 Min	00	01	06
NANGALMAJJA H.No. 86.	16/20 Min	00	11	64	17/20 Min	00	11	64
	21/2 Min	00	00	51	21/2 Min	00	00	51
	22 Min	00	09	36	22 Min	00	09	36
	23 Min	00	04	05	23 Min	00	04	05
	30/13/2 Min	00	06	81	30/13/2 Min	00	06	83
	219 Min	00	01	52	219 Min	00	01	01
	220 Min	00	01	02	220 Min	00	01	01
	—				—			
	1 to 6				1 to 6			
MADHOPUR H.No. 81	1216 Min	00	02	71	—	—	—	—
	1219 Min	00	00	00	—	—	—	—
	1220 Min	00	10	33	1220 Min	00	02	20
	1221 Min	00	02	88	1221 Min	00	10	67
	1222 Min	00	07	45	1222 Min	00	00	51
	1223 Min	00	00	34	—	—	—	—
	1226 Min	00	01	69	—	—	—	—
	1227 Min	00	09	99	1227 Min	00	07	76
	1235 Min	00	05	93	1235 Min	00	05	25
	1236/2 Min	00	04	58	1236/2 Min	00	06	10
	1240 Min	00	00	17	1240 Min	00	03	22
	1241 Min	00	08	63	1241 Min	00	10	16
	1242 Min	—	—	—	1242 Min	00	00	85
	1257 Min	—	—		1257 Min	00	08	29
	1265 Min	—	—	—	1265 Min	00	07	28
	1266 Min	00	07	96	1266 Min	00	04	24
	1267 Min	00	03	73	—	—	—	—
	1268 Min	00	07	96	1268 Min	00	05	76
	1269 Min	—	—	—	1269 Min	00	05	76
	1271 Min	—	—	—	1271 Min	00	04	24
	1273 Min	00	05	59	—	—	—	—
	1274 Min	00	06	27	1274 Min	00	09	14
	1275 Min	00	09	14	1275 Min	00	01	02
	1283 Min	00	04	58	—	—	—	—
	1337 Min	00	00	00	—	—	—	—
	1348 Min	00	07	62	1348 Min	00	01	02
	1349 Min	00	04	71	1349 Min	00	09	48
	1349/1 Min	00	09	65	1349/1 Min	00	04	74
	1349/2 Min	—	—	—	1349/2 Min	00	04	74
	1350 Min	—	—	—	1350 Min	00	00	17
	1351 Min	—	—	—	1351 Min	00	01	35
	1354 Min	00	04	24	1354 Min	00	10	16
	1365 Min	00	03	22	1365 Min	00	08	46
	1366 Min	00	08	63	1366 Min	00	02	71
	1368 Min	00	09	48	1368 Min	00	05	08
	1369 Min	00	02	54	1369 Min	00	06	27
	1371 Min	00	10	16	1371 Min	00	07	11
	1372 Min	00	01	69	1372 Min	00	04	24
	1373 Min	00	10	50	1373 Min	00	09	31
	1374 Min	00	00	17	—	—	—	—
	1383 Min	00	00	34	1383 Min	00	00	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Madhopur H. No. 81—(Contd.)	1401 Min	—	—	—	1401 Min	00	02	54
	1544 Min	00	00	51	1544 Min	00	01	35
	1550 Min	00	10	50	1550 Min	00	10	67
	1551 Min	00	00	51	1551 Min	00	01	02
	1553 Min	00	00	85	1553 Min	00	00	51
	1556 Min	00	08	68	1556 Min	00	08	63
	1697 Min	00	06	79		—	—	—
	1717 Min	00	02	37	1717 Min	00	02	71

[No. 12020/13/81—Prod]

नई दिल्ली, 5 जुलाई 1982

का० आ० 2644—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ०सं० 85 दिनांक 9-1-82 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है।

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय इंडियन ऑयल कार्पोरेशन में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

तहसील : समराला जिला . लुधियाना, राज्य . पंजाब

ग्राम का नाम	खसरा नं०		क्षेत्रफल हे०	मै०	वर्गमी०
1	2		3	4	5
गढ़ी सरखाना	13/2	मिन	00	01	77
ह० नं० 79	8	"	00	03	54
	9/1	"	00	07	84
	9/2	"	00	04	55
	13/1	"	00	01	77
	13/2	"	00	09	11
	14/1	"	00	04	30
	14/2	"	00	01	01
	16/1	"	00	03	54
	16/2	"	00	01	05
	17	"	00	08	10
	25	"	00	06	58
गढ़ी सरखाना	14/2/1	मिन	00	00	00
ह०नं० 79—जारी	21/2	"	00	08	85
	23/21/1	"	00	01	77
	21/3	"	00	00	51
	21/4	"	00	01	01
	22/2	"	00	02	28
	24/1	"	00	05	82
	2/3	"	00	10	12
	8	"	00	11	64
	9/1	"	00	02	02
	9/2	"	00	01	77
	24/13/1	"	00	02	53
	13/2	"	00	00	25
	14/1	"	00	13	66
	14/2	"	00	00	00
	15/1	"	00	00	25
	16/1	"	00	11	64
	16/3	"	00	01	26
	32/1	"	00	00	00
	2	"	00	12	40
	3/1	"	00	05	57
	33/19	"	00	10	37
	115/	"	00	02	02
	117/	"	00	02	02
	120/	"	00	00	76
	121/	"	00	01	77
	122/	"	00	03	29
	378/	"	00	01	01
	380/	"	00	01	01

[सं० 12020/10/81-प्रो०]

New Delhi, the 5th July, 1982

S.O. 2644.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizer (Department of Petroleum) S.O. 85 dated 9-1-82 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government.

And further the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-

section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines.

And further in exercise of the power conferred by Sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil -Samrala Distt—Ludhiana State—Punjab.

Name of Village Garhi Tarkhana (Part route of the pipeline across Sirhind Canal)

Name of Village	Khasra No.	Area H	Area A	Area Sq. M
1	2	3	4	5
Garhi Tarkhana	13/2 Min	00	01	77
H.B. No. 79	8 Min	00	03	54
	9/1 Min	00	07	84
	9/2 Min	00	04	55
	13/1 Min	00	01	77
	13/2 Min	00	01	11
	14/1 Min	00	04	30
	14/2 Min	00	01	01
	16/1 Min	00	03	54
	16/2 Min	00	04	05
	17 Min	00	08	10
	25 Min	00	06	58
	14/21/1 Min	00	00	00
	21/2 Min	00	08	85
	23/21/1 Min	00	01	77
	21/2 Min	00	00	51
	21/4 Min	00	01	01
	22/2 Min	00	02	28
	24/1 Min	00	05	82
	2/2 Min	00	10	12
	8 Min	00	11	64
	9/1 Min	00	02	02
	9/2 Min	00	01	77
Garhi Trkhana	24/13/1 Min	00	02	53
H.B. No. 79	13/2 Min	00	00	25
	14/1 Min	00	13	66
	14/2 Min	00	00	00
	15/1 Min	00	00	25
	161 Min	00	11	64
	16/3 Min	00	01	26
	32/1 Min	00	00	0)
	2 Min	00	12	40
	3/1 Min	00	05	57
	33/19 Min	00	10	37
	115/ Min	00	02	02
	117 Min	00	02	02
	120 Min	00	00	76
	121 Min	00	01	77
	122 Min	00	03	29
	378 Min	00	01	01
	380 Min	00	01	01

[No. 12020/10/81-Prod.]

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 5 जुलाई 1982

का०आ० 2645.—भारत के राजपत्र के भाग-II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) के पृष्ठ 1040 पर प्रकाशित भारत सरकार, पेट्रोलियम रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) के एस०ओ०नं० 952 दिनांक 6-3-1982 (अधिसूचना न० 12020/1/82 प्रो०डि० दिनांक 12-2-82 पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा (3) की उपधारा (1) बाबत तहसील और जिला लुधियाना राज्य पंजाब के ग्राम सलेमपुर ह०न० 33 के लाइन 5 के नीचे खसरा न० 8/17 क्षेत्रफल 00 01 01 दर्ज होने से छूट गया है। इसको इस स्थान पर सन्निविष्ट किया हुआ पढ़ा जाए।

ह० आर० वर्मा०

[फाइल न० 12020/1/82-प्रोड०]

एल० एम० गोयल, निदेशक

CORRIGENDUM

New Delhi the 5th July, 1982

S.O. 2645.—In the schedule appended to the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum, Chemical and Fertilizers (Department of Petroleum) S.O. No. 952 dated 6-3-1982 Notification No. 12012/82, Prod. dated 12-2-1982 issued under Sub-section (i) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Act 1962 (50 of 1962) published in the Gazette of India Part II, Section 3 of Sub section (ii) for Tehsil and District Ludhiana of Punjab State, at page 1040 in village Salampur H. No. 33 below line 5, Khasra No. 8/17, 00.01 01 has been omitted, the same should be read as inserted.

[F. No. 12020/1/82-Prod.]

L. M. GOYAL, Director

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, 30 जून, 1982

का० आ० 2646 — भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 8 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के अनुबन्ध केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के कर्मचारियों के लाभ के लिए स्थापित भविष्य निधि पर लागू होंगे।

[सं० 1/82-एफ०11(31)/80-यू० एस० डी०-7(2)/टी एण्ड आर]

जरनैल सिंह, अवर सचिव,

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Power)

New Delhi, the 30th June, 1982

S.O. 2646.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Provident Fund Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Provident Fund established for the benefit of the employees of the Central Power Research Institute, Bangalore.

[No. 1|82-F. 11(31)/80-USD. VII(2)/T&R]

JARNAIL SINGH, Under Secy.

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जून, 1982

का० आ० 2647:—केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति खली (पैरी गई या विलायक निस्तारित) श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम 1979 में कतिपय संशोधन करना चाहत है। जैसा कि उक्त धारा मे अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि के पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट 45 दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व नियमो के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. (1) नियमो का संक्षिप्त नाम वनस्पति खली (पैरी गई या विलायक निस्तारित) श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वनस्पति खली (पैरी गई या विलायक निस्तारित) श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम 1979 के नियम 8 के खंड (ii) में परिसर साफ एवं स्वास्थ्यकर होने चाहिए और उन्हें कालिक रूप में धूमित किया जाना चाहिए। शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख जाएंगे, अर्थात् :—

"परिसर साफ एवं स्वास्थ्यकर होने चाहिए और उनका तीन सप्ताह से अनधिक के अन्तराल पर निरोधोपचार किया जाना चाहिए।

जब कभी स्टाफ को कीटाणु ग्रस्त देखा जाए उसको धूमित किया जाना चाहिए।"

[सं० फा० 13-8/76-एम० ए०]

MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION

New Delhi, the 30th June, 1982

S.O. 2647.—The following draft of certain rules to amend the Vegetable Oil Cakes (Expressed or Solvent Extracted) Grading and Marking Rules, 1979, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), is hereby published, as required by the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period of forty-five days so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Vegetable Oil Cakes (Expressed or Solvent Extracted) Grading and Marking (Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force.....

2. In the Vegetable Oil Cakes (Expressed or Solvent Extracted) Grading and Marking Rules, 1979, in rule 8, in clause (ii), for the words "The premises should be clean and hygienic and should be periodically fumigated", the following words shall be substituted, namely :—

"The premises should be clean and hygienic and should be subjected to prophylactic treatment at an interval of not more than three weeks. The stock should also be fumigated as and when any insect infestation is noticed."

[No. F. 13-8/76-AM]

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1982

का० आ० 2648.—महुआ बीज श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1981 का एक प्रारूप कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1578 तारीख 7 मई, 1981 के साथ भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) तारीख 23 मई, 1981 के पृष्ठ 1653 से 1657 पर प्रकाशित किया गया था जिसमे उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 8 जून, 1981 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों/सुझावो पर विचार कर लिया है।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ.

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महुआ बीज श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1981 है।

(2) ये भारत में उत्पादित महुआ बीज को लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

इन नियमो में, जब तक संदर्भ मे अन्यथा अपेक्षित न हो :

(1) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है,

(2) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है;

(3) "प्राधिकृत पैकर" से ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति निकाय अभिप्रेत है जिसे कृषि विपणन सलाहकार ने नियमों के अधीन विहित श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार वस्तु को श्रेणीकृत कराने और एगमार्क चिह्न लगवाने के लिए प्राधिकृत प्रमाणपत्र दिया है;

(4) "प्रमाणपत्र" से प्राधिकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है।

3. श्रेणी अभिधान :

महुआ बीजों की क्वालिटी उपदर्शित करने वाला, श्रेणी अभिधान वह होगा जो अनुसूची 1 के स्तम्भ 1 में उपवर्णित है।

4. क्वालिटी की परिभाषा :

श्रेणी अभिधानों द्वारा उपदर्शित क्वालिटी वह होगी जो अनुसूची 1 के स्तम्भ 2 से 7 में, प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने उपवर्णित है।

5. श्रेणी अभिधान चिह्न

श्रेणी अभिधान चिह्न एक ऐसा लेबल होगा जिसमें श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट होगा और ऐसा डिजाईन बना होगा जिस पर अनुसूची 11 में उपवर्णित चिह्न के सदृश, भारत के मानचित्र की रूपरेखा जिसमें "एगमार्क" शब्द होगा और "भारतीय उत्पाद" तथा "Product of India" शब्द और उदय होता सूर्य का चित्र अंकित होगा।

6. चिह्नांकन पद्धति :

(1) श्रेणी अभिधान चिह्न, कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति से, प्रत्येक पैकेज पर मजबूती से चिपकाया जाएगा।

(2) श्रेणी अभिधान के अतिरिक्त लेबल पर निम्नलिखित विशिष्टियाँ भी स्पष्टतः दी जाएगी :

(क) पैक करने की तारीख

(ख) लाट संख्याक

(3) प्रत्येक आधान पर अमिट स्याही से निम्नलिखित विशिष्टियां अंकित होंगी।

(क) लाट संख्याक

(ख) पैकर का नाम और पता;

(ग) शुद्ध भार ; और

(घ) कोई अन्य विशिष्टियां जो कृषि विपणन सलाहकार समय समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(4) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् आधान पर अपना प्राईवेट व्यापार चिह्न उक्त अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से तब अंकित कर सकेगा जब प्राईवेट व्यापार चिह्न इन नियमों के अनुसार आधान पर चिपकाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित महुआ बीज की क्वालिटी या श्रेणी से भिन्न क्वालिटी या श्रेणी उपदर्शित न करे।

7. पैक करने की पद्धति :

(1) महुआ बीज के मजबूत जूट के थैलों में या किसी अन्य प्रकार के तथा ऐसी क्षमता वाले आधान में और ऐसी रीति में पैक किया जाएगा जो कृषि विपणन सलाहकार समय समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(2) पैकिंग सामग्री स्वच्छ और शुष्क होगी, फफूंदी या कीड़े लगी नहीं होगी और दुर्गन्ध मुक्त होगी।

(3) हर एक पैकेज में केवल एक ही श्रेणी अभिधान के महुआ बीज होंगी।

(4) प्रत्येक पैकेज को विहित ऐसी रीति से सुरक्षित रूप से बंद और सीलबंद किया जाएगा जो कृषि विपणन सलाहकार विहित करे।

स्लिप "क"

महुआ बीज :

(i) सेपोटेसिया परिवार के मधुका इंडिका जे० एफ० ग्मोलिन, साइन, मधुका लैटिफोलिया (आर ओ एक्स बी) मेकब्राईड या मधुका लोंगीफोलिया (कोइंग) मेकब्राईड, वृक्ष पर लगने वाले फल के निर्वल्कन से अभिप्राप्त को लिलिहा होगा।

(ii) स्वास्थ्यवर्धक होगा, फफूंदा, धुन दुर्गन्ध, हानिकारक पदार्थ से और अनुसूची में उपदर्शित सीमा तक के सिवाय सभी अन्य अपद्रव्यों से मुक्त होगा।

(iii) समान रूप, आकार और रंग का होगा।

अनुसूची -1

(नियम 3 और 4 देखिए)

भारत में उत्पादित महुआ बीज के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा।

श्रेणी अभिधान	रंग	क्वालिटी की परिभाषा				
		विजातीय पदार्थ, भारत के आधार पर प्रतिशत (अधिकतम)	विशेष लक्षण			साधारण लक्षण
			क्षतिग्रस्त, किंचित क्षतिग्रस्त और घुन खाए बीज, भार के अनुसार प्रतिशत (अधिकतम)	टूटे हुए और खंडित, भार के अनुसार, प्रतिशत (अधिकतम)	नमी, भार के अनुसार प्रतिशत अधिकतम	
1	2	3	4	5	6	7
I.	रक्ताभ पीला या भूरा पीला या हल्का भूरा	2·0	4·0	20	6·0	देखिए स्लिप "क"
II.	गहरा भूरा	4·0	10·0	6·0	6·0	
III.	गहरा भूरा	6·0	15·0	10·0	6·0	

मिश्रण "ख"

परिभाषाएं :

विजातीय पदार्थ : इसके अन्तर्गत धूल, कंकड़, मिट्टी की पिण्डियां, पत्तियां और कोई अन्य खाद्य या अखाद्य बीज भी हैं।

क्षतिग्रस्त बीज: ऐसे बीज होंगे जो यांत्रिक रूप से या फफूंदी द्वारा क्षतिग्रस्त हो गये हैं या जो बीजों का आन्तरिक विवर्णन दर्शित करते हैं जिससे क्वालिटी पर तात्विक रूप से प्रभाव पड़ता हो।

किंचित क्षतिग्रस्त बीज : ऐसे बीज होंगे जो मामूली रूप से क्षतिग्रस्त या विवर्णित हैं और उस क्षति या विवर्णन से क्वालिटी पर तात्विक रूप से प्रभाव नहीं पड़ता है।

घुने बीज : ऐसे बीज होंगे जिनमें घुन या अन्य कीटाणुओं द्वारा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से छेद कर दिया गया है या जिन्हें खा लिया गया है।

टूटे हुए बीज : इनके अन्तर्गत ऐसे बीज होंगे जो पूर्ण बीज के तीन चौथाई भाग से कम हैं।

खण्डित बीज : इनके अन्तर्गत ऐसे बीज होंगे जो पूर्ण बीज के एक चौथाई भाग से कम है।

अनुसूची 2

(नियम 5 देखिए)

श्रेणी अभिधान चिह्न

[सं० 10-780-/ए० एम०]

New Delhi, the 1st July, 1982

S.O. 2648.—Whereas a draft of the Mahua Seed Grading and Marking Rules, 1981 was published as required by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) at pages 1653 to 1657 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 23rd May, 1981 with the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Reconstruction No. S.O. 1578 dated the 7th May, 1981 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 8th June, 1981;

And whereas objections/suggestions received from the public in respect of the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :

RULES

1. Short title, application and commencement.—(i) These rules may be called the Mahua Seed Grading and Marking Rules, 1982.

(ii) They shall apply to the Mahua Seed produced in India.

(iii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(i) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(ii) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

(iii) "Authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a Certificate of Authorisation by the Agricultural Marketing Adviser for getting the commodity graded and agmarked in accordance with the grade standards and procedure prescribed under the rules;

(iv) "Certificate" means Certificate of Authorisation.

3. Grade designation.—The grade designations to indicate the quality of Mahua Seed shall be as set out in column 1 of Schedule I.

4. Definition of quality.—The quality indicated by the grade designations shall be as set out against each grade designation in columns 2 to 7 of Schedule I.

5. Grade designation mark.—The grade designation mark shall consist of a label specifying the grade designation and bearing a design consisting of outline map of India with the word "AGMARK" and figure of the rising sun with the words "Produce of India" and 'भारत का उत्पाद" resembling the mark as set out in Schedule II.

6. Method of marking.—(1) The grade designation mark shall be securely affixed to each package in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser.

(2) In addition to the grade designation, the following particulars shall also be clearly marked on the label :

(a) Date of packing;

(b) Lot number;

(3) Each container shall have indelibly marked on it the following details :

(a) Lot number;

(b) Name and address of packer;

(c) Net weight; and

(d) Any other particulars as may be specified by the Agricultural Marketing Adviser from time to time.

(4) The authorised packer may, after obtaining the prior approval of the Agricultural Marketing Adviser, mark his private trade mark on a container in a manner approved by the said officer, provided that the private trade mark does not represent a quality or grade of Mahua seed different from that indicated by the grade designation mark affixed to the container in accordance with these rules.

7. Method of packing.—(1) Mahua seed shall be packed in sound jute bag or any other type of container and of capacity and in such manner as may be specified from time to time by the Agricultural Marketing Adviser.

(2) Packing material shall be clean and dry, free from funds and insect attack and obnoxious smell.

(3) Each package shall contain Mahua seed of one grade designation only.

(4) Each package shall be securely closed and sealed in the manner prescribed by the Agricultural Marketing Adviser.

SCHEDULE I

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definitions of quality of Mahua seed produced in India

Grade designation	Definition of quality					
	Special characteristics					
	Colour	Foreign matter, percentage by weight (Maximum)	Damaged, slightly damaged and weevilled seeds, per cent by weight (Maximum)	Broken and fragments per cent by weight (Maximum)	Moisture, per cent by weight (Maximum)	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7
I.	Reddish yellow or yellowish brown or light brown	2.0	4.0	2.0	6.0	Mahua seed shall be : (1) the cotyledons obtained after decorticating the seeds from the fruit borne on the tree *Madhuca indica* J.F.

1	2	3	4	5	6	7
II.	Dark Brown	4.0	10.0	6.0	6.0	Gmolin, Syn., Madhuca latifolia (Roxb) Macbride or Madhuca longifolia (kooing) Macbride, belonging to the family Sapotaceae.
III.	Dark Brown	6.0	15.0	10.0	6.0	(2) wholesome, free from moulds, weevils, obnoxious smell, deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the schedule.
						(3) have uniform shape, size and colour.

Definitions :

Foreign matter : shall include dust, stones, lumps of earth, leaves, any other edible or non-edible seeds.

Damaged seeds : shall be the seeds which are damaged mechanically or by mould or those showing internal discolouration of seeds materially affecting the quality.

Slightly damaged seeds : shall be the seeds that are superficially damaged or discoloured, damaged and discolouration not materially affecting the quality

Weevilled seeds : shall be those seeds which are partially or wholly bored or eaten by weevils or other insects

Broken : shall include those seeds which are less than three-fourth but more than one-fourth of a whole seed.

Fragments : shall include those seed which are less than one-fourth of a whole seed.

SCHEDULE II

(See rule 5)

Grade designation mark

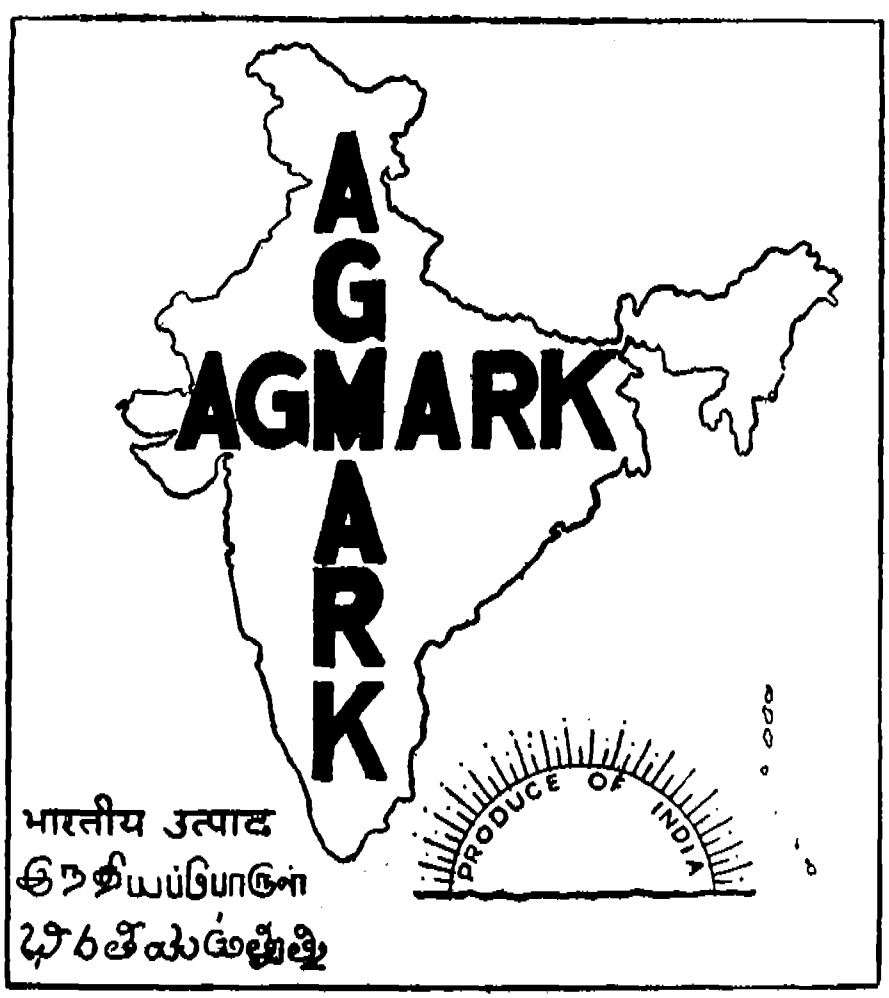

[No. 10-7/80—AM]

का०आ० 2649.—कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1952 तारीख 11 जून, 1981 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 18 जुलाई, 1981 के पृष्ठ 2176 से 2178 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 12 अगस्त, 1981 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और केन्द्रीय सरकार को जनता से उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

नियम

1 संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम साल बीज श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम 1982 है ।

(2) ये भारत में उत्पादित साल बीज (बीज और गिरी) को लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(1) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है ;

(2) "अनुसूची" से इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(3) "प्राधिकृत पैकर" से ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति निकाय अभिप्रेत है जिसे कृषि विपणन सलाहकार ने इन नियमों के अधीन विहित मानकों और प्रक्रिया के अनुसार वस्तु की श्रेणीकृत कराने और एगमार्क से चिन्हित कराने के लिए प्राधिकरण प्रमाणपत्र दिया है ।

(4) प्रमाणपत्र" से प्राधिकरण प्रमाणपत्र अपेक्षित है ;

3 श्रेणी अभिधान साल बीज और गिरी की क्वालिटी उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान वह होगा जो अनुसूची I और II के स्तम्भ 1 में यथा उपवर्णित है ।

4 क्वालिटी की परिभाषा—श्रेणी अभिधानों द्वारा उपदर्शित क्वालिटी वह होगी, जो अनुसूची 1 के स्तम्भ 2 से 7 में और अनुसूची 2 के स्तम्भ 2 से 6 में प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने यथा उपदर्शित है ।

5. श्रेणी अभिधान चिन्ह : श्रेणी अभिधान चिन्ह एक ऐसा लेबल होगा जिस पर श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट होगा और उस पर ऐसा डिजाइन बना होगा ; जिसमें भारत की रूपरेखा का मानचित्र एगमार्क शब्द और "Produce of India" तथा "भारतीय उत्पाद" शब्दों सहित उदय होते हुए सूर्य का चित्र होगा, जो अनुसूची 3 में उपवर्णित चिन्ह के सदृश होगा ।

6 चिन्हांकन पद्धति : (1) श्रेणी अभिधान चिन्ह, कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति से प्रत्येक पैकेज पर मजबूती से चिपकाया जाएगा।

(2) श्रेणी अभिधान के अतिरिक्त लेबल पर निम्नलिखित परिविष्टियां भी स्पष्टतः चिन्हित की जाएंगी—

(क) पकर का नाम,

(ख) शुद्ध भार

(ग) पक करने की तारीख तथा स्थान, और

(घ) कोई अन्य विशिष्टियां जो कृषि विपणन सलाहकार समय समय पर विनिर्दिष्ट करें।

(3) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् किसी आधान पर अपना निजी व्यापार चिन्ह उक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से तब अंकित कर सकेगा जब कि निजी व्यापार चिन्ह इन नियमों के अनुसार आधार पर चिपकाए गए श्रेणी अभिधान चिन्ह द्वारा साल बीजों की उपदर्शित क्वालिटी या श्रेणी से भिन्न क्वालिटी या श्रेणी उपदर्शित नहीं करता है ।

7. पैक करने की पद्धति (1) साल बीज और गिरी जूट के बोरे में या ऐसे अन्य प्रकार के और ऐसी धारिताओं वाले पैकेजों में और ऐसी रीति में पैक किए जाएंगे, जो कृषि विपणन सलाहकार अनुमोदित करें।

(2) पैकिंग सामग्री, स्वच्छ शुष्क और फफूंदी कीट ग्रसन तथा दुर्गन्ध से मुक्त होगी ;

(3) प्रत्येक पैकेज में केवल एक ही श्रेणी अभिधान के साल बीज और गिरी होंगे।

(4) प्रत्येक पकेज कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विहित रीति से बंधा करके मुहर बन्द किया जाएगा।

अनुसूची I

(नियम 3 और 4 देखिए)

साल बीज (शोरिया रोबस्टा) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा — विशेष लक्षण: विजातीय पदार्थ भार के अनुसार प्रतिशत (अधिकतम)	अपरिपक्व और झुर्रीदार बीज भार के अनुसार प्रतिशत (अधिकतम)	क्षतिग्रस्त और घुन खाए बीज भार के अनुसार (अधिकतम)	विभक्त और टूटे हुए बीज भार के अनुसार प्रतिशत (अधिकतम)	आर्द्रता भार के अनुसार प्रतिशत (अधिकतम)	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.0	1.0	0.5	10.0	10.0	साल बीज :
2.	3.0	2.0	1.0	15.0	10.0	(1) शोरिया रोबस्टा गाइर्टन परिवार डिप्टेरो-

1	2	3	4	5	6	7
3	4.0	4.0	2.0	25.0	10.0	रोकापेसी के सुखाए गए पके बीज होंगे । (2) स्वास्थ्यप्रद होंगे, फफूंदी, घुन, दुर्गन्ध, हानिकर पदार्थों और अन्य सभी अशुद्धताओं से सिवाय उस सीमा तक जो अनुसूची में उपवर्णित है, मुक्त होंगे । (3) आकार, रूप और रंग में एक समान होंगे ।

परिभाषा – विजातीय पदार्थ : इसके अन्तर्गत धूल, कंकड़, मिट्टी के पिंड, पत्तियां और अन्य खाद्य और अखाद्य बीज भी होंगे। अपरिपक्व और झुर्रीदार बीज : ऐसे बीज होंगे जो समुचित रूप से विकसित नहीं है और/या सिकुड़े हुए है।

क्षतिग्रस्त और घुन खाए बीज : ऐसे बीज होंगे जो यांत्रिक रूप से या फफूंदी के कारण क्षतिग्रस्त हो गए है या जो आन्तरिक रूप से इस प्रकार वर्णित हो गए है जिससे क्वालिटी पर सारतः प्रभाव पड़ता है । घुन खाए बीज वे बीज होंगे जिनमें अंशतः या पूर्णतः घुन या अन्य कीड़ों द्वारा छेद कर दिए गए है या खा लिया गया है । विभक्त और टूटे हुए बीज : विभक्त बीज वे होंगे जो लम्बाई से दो भागों में विभक्त है । टूटे हुए बीज वे बीज होंगे जो विभक्त बीज से छोटे है ।

अनुसूची 2

(नियम 3 और 4 देखिए)

साल की गिरियों के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी	क्वालिटी की परिभाषा				साधारण लक्षण
	विशेष लक्षण				
	विजातीय पदार्थ भार के अनुसार प्रतिशत (अधिकतम)	अपरिपक्व झुर्रीदार गिरियां भार के अनुसार प्रतिशत (अधिकतम)	क्षतिग्रस्त घुन खाई गिरियां भार के अनुसार प्रतिशत (अधिकतम)	आर्द्रता भार के अनुसार प्रतिशत (अधिकतम)	
1	2	3	4	5	6
1	0.5	2 0	1 0	7.0	साल की गिरियां
2	1.0	4.0	2.0	7 0	(1) शोरिया रोबस्टा गार्ईर्टन परिवार डिप्टेरोकार्पेसी के सुखाए गए पके बीज से प्राप्त गिरियां होंगी । (2) युक्तियुक्त रूप से सुखाई गई, स्वास्थ्यप्रद घुन, दुर्गन्ध, हानिकर पदार्थों और अन्य सभी अशुद्धताओं से, सिवाय उस सीमा तक जो अनुसूची में उपवर्णित है, मुक्त होंगी । (3) आकार, रूप और रंग में एक समान होंगी।

परिभाषा :—विजातीय पदार्थ : इसके अन्तर्गत धूल, कंकड़, मिट्टी के पिण्ड, पत्तियां, बीज के छिलके कोई अन्य खाद्य या अखाद्य बीज गिरियां होंगी अपरिपक्व और झुर्रीदार वे गिरियां होंगी जो उचित रूप से विकसित नहीं है और या सिकुड़ी हुई है ।

क्षतिग्रस्त घुन खाई गिरियां—वे है जो यांत्रिक रूप से या फफूंदी/कीड़ों के कारण क्षतिग्रस्त है या जो आन्तरिक रूप से इस प्रकार विवर्णित हो गई हैं जिससे क्वालिटी पर सारतः प्रभाव पड़ता है, घुन खाई गिरियां वे होंगी जिनमें अंशतः या पूर्णतः घुन या अन्य कीड़ों द्वारा छेद कर दिये गये है या खा ली गई हैं।

अनुसूची 3

(नियम 5 देखिए)

श्रेणी अभिधान चिन्ह

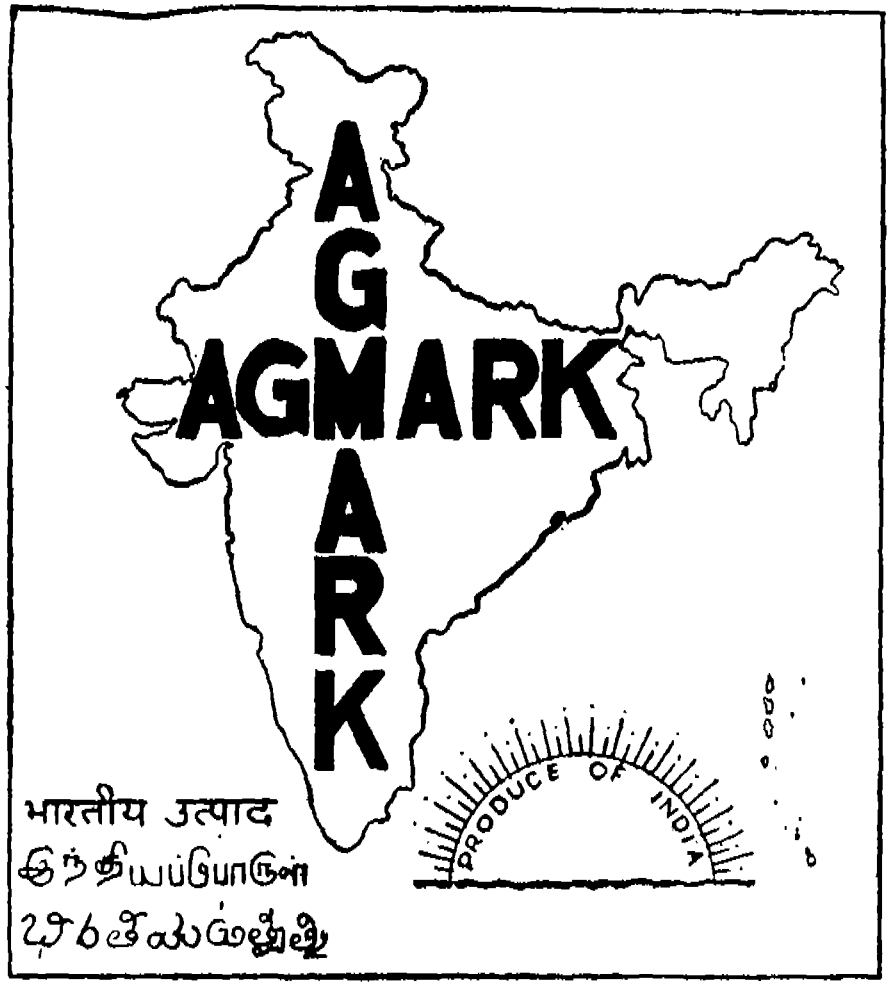

[फा० सं० 10-8/80-ए०एम०]

S.O. 2649.—Whereas a draft of the Sal seed Grading and Marking Rules, 1981 was published as required by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) at pages 2176 to 2180 of the Gazette of India, Part II Section 3, Sub-section (ii), dated the 18th July, 1981 with the notification of the Government of India, in the Ministry of Rural Reconstruction No. S.O. 1952 dated the 11th June, 1981 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of forty five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette.

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 12th August, 1981;

And whereas no objections or suggestions have been received from the public in respect of the said draft by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

RULES

1. Short title, application and commencement.—(1) These rules may be called the Sal seed Grading and Marking Rules, 1982;

(2) They shall apply to Sal Seed (Seed and Kernel) produced in India;

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(1) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(2) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(3) "Authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorisation by the Agricultural Marketing Adviser for getting the commodity graded and marked in accordance with the grade standards and procedure prescribed under the rules;

(2) "Certificate" means Certificate of Authorisation.

3. Grade designations.—The Grade designation to indicate the quality of the Sal Seed and Kernel shall be set out in column 1 of Schedules I and II.

4. Definition of quality.—The quality indicated by the grade designation shall be as set out against each grade designation in Columns 2 to 7 of Schedule I and columns 2 to 6 of Schedule II.

5. Grade Designation Mark.—The grade designation mark shall consist of a label specifying the grade designation and bearing a design consisting of outline map of India, with the word AGMARK and figure of the rising sun with the words "Produced of India" and resembling the mark as set out in Schedule III.

6. Method of marking.—(1) The grade designation mark shall be securely affixed to each package in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser.

(2) In addition to the grade designation, the following particulars shall also be clearly marked on the label—

(a) Name of the packer;
(b) net weight;
(c) date and place of packing; and
(d) any other particulars as may be specified by the Agricultural Marketing Adviser from time to time.

(3) The authorised packer may, after obtaining the prior approval of the Agricultural Marketing Adviser, mark his private trade mark on a container in manner approved by the said officer, provided that the private trade mark does not represent a quality or grade of Sal Seed different from that indicated by the grade designation mark affixed to the container in accordance with these rules.

7. Method of packing.—(1) Sal seed and Kernels shall be packed in Jute bags or in such other type of packages and of capacities and in such a manner as may be approved by the Agricultural Marketing Adviser.

(2) Packing material shall be clean, dry, free from fungus and insect attack and obnoxious smell.

(3) Each package shall contain Sal Seed or Kernels of the same grade designation only.

(4) Each package shall be securely closed and sealed in the manner prescribed by the Agricultural Marketing Adviser.

SCHEDULE I

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definitions of the quality of Sal Seed (Shorea robusta)

Grade Designation	Definition of quality					General characteristics
	Special characteristics					
	Foreign matter, per cent by weight (Maximum)	Immature and shrivelled seed, per cent by weight (Maximum)	Damaged and weevilled seed, per cent by weight (Maximum)	Split and broken seed per cent by weight (Maximum)	Moisture, per cent by weight (Maximum)	
1	2	3	4	5	6	7
I	1.0	1.0	0.5	10.0	10.0	Sal seed shall :
II	3.0	2.0	1.0	15.0	10.0	(1) be the dried ripe seed of *Shorea robusta* Gaertn, family Dipterocarpaceae.
III	4.0	4.0	2.0	25.0	10.0	(2) be wholesome, free from moulds, weevils, obnoxious smell, deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the schedule.
						(3) have uniform size, shape and colour.

Definition : Foreign matter :

shall include dust, stones, lumps of earth, leaves, any other edible or non-edible seed.

Immature and Shrivelled seed :

shall be the seeds which are not properly developed and/or shrunken.

Damaged and Weevilled :

Shall be the seeds which are damaged mechanically or by mould or those showing internal discolouration of seeds materially affecting the quality. Weevilled seeds shall be those seeds which are partially or wholly bored or eaten by weevils or other insects.

Split and broken seeds: Splits shall be the seeds which are broken in two parts length-wise. Broken seeds shall be those which are smaller than split.

SCHEDULE II

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of the quality of Sal Seed Kernels

Grade designation	Definition of quality				General characteristics
	Special characteristics				
	Foreign matter, per cent by weight (Maximum)	Immature/ shrivelled kernels, per cent by weight (maximum)	Damaged weevilled kernels, per cent by weight (maximum)	Moisture, per cent by weight (Maximum)	
1	2	3	4	5	6
I	0.5	2.0	1.0	7.0	Sal kernels shall :
II	1.0	4.0	2.0	7.0	(1) be the kernels obtained from the dried, ripe seeds of *Shorea robusta* Gaertn, Family Dipterocarpaceae. (2) be reasonably dried, wholesome, free from visible moulds, weevils, obnoxious smell, deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the Schedule. (3) have uniform shape, size and colour.

Definition :

Foreign matter : shall include dust, stones, lumps of earth, leaves, outershell of seed, any other edible or non-edible seed/kernels.

Immature and shrivelled kernels :

shall be the kernels which are not properly developed and/or shrunken.,

Damaged weevilled kernels :

are those which are damaged mechanically or by mould/insects or those showing internal discolouration materially affecting the quality. Weevilled kernels shall be those kernels which are partially or wholly bored or eaten by weevils or other insects.

SCHEDULE III

(See rule 5)

Grade designation mark

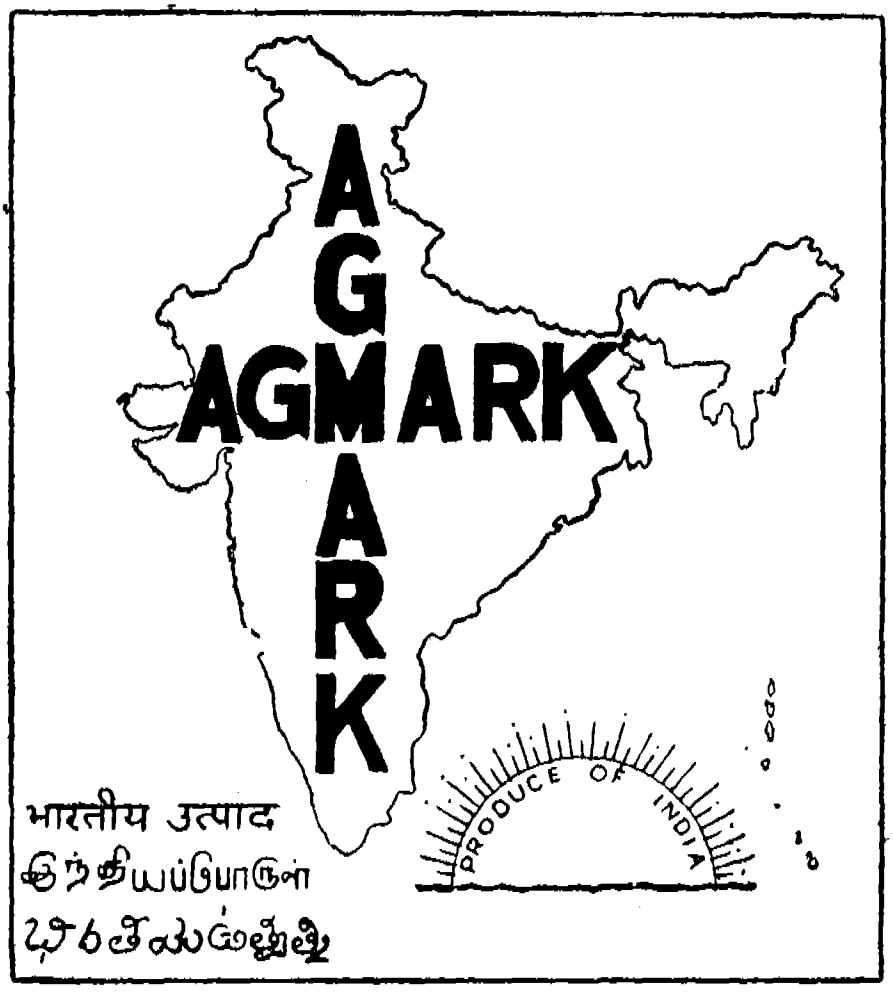

[No. F. 10-8/80—AM]

का०आ० 2650.—गवार गोंद श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1981 का एक प्रारूप, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 1576 तारीख 7 मई, 1981 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 23 मई, 1981 पृष्ठ 1644 से 1647 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 8 जून, 1981 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की बाबत प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है ; अर्थात्:—

नियम

संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ.—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गवार गोंद श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1982 है ।

(2) ये भारत में उत्पादित गवार गोंद को लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जबकि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार, अभिप्रेत है ;

(ख) "प्राधिकृत पैकर" से, ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय अभिप्रेत है, जिसे गवार गोंद के सम्बन्ध में साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1937 के नियम 3 के अधीन प्राधिकार-प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है ;

(ग) "अनुसूची" से, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ।

3. श्रेणी अभिधान:—गवार गोंद की क्वालिटी उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान वे होंगे जो अनुसूची I से III के स्तम्भ 1 में यथा उपवर्णित हैं ।

4. क्वालिटी की परिभाषा.—श्रेणी अभिधानों द्वारा उपदर्शित क्वालिटी वह होगी, जो अनुसूची I और II के स्तम्भ 2 से 8 और अनुसूची III के स्तम्भ 2 से 12 में प्रत्येक श्रेणी अभिधानों के सामने उपवर्णित है ।

5. श्रेणी अभिधान चिह्न.—श्रेणी अभिधान चिह्न एक लेबल होगा जिसमें एक ऐसा डिजाइन होगा, जिस पर अनुसूची IV में उपवर्णित चिह्न के सदृश भारत के मानचित्र की रूपरेखा, ऐगमार्क शब्द, उदय होते हुए सूर्य का चित्र तथा "Produce of India" और "भारतीय उत्पाद" शब्द अंकित होंगे।

टिप्पण:—(i) कागज या कपड़े के थैलों पर प्रयुक्त होने वाले श्रेणी अभिधान चिह्न, श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट करते हुए चिपकने वाला लेबल होगा।

(ii) वी-टिबल पटसन के बोरों पर प्रयुक्त किया जाने वाला श्रेणी अभिधान चिह्न, श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट करते हुए, बांधा जाने वाला आयताकार लेबल होगा ।

6. चिह्नांकन की पद्धति.—(1) श्रेणी अभिधान चिह्न, कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति से प्रत्येक आधान पर मजबूती से चिपकाया या स्टैंसिलकृत किया जाएगा और उसमें कृषि विपणन सलाहकार द्वारा पैकर को जारी किए गए कृषि प्राधिकार प्रमाणपत्र की संख्या भी उपदर्शित की जाएगी।

(2) श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त प्रत्येक आधान पर निम्नलिखित विशिष्टियां भी स्पष्ट रूप से चिह्नांकित की जाएंगी, अर्थात् :—

(क) पैक करने की तारीख ;

(ख) लॉट संख्यांक ,

(ग) पैकर का नाम और पता ;

(घ) शुद्ध भार ; और

(ङ) कोई अन्य विशिष्टियां जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(3) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, उक्त अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से आधान पर अपना निजी व्यापार चिह्न तब अंकित कर सकेगा, जब निजी व्यापार चिह्न गवार गोंद की ऐसी किसी क्वालिटी या श्रेणी को नहीं दर्शाता है, जो इन नियमों के अनुसार आधान पर चिपकाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा दर्शित क्वालिटी या श्रेणी से भिन्न है ।

7. पैक करने की पद्धति.—(1) गवार गोंद केवल पटसन (वीटटिबल बोरों) के बने अच्छे, साफ, शुष्क और अप्रयुक्त आधानों में या बोरों में या बहुस्तरीय क्राफ्ट के कागज के बोरों या कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य सामग्री में पैक की जाएगी । आधान किसी कीटग्रसन या फफूंदी संदूषण से मुक्त और किसी अवांछनीय गंध से भी मुक्त होंगे।

(2) आधान, कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति से मजबूती के साथ बंद और मुहरबंद किया जाएगा।

(3) प्रत्येक पैकेज में केवल एक ही श्रेणी वर्णन और एक ही श्रेणी अभिधान की गवार गोंद होगी ।

अनुसूची-I

(नियम 3 और 4 देखिए)

भूसी सहित विभक्त (कच्ची) गवार गोंद की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा						साधारण लक्षण
	विशेष लक्षण						
	भार के आधार पर नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	भार के आधार पर राख का प्रतिशत (अधिकतम)	भार के आधार पर (शुष्क आधार पर) प्रोटीन का प्रतिशत (अधिकतम)	भार के आधार पर अम्ल में अविलेय अवशिष्ट का प्रतिशत (अधिकतम)	भार के आधार पर गोंद का प्रतिशत (न्यूनतम)	भार के* आधार पर काले विभक्तों का प्रतिशत (अधिकतम)	
1	2	3	4	5	6	7	8
मानक	10.0	1.0	9 प्रतिशत से अनधिक	13.0	70.0	4.0	भूसी सहित विभक्त गवार गोंद:— (क) साइमाप्सिस टेटोगोनोलोबस
साधारण	12.0	2.0	9 प्रतिशत से अनधिक	14.0	67.0	7.0	लेग्युमिनोसी जाति के रूप में वनस्पति रूप से ज्ञात वनस्पति की गवार फलियों से गवार बीजों की कुटाई द्वारा अभिप्राप्त की जाएगी। (ख) गंदगी, धूल, अतिरिक्त रंजक पदार्थ, दृश्य फफूंदी, कीटग्रस्त और घृणाजनक गंध से मुक्त मुक्त होगी ; और (ग) के रूप, आकार और रंग में एक रूपता होगी।

*इसमें मानक श्रेणी के लिए कार्बनिक बाह्य जैसे तने/तृण/भूसा 0.5 प्रतिशत और साधारण श्रेणी के लिए 1.0 प्रतिशत हो सकता है।

अनुसूची-II

(नियम 3 और 4 देखिए)

भूसी रहित विभक्त (परिष्कृत) गवार गोंद की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और परिभाषाएं

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा						साधारण लक्षण
	विशेष लक्षण						
	भार के आधार पर नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	भार के आधार पर राख का प्रतिशत (अधिकतम)	भार के आधार पर (शुष्क आधार पर) प्रोटीन का प्रतिशत (अधिकतम)	भार के आधार पर अम्ल में अविलेय अवशिष्ट का प्रतिशत (अधिकतम)	भार के आधार पर गोंद का प्रतिशत (न्यूनतम)	भार के आधार पर *विभक्तों का प्रतिशत (अधिकतम)	
1	2	3	4	5	6	7	8
मानक	10.0	1.0	9 प्रतिशत से अनधिक	5.0	80.0	1.0	भूसी रहित विभक्त गवार गोंद :

1	2	3	4	5	6	7	8
साधारण	11.0	2.0	9 प्रतिशत से अनधिक	7.0	75.0	2.0	(क) सायमाप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्युमिनासो: जाति के रूप में वनस्पति रूप से ज्ञात वनस्पति की गवार फलियों से गवार बीजों की कुटाई द्वारा अभिप्राप्ति की जाएगी। (ख) गवगी, धूल, अतिरिक्त रंजक पदार्थ, दृश्य फफूंदी, कीटग्रसन और घृणाजनक गंध से मुक्त होगी ; और (ग) के रूप, आकार और रंग में एक रूपता होगी।

*इसके अन्तर्गत कार्बनिक बाह्य पदार्थ जैसे तने, तृण, भूसा भी है।

अनुसूची-III

(नियम 3 और 4 देखिए)

गवार गोंद (प्रकीर्णित) चूर्ण की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और परिभाषाएं

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा — विशेष लक्षण				
	भार के आधार पर नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	भार के आधार पर राख का प्रतिशत (अधिकतम)	भार के आधार पर (शुष्क आधार पर) प्रोटीन का प्रतिशत (अधिकतम)	भार के आधार पर अम्ल में अविलेय अवशिष्ट का प्रतिशत (अधिकतम)	भार के आधार पर गोंद का प्रतिशत (न्यूनतम)
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	11.0	0.5	9% से अनधिक	3.0	80.0
श्रेणी II	12.0	1.0	9 % से अनधिक	5.0	70.0
श्रेणी III	13.0	1.5	9 % से अनधिक	7.0	55.0

सेंटपायुससे में 25° सेंटीग्रेट पर श्यानता (न्यूनतम)	पी०एच०	आर्सेनिक (यथा ए एम्$_0$ ओ$_3$) पी पी एम (अधिकतम)	सीसा (पी पी एम) (अधिकतम)	साधारण लक्षण
7	8	9	10	11
3000.0	5.5—7.5	1.0	5	गवार गोंद चूर्ण : (क) सायमाप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्युमिनोसी : जाति के रूप में वनस्पति से ज्ञात, वनस्पति की गवार फलियों से गवार बीजों की बहुक्रम पिसाई करने के पश्चात् अभिप्राप्त उत्पाद होगा। (ख) स्टार्च बाह्य पदार्थ, अतिरिक्त रंजक पदार्थ, दृश्य फफूंदी, कीटग्रसन और घृणाजनक गंध से मुक्त होगी। (ग) 300 माइक्रान छलनी से गुजरेगी/क्रेताओं की विशेष छलनी अपेक्षाओं के अनुसार छलनी आकार के लिए सहायता 5%।
2000.0	6.0—8.0	1.0	5	
1000.0	6.0—8.0	1.0	5	

अनुसूची—IV

(नियम 5 देखें)

श्रेणी अभिधान चिह्न

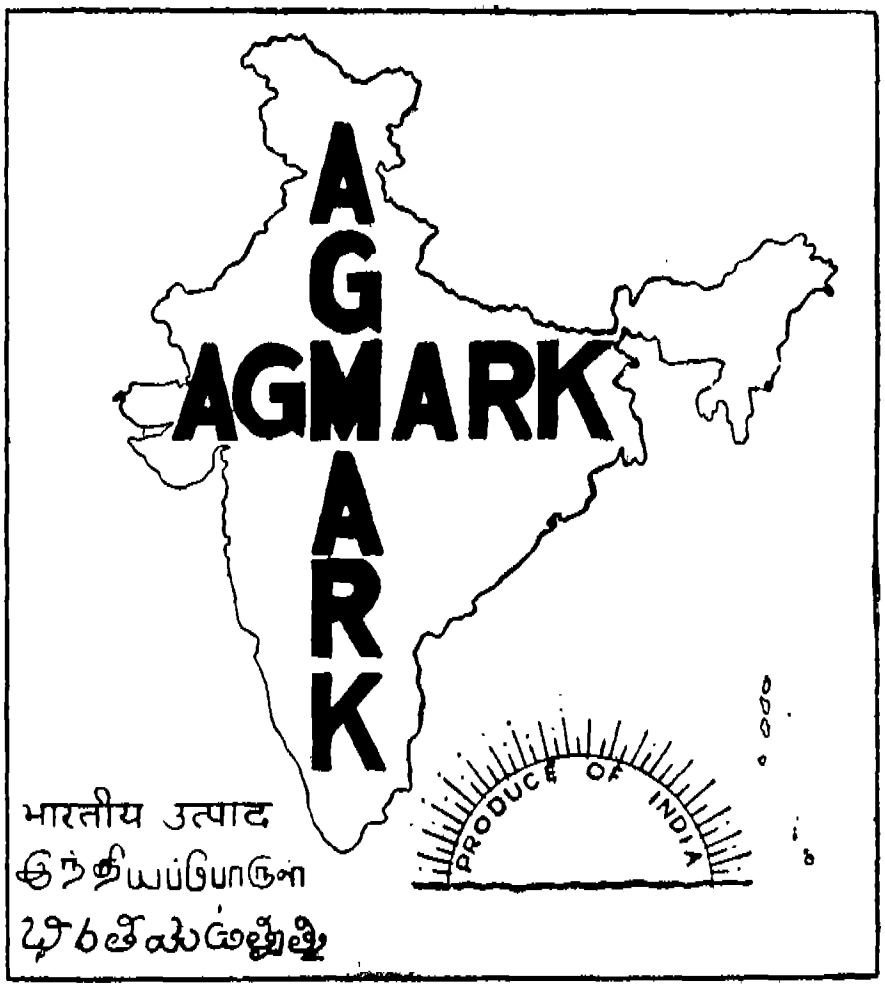

[फा० सं० 11-4/80-एएम]

राम सिंह, अवर सचिव

S.O. 2650.—Whereas a draft of the Guar Gum Grading and Marking Rules, 1981 was published as required by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) at pages 1644 to 1647 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 23rd May, 1981 with the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Reconstruction No. S.O. 1576 dated the 7th May, 1981 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 8th June, 1981;

And whereas, objections/suggestions received from the public in respect of the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

RULES

1. Short title, application and commencement.—(1) These rules may be called the Guar Gum Grading and Marking Rules, 1982.

(2) They shall apply to the Guar Gum produced in India.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(b) "Authorised Packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorisation under rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1937, in relation to Guar Gum;

(c) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

3. Grade designations.—The grade designations to indicate the quality of Guar Gum shall be as set out in Column 1 of Schedules I to III.

4. Definition of quality.—The quality indicated by the grade designations shall be as set out against each grade designation in columns 2 to 8 of Schedule I and II and columns 2 to 11 of Schedule III.

5. Grade designation mark.—The grade designation mark shall consist of label bearing a design consisting of an outline map of India with the word AGMARK and the figure of the rising sun with the words "Produce of India" and "भारतीय उत्पाद" resembling the mark set out in Schedule IV.

NOTE :—

(i) The grade designation mark to be used on paper or cloth bags shall consist of a paste-on label specifying the grade designation.

(ii) The grade designation mark to be used on B-twill jute bags shall consist of a rectangular tie-on label specifying the grade designation.

6. Method of marking.—(1) The grade designation mark shall be securely affixed or stencilled on each container in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser and shal also indicate the number of the certificate of authorisation issued to the packer by the Agricultural Marketing Adviser.

(2) In addition to the grade designation mark, every container shall be clearly marked with the following particulars, namely :—

(a) Date of packing;

(b) Lot number;

(c) Name and address of the packer;

(d) Net weight; and

(e) Any other particulars as may be specified by the Agricultural Marketing Adviser.

(3) The authorised packer may, after obtaining the prior approval of the Agricultural Marketing Adviser, mark his private trade mark on a container in a manner approved by the said officer, provided the private trade mark does not represent quality or grade of the Guar Gum different from that indicated by the grade designation mark affixed on the container in accordance with these rules.

7. Method of packing.—(1) The Guar Gum shall be packed only in sound, clean, dry and un-used containers made of B-twill jute or in polythene bags placed in gunny bags or multiply kraft paper sacks or any other material as may be approved by the Agricultural Marketing Adviser. The container shall be free from any insect infestation or fungrs contamination and also free from any undesirable smell.

(2) The container shall be securely closed and sealed in the manner approved by the Agricultural Marketing Adviser.

(3) Each package shall contain Guar Gum of one trade description and one grade designation only

SCHEDULE I

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definitions of quality of undehusked split (crude) Guar Gum

Grade designation	Definition of quality						
	Special characteristics						General characteristics
	Moisture, per cent by weight (Maximum)	Ash per cent by weight (Maximum)	Protein, per cent by weight (on dry basis)	Residue in soluble in acid, per cent by weight (maximum)	Gum, percent by weight (minimum)	Black splits* per cent by weight (maximum)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Standard	10.0	1.0	Not more than 9 %	13.0	70.0	4.0	The undehusked split guar gum shall ; (a) be obtained by milling guar seed from guar pods of the plant botanically known as Cyamopsis tetragonolobus, Leguminosae family. (b) be free from dirt, dust, added colouring matter, visible mould growth insect infestation and obnoxious smell. (c) have characteristic shape, size and colour.
General	12.0	2.0	Not more than 9 %	14.0	67.0	7.0	

*Includes organic extraneous matter such as stems/straw/chaff to the extent of 0.5 per cent for standard grade and 1.0 per cent for general grade.

SCHEDULE II

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definitions of quality of dehusked split (Refined) Guar Gum

Grade designation	Definition of quality						
	Special characteristics						General characteristics
	Moisture per cent by weight (Maximum)	Ash, per cent by weight (Maximum)	Protein, per cent by weight (on dry basis)	Residue insoluble in acid, by weight (Maximum)	Gum, per cent by weight (Maximum)	Black splits* per cent by weight (Maximum)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Standard	10.0	1.0	Not more than 9 %	5.0	80.0	1.0	The dehusked split guar gum shall : (a) be obtained by milling guar seeds after removal of husk, from guar pod of the plant botanically known as Cyamopsis tetragonolobus, leguminosae family. (b) be free from dirt, dust, added colouring matter, visible mould growth, insect infestation and obnoxious smell. (c) have characteristic shape, size and colour.
General	11.0	2.0	Not more than 9%	7.0	75.0	2.0	

*Includes organic extraneous matter such as stems, straw, chaff.

SCHEDULE III

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definitions of quality of Guar Gum (pulverised) powder.

Grade designation	Definition of quality									
	Special characteristics									General Characteristics
	Moisture per cent by weight (Maximum)	Ash, per cent by weight (Maximum)	Protein, per ent by weight	Residue insoluble in acid percent by weight weight (Maximum)	Gum, per cent by weight (Minimum)	Viscocity at 25°C in centipoises (Minimum)		Arsenic (As As_2O_3) p.p.m. (Maximum)	Lead (p.p.m, (Maximum)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grade I	11.0	0.5	Not more than 9%	3.0	80.0	3000	5.5—7.5	1.0	5	The guar gum powder shall : (a) be the produce obtained after multistage grinding of the guar seeds from guar pods of the plant bontanically known as *Cyapsis tetragonolobus* leguminosae family. (b) be free from added starch, extraneous matter, added colouring matter, visible mould growth, insect infestation and obnoxious smell.
Grade II	12.0	1.0	Not more than 9%	5.0	70.0	2000	6.0—8.0	1.0	5	
Grade III	13.0	1.5	Not more than 9%	7.0	55.0	1000	6.0—8.0	1.0	5	

	11
	(c) pass through 300 micron sieve/as per specific sieve requirements of the buyers. Tolerance for sieve size 5%

SCHEDULE IV

(See rule 5)

Grade designation mark

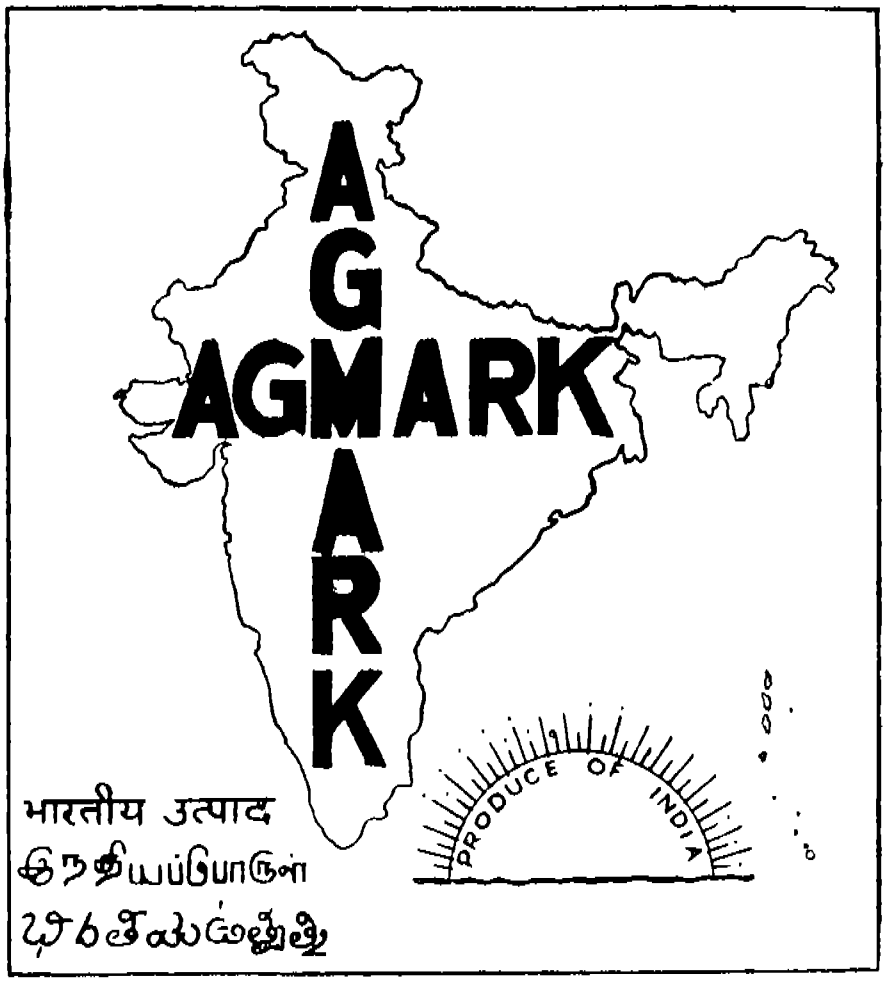

[No. F-11-4/80-AM]

RAM SINGH, Under Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1982

का०आ० 2651.—पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की दिनांक 28 जून, 1982 की समसंख्यांक अधिसूचना में, असेसरों की क्रम सं० 3 पर आए कैप्टेन के०सी० मेहरा, उप निदेशक (परिचालन) इंडियन एयरलाइंस के स्थान पर श्री जे० के० मेहरा, प्रबंधक, तकनीकी प्रशिक्षण, केन्द्रीय प्रशिक्षण संगठन, इंडियन एयरलाइन्स हैदराबाद, पढ़ा जाए ।

[फाइल सं० ए-15013/5/82-ए]

एम० एकाम्बरम्, निदेशक

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st July, 1982

S.O. 2651.— In the Ministry of Tourism and Civil Aviation's Notification of even number dated 28th June, 1982 in place of Capt. K.C. Mehra, Deputy Director (Operation) Indian Airlines, appearing at S. No. 3 of the Assessors, read Shri J.K. Mehra, Manager, Technical Training, Central Training Establishment, Indian Airlines, Hyderabad.

[F. No. Av. 15013/5/82-A]

S. EKAMBARAM, Director

निर्माण और आवास मंत्रालय

(सम्पदा निदेशालय)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1982

का०आ० 2652.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निम्न सारणी के कालम (1) में उल्लिखित अधिकारियों को, सरकार के राजपत्रित अधिकारी होने के नाते, उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु संपदा अधिकारी नियुक्त करती है, और आगे निदेश देती है कि उक्त सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के संबंध में उक्त अधिकारी उनके तत्संबंधी अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उसके अधीन संपदा अधिकारियों को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेंगे :—

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थानों की श्रेणियां और अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
1. सहायक संपदा प्रबन्धक, शिमला	चंडीगढ़ में साधारण पूल आवास
2. कार्यकारी इंजीनियर, के० लो० नि० वि०, चंडीगढ़	के०लो०नि०वि० के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन चंडीगढ़ में अवस्थित सरकारी स्थान

[फाइल सं० डी-11031/7/82-रीजन्स]

एस० पी० विश्वास, सम्पदा निदेशक ।

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

(Directorate of Estates)

New Delhi, 6th July, 1982

S.O. 2652.—*In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises Eviction of Unauthorised Occupants Act, 1971 (46 of 1971), the Central Govt. hereby appoints the officers mentioned in Column (1) of the table below, being gazetted officers of Government to be estate officers for the purpose of the said Act, and further directs that the said officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officers by or under the said Act within the limits of their respective jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.*

TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of Jurisdiction
(1)	(2)
1. Assistant Estate Manager, Simla.	General Pool accommodation at Chandigarh.
2. The Executive Engineer, C.P.W.D. Chandigarh.	Premises under the administrative control of the CPWD situated at Chandigarh.

[File No. D-11031/7/82-Regions]

S.P. BISWAS, Director of Estates

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1982

सूचनाएं

का० आ० 2653.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 11 के अन्तर्गत सूचना ।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि:—

(क) केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 9 की उपधारा 2 के अन्तर्गत क्षेत्र ए-6 (कदम शरीफ) हेतु क्षेत्रीय विकास चित्र को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) उक्त अनुमोदित चित्र की एक प्रति दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-1 में सभी कार्यशील दिवसों को 11-00 बजे (पूर्वाह्न) से 3-00 बजे (अपराह्न) तक देखने के लिए उपलब्ध है।

[संख्या एफ० 4(7) 63-एम० पी०]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 24th July, 1982

NOTICES

S.O. 2653.—Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957).

Notice is hereby given that :—

(a) The Central Government have under sub-section (2) of Section 9 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) approved the zonal development plan for zone A-6 (Quidam Sharif).

(b) A copy of the plan as approved may be inspected at the Office of the Delhi Development Authority, Delhi Vikas Minar, 19th Floor, Indraprashtha Estate, New Delhi-1 between the hours of 11-00 a.m. and 3-00 P.M. on all working days.

[No. F. 4(7)/63-MP]

का० आ० 2654.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 11 के अन्तर्गत सूचना।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि:—

(क) केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 9 की उप-धारा 2 के अन्तर्गत क्षेत्र डी-10 (बुद्ध जयन्ती पार्क) हेतु क्षेत्रीय विकास चित्र को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) उक्त अनुमोदित चित्र की एक प्रति दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय 19वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में सभी कार्य-दिवसों को 11-00 बजे (पूर्वाह्न) से 3-00 बजे (अपराह्न) तक देखने के लिए उपलब्ध है।

[संख्या एफ० 4(10)/68-एम० पी०]

S.O. 2654.—Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957).

Notice is hereby given that :—

(a) The Central Government have, under sub-section (2) of Section 9 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) approved the zonal development plan for zone D-10 (Budha Jayanti Park).

(b) A copy of the plan as approved may be inspected at the office of the Delhi Development Authority, Delhi Vikas Minar, 19th Floor, Indraprastha Estate, New Delhi-1 between the hours of 11-00 a.m. and 3-00 P.M. on all working days.

[No. F. 4(10)/68-MP]

का० आ० 2655.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 11 के अन्तर्गत सूचना।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि :—

(क) केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 9 की उप-धारा 2 के अन्तर्गत क्षेत्र एफ-6 (मोती बाग) हेतु क्षेत्रीय विकास चित्र को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) उक्त अनुमोदित चित्र की एक प्रति दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय 19वी मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में सभी कार्य-दिवसों को 11-00 बजे (पूर्वाह्न) से 3-00 बजे अपराह्न) तक देखने के लिए उपलब्ध है।

[संख्या एफ० 4(1)/63 एम० पी०]

नाथूराम, सचिव।

S.O. 2655.—Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957).

Notice is hereby given that :—

(a) The Central Government have, under sub-section (2) of Section 9 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) approved the zonal development plan for zone F-6 (Moti Bagh).

(b) A copy of the plan as approved may be inspected at the office of the Delhi Development Authority, Delhi Vikas Minar, 19th Floor, Indraprastha Estate, New Delhi-1 between the hours of 11.00 a.m. and 3-00 P.M. on all working days.

[No. F. 4(1)/63-MP]
NATHU RAM, Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 14 जून, 1982

का० आ० 2656.—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792, दिनांक 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबंध के अंतर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद एतद्द्वारा इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरण सहित जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई (मीटरों में)	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है।
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश समाचार-86	251.16	धीरेन्द्र पान्डे, निर्माता (फिल्म), सूचना और जन संपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। उत्तर प्रदेश सर्किट में प्रदर्शन के लिए।
2.	उत्तर प्रदेश समाचार-87	288.95	-तदैव-		-तदैव-
3	अस्थमा	297.00	फिल्म प्रभाग भारत सरकार, 24-डा० जी० देशमुख मार्ग, बम्बई-400026.		डाकुमेंटी फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिये।
4	ए लिटल थाट	230.00	-तदैव-		-तदैव-
5.	विजडम आफ मोर्जीराम	73.152	-तदैव-		-तदैव-
6.	फार माई फयूचर (आपके कल के लिए)	63.00	-तदैव-		-तदैव-
7	दोषी कौन ?	136.16	एशियन फिल्म्स, 72-जनपथ, नई दिल्ली 110001		डाकुमेन्टी फिल्म। दिल्ली में प्रदर्शन के लिए।
8	महिती चित्र संख्या 354 क	259.08	सहायक सूचना निदेशक (फिल्म), गुजरात सरकार, रामनार्ड रिसर्च लेबोरेटीज लि० 77 डा० एनी बेसेंट रोड, बम्बई-400018।	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार सचिवालय, गांधीनगर-382010	डाकुमेंट्री फिल्म; गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिये
9.	पथदर्शक (संशोधित)	350.52	—तदैव—	—तदैव—	डाकुमेंट्री फिल्म, सामान्य प्रदर्शन के लिये
10.	उत्तर प्रदेश समाचार 88	281.63	धीरेन्द्र पाण्डे, निर्माता (फिल्म), सूचना और जन संपर्क विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। उत्तर प्रदेश सर्किट में प्रदर्शन के लिए।
11.	अलोकरा जत्रा (रंगीन)	569.36	चारी महन्त, आई० पी० आर० ओ, असम राज्य विद्युत बोर्ड, नारंगी गोहाटी-781026	मेसर्स देवजनी चालिहा और सबधिन पी-21 गोल्फ क्लब रोड, कलकत्ता-700033	डाकुमेन्ट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिए।
12	विपद : सावधान (रंगीन)	437.69	-तदैव	-तदैव-	डाकुमेन्ट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिए।
13.	विस लैड इज माइन (रंगीन)	338.33	हरि एस० दासगुप्त प्रोडक्शन, मार्फत वत्सला पाटंकर 611 म्यूर, एस० वी० पटेल रोड, बोरीवली पश्चिम, बम्बई-400092		डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिये।
14	महाराष्ट्र समाचार संख्या 368	295.00	सूचना और जनसंपर्क महानिदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म केन्द्र, 68-तारदेव रोड, बम्बई-34		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। महाराष्ट्र सर्किट में प्रदर्शन के लिये।
15	वार्ता तरंगिनी संख्या 17	281.80	आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि०, गृहकल्प, एम० जे० रोड, हैदराबाद-1		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। आन्ध्र प्रदेश सर्किट में प्रदर्शन के लिये।
16.	वार्ता तरंगिनी संख्या 18	266.60	—तदैव—		

1	2	3	4	5	6
17	दम्नु	274 5	सूचना और जन संपर्क महानिदेशालय महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सेंटर, 68-तारदेव रोड, बम्बई-34।		डाकुमेंट्री फिल्म । सामान्य प्रदर्शन के लिये।
18	सखिनी चित्र संख्या 355	289 56	सहायक सूचना निदेशक (फिल्म) गुजरात सरकार, रामनार्ड लेबारटरी लि०, 77-डा० एनी बेसेंट रोड, बम्बई-400018।	सूचना निदेशक (फिल्म), गुजरात सरकार सचिवालय	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म । गुजरात सर्किट मे प्रदर्शन के लिये ।
19	दी कासबाद एक्सपेरिमेन्स	167 00	के० के० कपिल, 133-जहू प्रभात न्यू डी० एन० नगर बम्बई-400058		डाकुमेंट्री फिल्म । सामान्य प्रदर्शन के लिये।
20	याद करो कुर्बानी (नथ कार मजे जुलाट।)	301 00	सूचना और जन संपर्क महानिदेशालय महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सेंटर, बम्बई-34।		डाकुमेंट्री फिल्म । महाराष्ट्र सर्किट में प्रदर्शन के लिये।
21	दि कैमिस्ट्री आफ इंडिया (रंगीन)	305 00	मैसर्स रिवेलेशन ई-20 एवरेस्ट तारदेव रोड, बम्बई-400034।		डाकुमेंट्री फिल्म । सामान्य प्रदर्शन के लिये।
22	दि च्वाइस इज योर्स (फैसला आप पर)	498 98	धीरज चौहान, धीरज प्राडक्शन, स्मृति बिल्डिंग, फ्लैट संख्या 1 प्रथम तल 4-ई, जय भारत, खार (पश्चिम), बम्बई-52।		डाकुमेंट्री फिल्म । सामान्य प्रदर्शन के लिये।
23	मध्य प्रदेश समाचार दर्शन-33	268 04	सहायक निदेशक, सूचना और प्रचार मध्य प्रदेश। निदेशक, सूचना और प्रचार, मध्य प्रदेश।		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म । मध्य प्रदेश सर्किट के लिये।
24	फारपीस एण्ड अमिटी (रंगीन)	559 00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-400006।		डाकुमेंट्री फिल्म । सामान्य प्रदर्शन के लिये।
25	एक्सेपटेंस	370	मैसर्स न्यू प्वाइंट, ए-5, रवि दर्शन कार्टर रोड बम्बई-50।	सुनिल घोष, मैसर्स न्यू प्वाइंट यू-5, रवि दर्शन, कार्टर रोड, बम्बई-50।	डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिये।
26	इलक्ट्रीकल हेजर्ड्स	364	एम० एम० राजन, 32, आदित्य बिल्डिंग, 501 रास्ता पठ, पुणे-411011।	एम० एम० राजन, 32-आदित्य बिल्डिंग, पुणे-411011।	—तदैव—
27	मैकेनिकल हैजर्ड्स	381	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

1	2	3	4	5	6
8	एक छोटा सा घर होता	250	ऋषि फिल्म्स 11, क्षितिज, आदर्श सोसाइटी रामचन्द्र लेन, मालाड (पश्चिम), बम्बई-64		-तदैव-
9	ग्रोल्ड कालइज दि इनर्जी न्यू	240.79	काल इंडिया लि०, नं०-10, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	फिल्म, मीडिया, 47, लक्ष्मी इन्श्योरेंस बिल्डिंग, सर पी० एम० रोड, बम्बई-1	-तदैव-
10	महिती चित्र संख्या 365	228.60	सहायक सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, रामनार्ड रिसर्च लेबोरेट्रीज लि०, 77-डा० एनी बेसेंट रोड, बम्बई-18		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म, गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिए।
31.	सूरज अकेला चलता है	292.30	सूचना और जनसम्पर्क महानिदेशालय, महाराष्ट्र सरकार फिल्म सेंटर, 68-तारदेव रोड, बम्बई-34		डाकुमेंट्री सामान्य प्रदर्शन के लिए।
32	फोक ड्रामा ग्राफ गुजरात "भवाई"	480.06	सहायक सूचना निदेशक (फिल्म), गुजरात सरकार, रामनार्ड रिसर्च, लेबोरेट्रीज लि०, 77-डा० एनी बेसेंट रोड, बम्बई-18		-तदैव-
33	चन्द्रभैनी चिन्ता	184.40	-तदेव-		-तदैव-
34	कैमीकल हैज फ़र्म	472.44	एम० एम० राज नं० 32, आदित्य बिल्डिंग, 501, रास्ता पेट, पुणे-411011		-तदैव-
35.	गुड हाउस कीपिंग	505.42	-तदेव-		-तदैव-
36.	उत्तर प्रदेश समाचार-93	276.15	धीरेन्द्र पांडे (निर्माता), न्यूजरील, सूचना और जनसम्पर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (उत्तर प्रदेश सर्किट मे प्रदर्शन के लिए)
37.	मध्य प्रदेश समाचार, दर्शन-36	291.63	सूचना और प्रचार निदेशक, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल।		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म मध्य प्रदेश सर्किट में प्रदर्शन के लिए।
38.	हिमाचल के लोक नृत्य	475.49	जनसम्पर्क निदेशक, हिमाचल प्रदेश सरकार, , शिमला।		डाकुमेंट्री फिल्म केवल हिमाचल प्रदेश सर्किट में प्रदर्शन के लिए।
39	न्यो-यूथ फिल्म फैस्टिवल	302	फिल्म्स प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-400026		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। सामान्य प्रदर्शन के लिए।

1	2	3	4	5	6
40.	सुधारेल खेती पद्धति	297	सूचना सहायक निदेशक (फिल्म) गुजरात सरकार, रामनाईं रिसर्च लेबोरेट्रीज, 77-डा० एनीबेसेंट रोड, बम्बई-18	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, सचिवालय, ब्लाक संख्या 7, गांधी नगर-382010	डाकुमेंट्री फिल्म गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिए।
41.	फारयू	297.18	जगदीश बैनर्जी, 2, हिमगिरी पेडर रोग, बम्बई।	उमेश बैनर्जी, 2, भावेश्वर टैरेस, 85 डॉ० ऐनी बेसेंट रोड, वोरली, बम्बई।	डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिए।
42.	वार्ता तरंगीनि संख्या 22	200	आन्ध्र प्रदेश फिल्म विकास निगम लि० गृह कल्प, एम० जे० रोड, हैदराबाद-500001		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म आन्ध्र प्रदेश सर्किट में प्रदर्शन के लिए।
43	महिनी चित्र संख्या 364	254.51	सहायक सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, रामनाईं रिसर्च लेबोरेट्रीज लि०, 77-डॉ० ऐनी बेसेंट रोड, बम्बई-18।	सूचना निदेशक, गुजरात, सरकार, सचिवालय, ब्लाक संख्या 7, गांधी नगर-382010।	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिए।
44.	उत्तर प्रदेश समाचार 93	266.70	धीरेन्द्र पाडे, निर्माता न्यूजरील, सूचना और जन सपर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म उत्तर प्रदेश सर्किट में प्रदर्शन के लिये।
45.	फ्लाइट आफ टेलीफोन	228.60	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24 पैडर रोड, बम्बई-400026		डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिये।
46.	किंग आफ दी जंगल	85.344	—तदेव—		डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिए।
47	स्पेरिंग इन सिक्किम	297.00	—तदेव—		—तदेव—
48.	न्यू डिस्ट्रिक्ट सिन्धु दुर्ग	161	सूचना और जन संपर्क महानिदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सेंटर, 68-तारदेव रोड, बम्बई-400034	महाराष्ट्र सरकार	डाकुमेंट्री फिल्म महाराष्ट्र सर्किट में प्रदर्शन के लिये।
49	चलती रहे जो	356.92	सहायक सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, रामनाईं, रिसर्च लेबोरेट्रीज, 77, एनीबेसेन्ट रोड, वोरली, बम्बई-400018	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, सचिवालय, ब्लाक संख्या 7, गांधीनगर-392010	डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिये।
50	उत्तर प्रदेश समाचार 92	288.95	धीरेन्द्र पांडे, प्रोड्यूसरा न्यूजरील, सूचना और जन सपर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।		समाचार और सामयिक घटना की फिल्म। उत्तर प्रदेश सर्किट में प्रदर्शन के लिए।
51.	महिनी चित्र संख्या 363	262.13	सहायक सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, रामनाईं रिसर्च लेबोरेट्रीज, लि०, 77-डा० एनीबेसेंट रोड, वोरली, बम्बई-400018	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, सचिवालय, ब्लाक संख्या 7, गांधी नगर-382010	समाचार और सामयिक घटना की फिल्म गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिये।

1	2	3	4	5	6
52	सुखी जीवन का राज (रंगीन)	285.00	मैसर्स ए० एम० ए० प्राईवेट लि०, कनाटा बिल्डिंग, डा० डी० एन० रोड० बम्बई-1		डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिये।
53	टी० बी० कन्ट्रोल कैम्पेन 1982	281.68	बाल एम० जोगलेकर, सह-निर्माता, 7/6, शिवाजी नगर, बोरली, बम्बई-25	आर० बी० नैने, मुख्य चिकित्सक, जसलोक अस्पताल, पेडर रोड, बम्बई।	डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिये।
54.	विरेन्द्र नाथ सिरकार	531.31	भेजेश कुमार कलात्मक ओल्ड म्यूचल बिल्डिंग, तीसरा तल, 23 ए देश मार्ग, बम्बई-23		डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिये।
55.	प्राईमरी हैल्थ सेंटर	163.30	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24-पैडर रोड, बम्बई-400026		डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिए
56.	कल और आज (रंगीन) कार्टून	186.00	कुमारी विमला स्वामीनाथन, राम श्याम निवास एस० डी० मंदिर रोड, महिम, बम्बई		तदैव
57	क्या आप जानते है ?	297.18	एच० टी० वेंवे स्वामी, प्रसार भवन, स्वामीनारायन चौक, दादर, बम्बई-400014।	बोचासन्वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम संस्था, शाही बाग रोड, अहमदाबाद-380004	डाकुमेंट्री फिल्म अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शन के लिये।
58	महाराष्ट्र समाचार संख्या 372	274.00	सूचना और जन सम्पर्क महानिदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सेंटर, 68 तारदेव रोड, बम्बई-34		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म महाराष्ट्र सर्किट में प्रदर्शन के लिये।
59	स्ट्रीम एबिलिटी (रंगीन)	304.80	मोही-उ-दीन मिर्जा, हिलमैन फिल्म, 4-एफ०/2, कोर्ट चेम्बर्स 35-न्यू मैराइन लाइन्स, बम्बई-20	हिलमैन फिल्म, 4-एफ/2 कोर्ट चेम्बर्स 35-न्यू मैराइन लाइन्स बम्बई-20	डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिये।
60.	बचाइये बचाइये बचाइये ऊर्जा	408.84	अशोक सागर पो० आ० बाक्स-5543 बम्बई-400014		डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिये।
61.	ए० प्रोग्राम फार प्रोग्रेस	270.00	फिल्म प्रभाग, 24-पैडर रोड, बम्बई-400026		डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिये।
62.	उत्तर प्रदेश समाचार-91	292.61	धीरेन्द्र पाण्डे, निर्माता, न्यूजरील मार्फत बम्बई फिल्म लेबोरेट्रीज लि०, 149-एम० के० बोले रोड, बम्बई-28	धीरेन्द्र पाण्डे निर्माता, न्यूजरील, सूचना और जनसम्पर्क निदेशालय उत्तरप्रदेश सरकार, लखनऊ।	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। उत्तर प्रदेश सर्किट में प्रदर्शन के लिये।
63	सहिली चित्र संख्या 362	259.08	सहायक सूचना निदेशक गुजरात सरकार, रामनार्ड रिसर्च लेबोरेट्रीज लि०, 77-डा० एनी बेसेन्ट रोड, वोरली, बम्बई-18	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार सचिवालय।	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिए।
64.	श्रीवत्स (लघु रूपान्तर)	351.00	प्रकाश झा, चित्रपट, 3-अमर काटेज मारोल, अन्धेरी (पूर्व), बम्बई-59		डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिये।
65.	मध्य प्रदेश समाचार स० 34	280.00	सहायक सूचना और प्रकार निदेशक, मध्य प्रदेश सरकार, मार्फत बम्बई फिल्म लेबोरेट्रीज, दादर, बम्बई।	सूचना और प्रकार निदेशक, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल।	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। मध्य प्रदेश सर्किट में प्रदर्शन के लिये।
66	मध्य प्रदेश समाचार संख्या 35	289.00	--तदैव--	--तदैव--	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। मध्य प्रदेश सर्किट में प्रदर्शन के लिये और सामान्य प्रदर्शन के लिये।
67.	आईथिंक आई कैन इफ ओनली यू कैन	468.00	फिल्म प्रभाग, 24-पैडर रोड, बम्बई-400026		डाकुमेंट्री फिल्म। सामान्य प्रदर्शन के लिये।

1	2	3	4	5	6
68.	वार्ता तरंगिनी संख्या 21	260.67	आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि०, "गृह कलव्य", एम० जे० रोड, हैदराबाद-500001.		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। आंध्र प्रदेश राज्य में प्रदर्शन के लिये।
69.	नयी खेती पद्धति द्वारा समृद्धी	297.18	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार सचिवालय, गांधी नगर।		डाकुमेंट्री फिल्म। गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिए।
70.	एंड दैन मैन करिएटिड गाइड्स एंड डेमन्स इन हिज ओन इमेज	402.03	ग्रजीज, फिल्म्ज, अम्बलमोक्कू, त्रिवेन्द्रम।		डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिये।
71.	इंडियन टेलीफोन्स—100 इयर्स यंग	284.38	फिल्म प्रभाग, 24-पैडर रोड, बम्बई-400026		—तदैव—
72.	महिती चित्र संख्या 362	243.84	सहायक सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, रामनार्ड रिसर्च लेबोरेट्रीज लि०, 77-डा० एनी बेसेंट रोड, वोरली, बम्बई-400018	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार सचिवालय, गांधीनगर-382010	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिये।
73.	युगद्रष्टा स्वामी सगहृानन्द (रंगीन)	298.70	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार सचिवालय, गांधीनगर-382010	—तदैव—	डाकुमेंट्री फिल्म। सामान्य प्रदर्शन के लिये।
74.	वर्ल्ड कप हाकी-1982	292.60	फिल्म प्रभाग, 24-पैडर रोड, बम्बई-400026		डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिये।
75.	गांव गांव बनती ज्वाली जाय (रंगीन)	586.00	चारु महन्त, सूचना और जन सम्पर्क निदेशालय, असम राज्य विद्युत बोर्ड, नारंगी, गोहाटी-781026	मैसर्स देवजानी चाविहा एंड ऐसोसियेट्स पी-21, गोल्फ क्लब, रोड, कलकत्ता-33	डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिये।
76.	संगीमा रत्न डा० मल्लिकार्जुन मंसूर	381.00	के० जी० शिवयोगी फोटोग्राफर, 39/40 भंडारी कम्पलेक्स, शेषाद्री रोड, आनंद राव सर्किल, बंगलौर-560009	के० जी० शिवायोगी, 39/40-भंडारी कम्पलेक्स शैषाद्री रोड, आनंदराव सर्कल, बंगलौर-560009	डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिये।
77.	प्रबोड आफ गाड्स (रंगीन)	400.00	सी० एफ० मार्कोनी, आनन्द बिहार-69, वी० दे० साई रोड, बम्बई-26		—तथव—
78.	आफ्टर स्कूल वाट नैक्स्ट	335.44	रवि मेहरा, मार्फत क्रीएटिव यूथ 36, हरी मार्किट, खार रेलवे स्टेशन के सामने, खार, बम्बई-52		डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिये।
79.	मेकिंग ए० फाइटर पायलट (रंगीन)	386.00	फिल्म प्रभाग, 24-पैडर रोड, बम्बई-26	फिल्म प्रभाग, 4-टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली।	—तथैव—
80.	राजमाया जिजो 384वीं जन्मोत्सव सोहाला	188	सूचना और जनसंपर्क महानिदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सेंटर, 68, तार देव रोड, बम्बई-400034		डाकुमेंट्री फिल्म महाराष्ट्र सर्किट में प्रदर्शन के लिये।
81.	हिजरा हरा सेलिब्रेशन्स इन इंडिया	391	फिल्म प्रभाग 24-पैडर रोड, बम्बई-26	फिल्म प्रभाग 4-टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली।	डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिये।
82.	ए० लाइफ आफ ओनर	500	फिल्म प्रभाग, 24-पैडर रोड, बम्बई-26	फिल्म प्रभाग, 24-पैडर रोड, बम्बई/नई दिल्ली।	डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिये।
83.	सेकिंड हनीमून	84.430	—तथैव—	—तथैव—	—तथैव—
84.	रील आफ टेलीकम्यूनीकेशन	270	—तथैव—	—तथव—	—तथैव—
85.	सी० वी० रमण	500	—तथैव—	—तथैव—	—तथैव—
86.	गुजरात्मा भडी जातिने विकास	428.91	सहायक सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, रामनार्ड रिसर्च लबोरेट्रीज, वोरली, बम्बई-18	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार सचिवालय, गांधी नगर-382010	डाकुमेंट्री फिल्म गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिये।
87.	जल मन्थन	528.52	—तथैव—	—तथैव—	—तथैव—

1	2	3	4	5	6
88.	उत्तर प्रदेश समाचार-95	284.99	ए० डेविड, मार्फत बम्बई फिल्म लेबोरेट्रीज (प्रा०) लि०, 149-एस०के० बोले रोड, बम्बई-400028	सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, सरकार लखनऊ ।	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म । उत्तरप्रदेश सर्किट मे प्रदर्शन के लिये
89.	उत्तर प्रदेश समाचार-96	276.15	धीरेन्द्र पाण्डे, सूचना और जन संपर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म । उत्तर प्रदेश सर्किट में प्रदर्शन के लिये ।
90	दि फेमिली	250	फिल्म प्रभाग, 24-पैडर रोड, बम्बई-26		डाकुमेंट्री फिल्म । सामान्य प्रदर्शन के लिये।
91.	दमन गंगा	366	सहायक सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, रामनाडे गुबोरेट्रीज, बोरली, बम्बई	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार सचिवालय, गांधीनगर, गुजरात।	डाकुमेंट्री फिल्म गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिये।
92.	बम्बई पोर्ट	472.440	फिल्म प्रभाग, 24-पैडर रोड, बम्बई 400026		डाकमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिये ।
93.	कोलयू यूरिमा	258.22	—तथैव—		—तथैव—
94.	सेक्सूअली ट्रांसमिटिड डिसिजिज	492.00	—तथैव—		'ए' प्रमाणपत्र के लिए डाकुमेंट्री फिल्म । सामान्य प्रदर्शन के लिये ।
95.	मार्ता तंरे गिनी	275.91	आन्ध्रप्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि० "गृहकल्प", एम० जे० रोड, हैदराबाद-500001		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म । आंध्र प्रदेश सर्किट में प्रदर्शन के लिये ।
96.	सो फार सीमियर	396.5	वी० एस० एन्टर प्राइजिज, नाथन, 11, रामश्याम निवास, सीतादेवी मंदिर रोड, महीम, बम्बई-400014	कुमारी विमला स्वामी	डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिये।

[फाइल संख्या 315/1/80-एफ(पी)]
सुकुमार मंडल, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDER

New Delhi, the 14th June, 1982

S.O. 2656.—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information & Broadcasting No. S.O. 3792 dated 2nd December, 1966 the Central Government after considering recommendations of the Films Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length of the film in metres	Name of the applicant	Name of the producer	Brief synopsis whether scientific film or for educational purpose of a film dealing with news and current events or documentary film
1	2	3	4	5	6
1.	Uttar Pradesh Samachar-86	251.16	Dhirendra Pandey, Producer (Films), Deptt. of Information & Public Relations, Government of U.P., Lucknow		'News and Current Event for release in UP circuit
2.	Uttar Pradesh Samachar-87	288.95	-do-		-do-

1 2	3	4	5	6
3. Asthama	297.00	Films Division, Government of India, 24-Dr. G. Deshmukh Marg, Bombay-400026.		'Documentary' for General release.
4. A Little Thought	230.00	-do-		-do-
5. Wisdom of Maujiram	73.153	Films Division, Government of India, 24-Dr. Deshmukh Marg, Bombay-26.		'Documentary for General release.
6. For My Future (Aap Ke Kal Ke Liye)	63.00	do-		-do-
7. Doshi Kaun .	436.16	Asian Films, 72-Janpath, New Delhi 110001.		'Documentary for release Delhi circuit.
8. Mahitichitra No. 354A	259.08	Asstt. Director of Information (Films), Govt. of Gujarat, Ramnord Research Labs., Ltd., 77-Dr. Annie Besant Road, Bombay-400018.	Director of Information Government of Gujarat Sachivalaya, Gandhinagar-382010	'News and Current Event for release in Gujarat circuit.
9. Pathadarshak (Revised)	350.52	do-	-do-	'Documentary' for genera release.
10. Uttar Pradesh Samachar-88	284.63	Dhirendra Pandey, Producer Films, Deptt. of Information and Public Relations, Government of U.P., Lucknow.		'News and Current Events' for release in Uttar Pradesh circuit.
11. Alokara Jatra (Colour)	569.36	Charn Mahanta, I.P.R.O., Assam State Electricity Board, Narangi, Gauhati-781026	M/s. Devjani Chaliha & Associates, P-21 Golf Club Road, Calcutta-700033.	'Documentary' for general release.
12. Bipad: Savadhan (Colour)	437.69	-do-	-do-	'Documentary' for general release.
13. This Land is Mine (Colour)	338.33	Hari S. Dasgupta Production, c/o Datta Patankar 611 Mayur, S.V. Patel Road, Borivali West, Bombay-400092.		'Documentary for general release.
14. Maharashtra News No. 368	295.00	Directorate General of Information and Public Relations, Government of Maharashtra, Film Centre 68-Tardeo Road, Bombay-34.		'News and Current Events' for release in Maharashtra circuit.
15. Varta Tarangini No. 17	281.80	Andhra Pradesh State Film Development Corp. Ltd., Gruhakalpa, M.J. Road, Hyderabad-1		'News and current Events' for release in Andhra Pradesh circuit.
16. Varta Tarangini No. 18	266.60	-do-		-do-
17. Dattu	274.5	Directorate General of Information and Public Relations, Government of Maharashtra, Film Centre, 68-Tardeo Road, Bombay-34.		'Documentary' for genera release.
18. Mahiti Chitra No. 355	289.56	Asstt. Director of Inf. (Films) Govt. of Gujarat Ramnord Labs., Ltd., 77-Dr. Annie Besant Road, Bombay-18.	Director of Information (Films), Govt. of Gujarat Sachivalaya, Gandhinagar	'News and Current Event, for release in Gujarat circuit.
19. The Kosbad Experience	467.00	K.K. Kapil, 133-Juhu Prabhat, New D.N. Nagar, Bombay-400058.		'Documentary' for genera release.

1	2	3	4	5	6
0.	Yaad Karo Qurbani the Kar Maze Julati)	310.00	Directorate Genl. of Information Public Relations, Government of Maharashtra, Film Centre 68-Tardeo Road, Bombay-34.		'Documentary' for release in the Maharashtra circuit.
	The Chemistry of India (Col).	305.00	M/s. Revelation, E-20, Everest Tardeo, Bombay-400034.		'Documentary' for general release.
22.	The Choice Is Yours (Faisla Aap par)	498.98	Dhiraj Chauhan, Dhiraj Productions, Smruti Building, Flat No. 4, 1st Floor 4-E Jay Bharat Khar (West), Bombay-52.		'Documentary' for general release.
23.	Madhya Pradesh Samachar Darshan-33	288.04	Asstt. Director Information & Publicity Madhya Pradesh Director, Information & Publicity, Madhya Pradesh.		'News and current Events' for release in Madhya Pradesh circuit.
24.	For Peace & Amity (Colour)	558.00	Films Divisions Government of India 24-Peddar Road, Bombay-400006		'Documentary' for general release.
25.	Acceptance	370	M/s. View Point A-5 Ravi Darshan Carter Road, Bombay-50.	Sunil Ghosh M/s. View Point A-5 Ravi Darshan Carter Rd., Bombay-50.	'Documentary' for general release
26.	Electrical Hazards	384	M.S. Rajan 32, Aaditya Bldg., 501, Rasta Peth Pune-411 011.	M.S. Rajan 32, Aaditya Bldg. Pune-411011.	-do-
27.	Mechanical Hazard	384	-do-	-do-	-do-
28.	Ek Chota Sa Ghar Hota	250	Rishi Films, 11, Kshitij Adarsh Society, Ramachandra Lane, Malad (W), Bombay-64.		-do-
29.	Old Coal is the Energy Now.	240.79	Coal India Limited, No. 10, Netaji Subhash Road, Calcutta.	Film Media, 47, Laxmi Insurance Bldg., Sir P.M. Road, Bombay-1	do-
30.	Mahiti Chitra No. 365	228.60	Asstt. Director of Information, Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratories Ltd., 77, Dr. Annie Besant Road, Bombay-18.		'News & Current Events' (Release in Gujarat Circuit)
31.	Suraj Ekela Chalta Hai	292.30	Directorate General of Information & Public Relations, Govt. of Maharashtra, Films Centre, 68, Tardeo Road, Bombay-34.		'Documentary' for General Release.
32.	Folk Drama of Gujarat 'Bhavai'	480.06	Asstt. Director of Information (Films) Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratories Ltd., 77, Dr. A.R. Road Bombay 18.		-do-
33.	Chandubhaini Chinto	184.40	-do-		-do

1	2	3	4	5	6
34.	Chemical Hazards	472.44	M.S. Rajan, 32, Aaditya Bldg. 501, Rasta Peth, Pune-411011.		'Documentary' General Release
35.	Good House Keeping	505.42	-do-		-do-
36.	Uttar Pradesh Samachar-94	276.15	Dhirendra Pande (Producer Newsreel), Directorate of Information and Public Relation U.P., Lucknow.		'New and Current Events' Release in U.P. circuit
37.	Madhya Pradesh Samachar Darshan-36	291.63	Director of Information & Publicity, Govt. of M.P., Bhopal.		'News and Current Events' Release in M.P. circuit
38.	Himachal Ke Lok Nritya	475.49	Director of Public Relation, Himachal Pradesh Simla.		'Documentary' Release only in Himachal Pradesh circuit.
39.	Neo-Youth Film Festival	302	Films Division, Govt. of India 24, Peddar Road, Bombay-400026.		News and Current Events for General Release.
40.	Sudharel Kheti Padhati	297	Asst. Director of Information (Films), Govt. of Gujarat, Ramnord Research Lab. 77, Dr. A.B. Road, Bombay-18.	Director of Information, Govt. of Gujarat Sachivalaya, Block No. 7 Gandhinagar-382010.	Documentary' Release in Gujarat circuit.
41.	For You	297.18	Jagadish Banerjee 2, Himgiri, Peddar Road, Bombay.	Uma Banerjee 2, Bhaveshwar Terrace, 85, Dr. A.B. Road, Worli, Bombay.	Documentary for General Release.
42.	Varta Tarangini No. 22	200	A.P. State Film, Dev. Corpn. Ltd. Gruhakalpa, M.J. Road, Hyderabad-500001.		News and Current Events (Release in A.P. circuit)
43.	Mahiti Chitra No. 364	254.51	Asst. Director of Information Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratories Ltd., 77, Dr. A.B. Road Bombay 18.	Director of Information Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Block No. 7 Gandhinagar-382010	News and Gujarat Event' (Release in Gujarat circuit).
44.	Uttar Pradesh Samachar-93	266.70	Dhirendra Pande, Producer Newsreel, Directorate of Information & Public Relations U.P., Lucknow.		News and Current Events (Release in Uttar Pradesh Circuit).
45.	Plight of Telephone	228.60	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-400026.		Documentary General Release.
46.	King of the Jungle	85.344	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.		Documentary General, Release.
47.	Spring in Sikkim	297.00	-do-		-do-
48.	New District Sindhudurg	161	Directorate General of Information & Public Relations Govt. of Maharashtra, Filmcenter, 68, Tardeo Road, Bombay-400 034	Govt. of Maharshtra.	Documentary Release in Maharashtra circuit.
49.	Chalto Rahe Je	356.92	Asst. Director of Information Govt. of Gujarat Remnord R. Lab. 77, A.B. Road, Worli, Bombay-400 018.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya Block No. 7 Gandhinagar-382010	Documentary General Release.

1	2	3	4	5	6
50.	Uttar Pradesh Samachar-92	288.95	Dhirendra Pande, Producer Newsreel, Directorate of Inf. & Public Relations, Govt. of U.P. Lucknow.		News and Current Events (Release in U.P. circuit),
51.	Mahitichitra No. 363	262.13	Asstt. Director of Inf. Govt. of Gujarat Ramnard Research Lab. Ltd., 77, Dr. A.B. Road, Worli, Bombay-400018.	Director of Information, Govt. of Gujarat Sachivalaya Block No. 7, Gandhinagar-382010.	News and Current Events (Release in Gujarat circuit)
52.	Sukhi Jeevan Ka Raaj (Colour)	285.30	M/s AMA Pvt. Ltd., Canada Building, Dr. D.N. Road, Bombay-1.		Documentary General Release.
53.	T.B. Control Campaign 1982	284.68	Bal. M. Joglekar Co-Producer, 7/6, Shivaji Nagar, Worli, Bombay-25.	R.D. Lele, Chief Physician Jaslok Hospital, Peddar Road, Bombay.	-do-
54.	Birendra Nath Sircar	531.31	Bhadresh Kumar Kalatmak, Old Mutual Bldg, III Floor, 23, A. Desh Marg, Bombay-23.		Documentary General Release.
55.	Primary Health Centre	163.30	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.		-do-
56.	Kal Aur Aaj (Colour) Cartoon	186.00	Miss Vimala Swaminathan 11, Ramsyam Nivas, S.D. Temple Road, Mahim, Bombay.		Documentary General Release.
57.	Kya Aap Jante Hai ?	297.18	H.T. Dave, Trustee, Akshar Bhavan, Swaminarayan Chowk, Dadar, Bombay-400014.	Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam, Sanstha, Shanibaug Road, Ahmedabad-380004.	Documentary Release in semi-Urban and Rural areas.
58.	Maharashtra News No. 372	274.00	Directorate Gen of Inf. & Pub. Relations, Govt. of Maharashtra, Film Center 68, Tardeo Road, Bombay-34.		News and Current Events (Release in Maharashtra circuit)
59.	Stress Ability (Colour)	304.80	Mohi-ud-Din Mirza Hillman Film, 4-F/2, Court Chambers, 35 New Marine, Lines, Bombay-20.	Hillman Film 4-F/2, Court Chambers, 35 New MarineLines, Bombay-20.	Documentary general Release.
60.	Bachaiye Bachaiye Bachaiye Urja	408.84	Ashok Sagar, P.O. Box 5543 Bombay-400 014.		-do-
61.	A Programme for Progress	270.00	Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.		-do-
62.	Uttar Pradesh Samachar 91	292.61	Dhirendra Pande Producer, Newsreels C/o. Bombay Film Lab, Ltd., 149, S.K. Bole Road, Bombay-28.	Dhirendra Pande, Producer Newsreels Directorate of Information & Pub. Relations, Govt. of U.P., Lucknow.	News and Current Events (Release in U.P. circuit).
63.	Mahitichitra No. 362	259.08	Asst, Director of Information Govt. of Gujarat Ramnord Research Lab Ltd., 77, Dr. A.B. Road, Worli, Bombay-18.	Director of Information Government of Gujarat Sachivalaya.	News and Current events (Release in Gujarat Circuit)
64.	Shrivatsa (Shorter version)	351.00	Prakash Jha, Chitrapat, 3 Amer Cottage Marol, Andheri (E), Bombay-59.		Documentary General Release.
65.	Madhya Pradesh Samachar 34.	280.00	Asst. Director Information & Publicity, Govt. of M.P. C/o. Bombay Film Lab, Dadar, Bombay.	Director of Inf. & Publicity Govt. of M.P., Bhopal.	News and Current Events (Release in M.P. circuit)
66.	Madhya Pradesh Samachar No. 35	289.00	-do-	-do-	News and Current Events (Release in M.P. circuit) and for General release).
67.	I Think I Can If Only You Can	468.00	Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-400026.		Documentary for General release.

1	2	3	4	5	6
68.	Varta Tarangini No. 21	260.67	A.P. State Film Dev. Corpn Ltd., Gruhakalpa, M. J. Road, Hyderabad-500001.		News and Current Events (Release in A.P. State)
69.	Navi Kheti Paddati Dwara Smruddhi	297.18	D irector of Information Govt. of Gujarat Sachivalaya, Gandhinagar.		Documentary Release in Gujarat Circuit.
70.	And Then Man Created Gods And Demons in His Own Image	402.03	Azeez, Filmage, Ambalamokku, Trivandrum		Documentary General Release,
71.	Indian Telephones-100 Years Young	84.38	Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-400026.		-do-
72.	Mahitichitra No. 361	243.84	Asst. Director of Information Govt. of Gujarat. Ramnord Research Lab. Ltd, 77, Dr. A.B. Road, Worli, Bombay-400018.	Director of Information Government of Gujarat Sachivaleaya Gandhinagar-382010.	News and Current Events (Release in Gujarat Circuit).
73.	Yugdrusht Swami Sagahanand (Colour)	298.70	Director of Information Govt. of Gujarat, Sachivalaya Gandhinagar-382010.	-do-	Documentary General Release.
74.	World Cup Hockey-1982	292.60	Film Division, '24-Peddar Road, Bombay-400026.		-do-
75.	Gaoen Gaoen Banti Jwalai Jaon (Colour)	586.00	Charu Mahanta I.P.R.D. Assam State Electricity Board, Narangi, Gauhati-781026	M/s. Davjani Chaliha & Associates, P-21Golf Club Road, Calcutta-33.	Documentary Release in Assam Circuit.
76.	Sangeeta Ratna Dr. Mallikarjuna Mansoor	381.00	K.G. Shivayogi Photog rapher 39/40 Bhandari Complex, Sheshadri Road, Anand Rao Circle, Bangalore-560009	K.G. Shivayogi 39/40, Bhandari Complex, Shashddri Road, Anand Rao Circle, Bangalore-560009.	Documentary General Release.
77.	Abode of Gods (Colour)	400.00	C.F. Marconi, Anand Vihar-69 B. Desai Road, Bombay-26.		-do-
78.	After School What Next	335.44	Ravi Mehra, C/o Creative Youth 2o, Hari Market, Opp. Khar Rly. Station, Khar, Bombay-52.		Documentary General Release.
79.	Making a Fighter Pilot (Colour)	386.00	Films Division 24-Peddar Road, Bombay-26.	Films Division, 4-Tolstoy Marg, New Delhi.	-do-
80.	Rajmata Jijau 384th Janmotsave Sohala	188	Directorate General of Information & Public Relations, Govt. of Maharashtra, Film Centre, 68, Tardeo Road, Bombay-400 084.		Documentary Release in Maharashtra Circuit.
81.	Hijra Era Celebrations in India.	391	Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-26.	Films Division, 4-Tolstoy Marg, New Delhi.	Documentary General Release
82.	A Life of Honour	500	-do-	Films Division, 24-Peddar Road, Bombay.	-do-
83.	Second Honeymoon	84,430	-do-	-do-	-do-
84.	Role of Telecommunication	270	-do-	-do-	-do-
85.	C.V. Raman	500	-do-	-do-	-do-
86.	Gujaratmaa Adi-Jatino Vikas	428.91	Asst. Director of Information Govt. of Gujarat, Rammord R. Lab., Worli Bomaby-18.	Director of Information Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Gandihinagar-382010.	'Decumentary' Release in Gujarat Circuit.
87.	Jal Manthan	528.52	-do-	-do-	-do-
88.	Uttar Pradesh Samachar-95	284.99	A. David C/o Bombay Film Lab(P) Ltd., 149, S.K. Bole Road, Bombay-400028	Director of Information Govt. of U.P. Lucknow.	News and Current Events for release in U.P., Circuit.
89.	Uttar Pradesh Samachar-96	276.15	Dhirendra Pande, Directorate of Information & Public Relations, U.P., Lucknow.		News and Current Events for release in U.P. Circuit.
90.	The Family	250	Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-26		'Documentary' for General Release.

1	2	3	4	5	6
91.	Daman Ganga	366	Asst. Director of Information Govt. of Gujarat Ramnord Lab., Worli, Bombay.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Gandhinagar, Gujarat.	'Documentary' Release in Gujarat circuit.
92.	Bombay Port	472.440	Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-400026.		'Documentary' for general release.
93.	Coal to Urea	268.22	-do-		-do-
94.	Sexually Transmitted Diseases	492.00	-do-		'Documentary' with certificate for general release
95.	Varta Tarangini No. 23	275.91	A.P. State Film Dev. Corpn. Ltd. "Gruhakalpa", M.J. Road, Hyderabad-500001.		News and Current Events. Release in A.P. circuit
96.	So Far So Near	396.5	V.S. Enterprises, 11, Ramashyam Nivas, Sitha Devi Temple Road, Mahim, Bombay-400014.	Miss Vimla Swami Nathan	'Documentary' General Release

[File No. 315/1/80-F (P)]
SUKUMAR MANDAL, Desk Officer

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 मई, 1982

का० आ० 2657.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में बी०सी०जी०वेक्सिन लेबोरेट्री, मद्रास के प्रबन्धतंत्र संबद्ध से एक औद्योगिक विवाद नियोजकों बी०सी० जी० कर्मचारी संघ और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निदेशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उप धारा (1) के (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी. सुदरसनम डानियल होंगे जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या बी०सी०जी० वेक्सिन लेबोरेट्री, गिण्डी, मद्रास के प्रबन्धतंत्र की श्री एस०जी० जयरामन प्रयोगशाला सहायक को उसके वेतनमान में दो प्रक्रम को करने का दंड देने की कार्यवाही न्यायोचित थी और नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एम-42012/45/81-डी-II-बी]
एस०एस० पराशर, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 13th May, 1982

S.O. 2657.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the BCG Vaccine Laboratory, Madras and BCG Vaccine Employees Union and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Sundarsanam Daniel shall be the Presiding Officer with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the employers of BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Madras were justified in punishing Shri T. S. Jayaraman, Laboratory Assistant by reduction by two stages in his scale of pay and if not what relief is the workman entitled".

[No. L-42012(45)/81-D. II (B)]
S. S. PRASHER, Desk Officer

New Delhi, the 7th July, 1982

S.O. 2658.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Moonidih Project of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Moonidih, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 29th June, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference U/s. 10(1)(d) of I.D. Act, 1947

Reference No. 21 of 1981

(Ministry's Order No. L-20012/288/80-D.III(A)

Dt. 5-5-1981)

PARTIES :

Employer in relation to the management of Moonidih Project of Messrs Bharat Cooking Coal Limited, Post Office Moonidih, District Dhanbad

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice B. K Ray (Retd.), Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri R. S. Murthy, Advocate.

For the Workmen—Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, dated the 23rd June, 1982

AWARD

This reference has to be answered against the Union. The dispute relating to the case is as to whether the action of the management of Moonidih Project of Messrs Bharat Coking Coal Limited in not giving promotion to the five concerned workmen, all L.D.Cs, to the posts of U.D.C. as per Cadre Scheme of the erstwhile N.C.D.C. is justified. Although the language of the reference places the initial onus on the management in course of hearing of the case both parties having led evidence in support of their respective cases, the question of onus is no longer significant and the case has to be decided on the evidence led by the parties.

2. The union as per its pleading and evidence led by it bases its case mainly on three points. The first point is that the concerned workmen were originally L.D.Cs. in Moonidih Project when the said project was under N.C.D.C. The management of this project was transferred to B.C.C.L. in May 1973 a fact not disputed by the parties. Thereafter the ownership of the Project vested in B.C.C.L. in November, 1975. Before transfer of management of the project to B.C.C.L. there was prevailing a cadre scheme in N.C.D.C. according to which L.D.Cs. according to their seniority and suitability alone used to be promoted to the rank of U.D.Cs. This scheme in force in N.C.D.C. applied to the concerned workmen after they were transferred to B.C.C.L. when the management of the project was transferred. According to the said scheme prevailing in N.C.D.C. Time Keepers and Miners Time Keepers were not being considered for promotion alongwith the L.D.Cs to the next higher rank because the cadre scheme for L.D.Cs and U.D.Cs was separate from the cadre scheme of Time Keepers. Accordingly Time Keepers used to be promoted to higher rank according to their scheme provided for by the management. The aforesaid schemes for promotion of L.D.Cs and Time Keepers prevalent in the project under N.C.D.C continued to be in force after the administration of the project was transferred to B.C.C.L. and also after ownership of the project vested in B.C.C.L. The concerned workmen belong to B.C.K.U the sponsoring union where as the Time Keepers belong to recognised union of the management, namely, R.C.M.S. The management of B.C.C.L. always favours R.C.M.S. its recognised union. So in order to deprive the concerned workmen who belonged to B.C.K.U. of their chances for promotion under the old prevailing scheme mentioned above the management introduced a new promotional policy in 1978, according to which Time Keepers and L.D.Cs were to be jointly considered for promotion to the next higher rank and in pursuance to the said policy did not promote the concerned workmen while promoting some other Time Keepers. The new promotional policy introduced by the management can not be made applicable to the concerned workmen as they being old employees under N.C.D.C. are to be governed by the old promotional scheme prevalent under N.C.D.C. at theh time when the project was transferred to B.C.C.L. The application of new promotional scheme to the concerned workmen is therefore not justified.

3. The second point raised by the union is that the introduction of the new promotional policy by B.C.C.L. in 1978 amounts to change in condition of service and that such a policy having been introduced and enforced against the concerned workmen without due compliance with the provision to Sec. 9A of I.D. Act the action of the management must be held to be illegal and hence not justified.

4. The third point of the union is that B.C.C.L. which always favours its recognised union R.C.M.S. being hostile to members of B.C.K.U. in order to victimise its members including the concerned workmen invented a new promotional policy in 1978 thereby making chances of promotion for the concerned workmen bleak. This according to the union is an act of victimisation on the part of the management and so has to nullified.

5. Of the three points raised by the union I shall take up the third point first Regarding the point I am constrained to say that victimisation although pleaded by the union has not been established at all. To support its case of victimisation the union has only examined one of the five concerned workmen. This witness's solitary assertion in his evidence without being supported by any document or by evidence of any other dis-interested witness does not inspire confidence. My conclusion is very much strengthened from the admitted position which has been revealed in course of hearing of the case that three of the five concerned workmen have already been promoted in the meanwhile. It is argued by Mr. D. Mukherjee for the union that these promotions being during the pendency of the reference cannot disprove the union's case of victimisation. I do not accept this contention because if the management actually victimised five concerned workmen there is no reason why three of them would be promoted during the pendency of the the reference when the question of victimisation is pending decision before the Tribunal. Nothing has been shown that the management is hostile to B.C.K.U. Only a bold assertion of one of the concerned workman WW-1 cannot make out a case of victimisation for the union. So the point regarding victimisation raised by the union fails.

6. Ragarding the second point of the union it is urged by Mr. Mukherjee that the introduction of the new promotional scheme by B.C.C.L. in 1978 amounts to change in condition of service and that the change having been made without compliance with provision of Sec. 9A of the Act the promotion held in pursuance of new scheme must be struck down as illegal. Mr. Mukherjee in support of the point refers to me Paras 7, 8 and 9 of the Fourth Schedule of the Act. The heading of the schedule is "Conditions of service for change of which notice is to be given". Para 7 of the schedule refers to 'Classification by grades'. It means that where classification by grade is made during employment a notice under Sec. 9A must have to be issued before such classification takes effect. In the present case there has been no fresh classification. Under Wage Board recommendations there is no post as L.D.C. and U.D.C. It is admitted that the scale of pay for an L.D.C. is the same as that of a Time Keeper and both of them belong to Grade II under Wage Board Classification. There has been no change in this classification by the management. Formerly before introduction of the new promotional scheme the management was promoting L.D.Cs according to their own separate cadre and so also was the case with Time Keepers. Both Time Keepers and L.D.Cs who already belonged to Grade II are now under the new scheme considered together for promotion to the next higher grade i.e. Grade I. It is not disputed that the scale of pay of an U.D.C. is the same as the scale of pay of Grade I Clerk. Only because under the new promotional scheme Time Keepers and L.D.Cs who belong to Grade II are considered for promotion to the next higher Grade jointly it cannot be said that there is any new classification. So para 7 of the Fourth schedule has no application. Para 8 of the schedule says about withdrawal of any customary concession or privilege or change in usage. The promotional scheme which was applicable to the concerned workmen before introduction of the new promotional scheme can by no stretch of imagination be said to be a customary concession or a privilege or an usage. Where the management stops free supply of coal for consumption for its workmen a practice which was obtaining for long time, it may be said that the management has withdrawn a customary concession or privilege. By introduction of the new scheme promotional avenue for the L.D.Cs is not stopped. So it cannot be said to be withdrawal of any concession or privilege. For these reasons I do not accept the contention of Mr. Mukherjee that introduction of new promotional policy amounts to withdrawal of any concession or privilege or usage. Para 9 of the schedule deals with introduction of new rules of discipline or alteration of existing rules. In the context in which the words "existing rules"

have been used in this para they mean only rules of discipline. Change of a promotional scheme cannot come within the purview of this para. The result therefore is that the introduction of new promotion scheme by the management does not amount to a change in condition of service and hence Sec. 9A of Act is not required to be complied with. The second point raised by the union therefore fails.

7. Coming to the first point the position is admitted that while the concerned workmen were under NCDC and were working in Moonidih Project they were being governed by a scheme of N.C.D.C. according to which L.D.Cs were alone considered for promotion to the posts of U.D.Cs. It is also not disputed that an L.D.C. post is in Grade II and an U.D.C. post is in Grade I according to gradation given in the Wage Board recommendations of 1967 which parties admit have been implemented since 15-8-67. After the Moonidih Project was transferred to B.C.C.L. and before B.C.C.L framed its new promotional scheme it is also not disputed that promotions of L.D.Cs used to be made by B.C.C.L. as per the old scheme prevailant in N.C.D.C. Therefore in the year 1976 before the new promotional scheme was framed by B.C.C.L. a seniority list was prepared in which seniority of L.D.Cs and seniority of Time Keepers were separately shown. This document is Ext. W-4. Much emphasise has been made on this document by Mr. D. Mukherjee who argues that even after 1967 L.D.Cs, were being separately considered for promotion as belonging to a separate cadre. I do not understand how this document can be of any assistance to the union if it is held that the management had a right to substitute its old promotional scheme by a new one and in exercise of that right framed a new scheme introduced it and implemented the same. It is the case of the management that in the year 1978 B.C.C.L. after consultation with all the trade unions in a Consultative Committee framed a new promotional scheme, Ext. M-1 under which Time Keepers and L.D.Cs both belonging to Clerical Grade II under Wage Board recommendation are to be jointly considered for promotion to the rank of clerical Grade I. The top portion of Ext. M-1 clearly shows that the scheme was framed after consultation with different trade unions. The endorsement at the bottom of Ext. M-1 shows that copies of the scheme were sent to all members of the Consultative Committee. It is admitted by WW-1 one of the concerned workmen that there was a Consultative Committee in which different trade unions and management were represented. The witness while asserting that B.C.K.U is a very big and old trade union says that the said union was not represented in the committee. This evidence is contradicted by MW-1. If really that was so as deposed by WW-1 one would normally expect that the said union would have raised a protest before the management immediately after the new policy was introduced. There is nothing to show if any such protest was even lodged by the union. So I do not accept the evidence of WW-1 that B.C.K.U. was not represented in the Consultative Committee and I hold that the new promotional scheme Ext. M-1 was introduced by the management after consultation with all the trade unions including B.C.K.U. in a Consultative Committee. That apart the new promotional scheme Ext. M-1 does not take away any of the rights of the concerned workmen to be considered for promotion. Under the new promotional scheme only some other workers, namely, Time Keepers had to be considered alongwith L.D.Cs for promotion to the higher rank. It may be said that after the introduction of the new scheme the chance for promotion for the L.D.Cs became less. But since this does not take away the right of the concerned workmen to be considered for promotion and since the management has always the right to change its promotional scheme subject to the right of the concerned workmen to be considered for promotion no fault can be found with the management particularly when the new scheme was introduced after consulting all the trade unions including B.C.K.U. The case can be looked from another angle Under Wage Board recommendation there are three grades of classifications, namely Gr. I, Gr. II and Gr. III for clerks. It is admitted that Time Keepers and L.D.Cs belong to Gr. II and on their promotion to Gr. I they would be entitled to the scale of pay admissible to Gr. I clerk under Wage Board recommendation. Formerly under N.C.D.C. L.D.Cs used to be treated as a separate class although they belonged to Gr. II and used to be promoted according to their seniority to Gr. I. After B.C.C.L. took over the Moonidih Project it thought of abolishing distinctions between clerks belonging to Gr. II whose scale of pay was same and of considering all of them in a lot for promotion to clerical Gr. I. Before finalising management consulted with different trade unions and after consultation framed the new promotional scheme Ext. M-1 copies of which were sent to all the members of the Consultative Committee. If the trade unions had any grievance at that time they could have agitated the matter. But nothing was done. The new scheme only abolished the distinction between different groups of clerks in one grade. That being so it is not possible to accept the union's case that there was any malafide in the action of the management in introducing and implementing the new promotion scheme Ext. M-1. A promotional scheme as has been stated is always open to be changed from time to time by the management according to exigency of situation. Time Keepers are otherwise known as Asstt. Clerk-cum-Register Keepers. So they together with L.D.Cs have been put under grade II by the Wage Board. Such being the position the management's action in putting all the workers in one grade together for their consideration for promotion to the next higher rank cannot be objected.

8. Lastly Mr. D. Mukherjee argues that even assuming that the management was justified in changing over to new promotional scheme and in implementing the same it was incumbant on the management before implementing the scheme to prepare a combined seniority list of the Time Keepers and L.D.Cs and to serve copy of such list on all the workmen concerned before promotion was made on the basis of the said list. Mr. D. Mukherjee says that such a list was neither prepared nor notified and thus the concerned workmen have been greatly prejudiced. This point has not been specifically pleaded. It is only at the evidence stage Mr. Mukherjee in course of cross-examining MW-1 put a question as to whether a combined seniority list had been prepared before implementing Ext. M-1. To this question MW-1 while answering in affirmative admitted that the list was hung up in the Notice Board although copies thereof were not served on individual workers. As against this evidence WW-1 the only witness for the union asserts that no such list was even prepared and hung up on the Notice Board. The evidence on both sides is oath against oath. In view of the fact that no specific plea was raised by the union in its pleading and that the action of the management in not promoting the concerned workman was not challenged on account of the fact that no combined seniority list was ever published, I take no notice of the point raised by Mr. Mukherjee. The union never raised the point in the pleading and did not challenge the action of the management on the ground that it did not publish a seniority list. The management therefore was not put to notice. If the point now urged would have been taken by the union in its pleading the management would have taken steps to disprove the point taken by the union. To accept the point now raised by Mr. Mukherjee without any basis in the pleading will amount to doing injustice to the management.

9. For the reasons given above I do not find any merit in the reference which is therefore answered against the union In the circumstances there will be no order for cost.

B. K. RAY, Presiding Officer

[No. L-20012(283)/80 D III(A)]

New Delhi, the 9th July, 1982

S.O. 2659.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th June, 1982.

BEFORE JUSTICE SHRI S. R. VYAS (RETD.)
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(54)/1981

PARTIES :

Employer in relation to the management of Punjab National Bank Bhopal and their workman Shri K. S. Sen, Peon-cum-Chowkidar represented through the General Secretary, The Association of Punjab

National Bank Employees (M.P.) Central Office, 30 Bakshi Gali, Indore (M.P.)

APPEARANCES :

For Workman—Shri N K. Sharma, General Secretary of the Association.

For Management—Shri R. P. Raizada, Regional Manager of the Bank.

INDUSTRY : Bank DISTRICT : Bhopal (M.P.)

AWARD

Dated : June 21, 1982

By Notification No. L-12012/68/81-D. II(A) Dated 18th December, 1981, Government of India in the Ministry of Labour has referred the following dispute to this Tribunal, for adjudication :—

"Whether the action of the management of Punjab National Bank in relation to their Basai Branch, District Datia in not paying Daftri allowance to Shri K. S. Sen, Peon-cum-Chowkidar of Punjab National Bank Basai Branch for the period from October, 1977 to May, 1980 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. From the order of reference it appears that the dispute between the parties was with regard to the payment of Daftri Allowance to the workman, Shri K. S. Sen, Peon-cum-Chowkidar of the Basai Branch District Datia for the period from October, 1977 to May, 1980.

3. After notices were issued the workman submitted his statement of demands and claimed the aforesaid allowance which was not paid to him by the management. The management before filing the statement of demands requested for a short adjournment on the ground that there was a possibility of a mutually agreed settlement being filed before this Tribunal. Accordingly on 29-5-1982 both the parties filed a written settlement before this Tribunal according to which a lump sum of Rs. 1051 was agreed to be paid to and received by the workman towards the Daftri Allowance excluding Chowkidar's allowance already paid to him. This payment according to the settlement must be made within a month from the date of the award. Union also agreed not to refer to the settlement as a precedent for any other case. The terms and conditions of the settlement were read over to the representatives of both the parties who were signatories to the settlement. They expressed that such a settlement has been arrived at by mutual agreement and was voluntary.

4. As already stated above, the claim of the workman was for the payment of the Daftri Allowance for the aforesaid period. The management of the Bank instead of contesting the claim on merits arrived at a settlement with the workman and agreed to pay a lump sum of Rs. 1051/- as Daftri Allowance to the workman. The workman has agreed to receive this amount in full and final satisfaction of his claim from the management.

5. The settlement appears to be fair and reasonable settlement of the claim made by the workman. This amount of Rs. 1051/- is being paid to him in addition to the allowance of Chowkidar which has been separately paid to him for the aforesaid period. I accordingly find no reason, not to pass an award on the settlement. Accordingly, acting on the mutually agreed settlement filed by the parties the following award is passed in this case :—

(i) That the Punjab National Bank, Basai Branch, District Datia shall pay Rs. 1051 to the workman, Shri K. S. Sen as Daftri Allowance within one month from the date of the publication of this award. This payment shall be in addition to the Chowkidar's allowance already paid to the workman from 29-10-1977 to 10-6-1980. The said payment of Rs. 1051 - shall be in full and final settlement of the claim made by the workman in this reference.

(ii) The workman's Union shall not quote the settlement as a precedent in any other case.

(iii) In view of the settlement arrived at between the parties both the parties shall bear their own costs as incurred in these proceedings.

S. R. VYAS, Presiding Officer

[No. L-12011(68)/81-D.II(A)]

S.O. 2660—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore, in the industrial dispute between the employment in relation to the management of Canara Bank and their workman, which was received by the Central Government on the 26th June, 1982.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN KARNATAKA BANGALORE

Dated this 18th day of June, 1982

Shri V. H. Upadhyaya, B.A., LL.B.—Presiding Officer.

Central Ref. No. 5/81

I Party.	II Party.
Sri M. C. Kanakeri,	The Deputy General Manager
C/o. The General Secretary,	Canara Bank, Head Office,
Dharwad Dist.	Bangalore-560002,
Bank Employees ASSN.	Karnataka.
No. 9, Co-operation Bldg.	
Broadway, Hubli.	

APPEARANCE

For the I party.—Sri M. Rama Rao, General Secretary, Dharwad District Bank Employees' Assn. Hubli-580020.

For the II Party.—Sri Urval N. Ramanand, Advocate, Bangalore.

AWARD

Government Order No. L-12012/35/80-D. II. A. Dated 20th March, 1981

The Government of India has made a reference of the dispute between the parties for adjudication on the following points.

"Whether the action of the management of Canara Bank, Head Office, Bangalore in terminating the services of Shri M. C. Kanakeri, Messenger with effect from 7-11-78 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?".

2. The parties submitted their statements. At the time of the enquiry they filed a Joint Memo of settlement, As the same is just and proper it is accepted and an Award is passed in terms of the settlement. No costs.

Sd/-

illegible

Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bangalore.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, HUBLI CAMP, HUBLI.

Cent. Ref. No. 5 of 1981

BETWEEN :

M. C. KANAKERI FIRST PARTY

AND

DEPUTY GENERAL MANAGER
CANARA BANK SECOND PARTY

The parties above named beg to file the following joint memo :

1. The Second Party hereby agrees to absorb the First Party in the services of the Bank as Sub-Staff (Peon) with prospective effect within one month from the date hereof.

2. The Second Party hereby agrees that the First Party will be taken in the services of the Bank in any one of the branches in Dharwar District, with the usual probationery period.

3. The First Party hereby gives up all his claims against the Second Party including any back wages or other benefits and hereby declares that he has no claim whatsoever against it until todate.

4. The parties pray for orders accordingly.

Authorised Representative of the First Party.—First Party
Advocate for II Party.—Second Party Hubli.

18-6-1982.

Sd. Illegible
Presiding Officer

[No L-12012 (35)/80-D. II (A)]

S.O. 2661.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of United Western Bank Limited, Satara and their workman, which was received by the Central Government on the 29th June, 1982.

BEFORE JUSTICE SHRI S. R. VYAS (RETD.) PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.).

Case No. CGIT/LC(R)(44)/1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of United Western Bank Ltd. and their workman Shri R. S. Kulkarni represented through the General Secretary, M. P. Bank Karamchari Sangh, 30, Bakshi Gali, Indore (M.P.).

APPEARANCES :

For Workman.—Shri M. L. Sabharwal, General Secretary of the Union.

For Management.—Shri K. K. Kelkar, Manager.

INDUSTRY : Bank DISTRICT : Indore (M. P.)

AWARD

Dated June, 1982

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour for adjudication of the following dispute by this Tribunal vide Notification No. L-12012/197/81-D. II(A) dated 17th November, 1981 :—

"Whether the action of the management of United Western Bank Ltd., Satara in relation to their Indore Branch in not promoting Shri R. S. Kulkarni, Clerk to the post of Head Clerk is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?".

2. From the statements of demands by the parties it appears that the dispute raised by the workman, Shri R. S. Kulkarni, was about the denial of his promotion as a Head Clerk and payment of pay and allowances admissible for that post.

3. It was contended by the workman that both on the ground of seniority and merit he was entitled to be promoted.

The management, however, contended that the demand raised by the workman and the union representing him was not justified; that neither under the Bipartite Settlement nor under Sastry Award the workman was entitled to the claim made by him; and that promotion claimed by the workman was not due to him.

4. However, before the stage of settlement of issues could be reached both the parties indicated their inclination to enter into discussions for a mutual settlement. Finally on 24-5-1982 the parties submitted a joint application and stated that as a result of negotiations which took place between the parties the workman Shri R. S. Kulkarni has been appointed as a Head Clerk in the Fort Branch of the Bank at Bombay and he has commenced working from 21-5-1982 and that the special allowance of Rs. 152 p.m. has been and is being paid from 1-1-1982. The parties accordingly prayed that an award be passed in terms of the aforesaid settlement.

5. As already stated above, the claim of the workman was for promotion to the post of Head Clerk and also for payment of special allowance. Both these demands have been conceded by the management and with effect from 21-5-1982 the workman has been promoted and posted as a Head Clerk in the Fort Branch of the Bank at Bombay. The workman has also been paid the special allowance @ Rs. 152 p.m. from 1-1-1982. It is also agreed between the parties that for all practical purposes the workman shall be deemed to have been promoted and posted as a Head Clerk with effect from 1-1-1982 with all consequential benefits.

6. The terms and conditions of the settlement were read over to both the parties/representatives and they agreed to have arrived at a settlement voluntarily. The settlement appears to be just, fair and is to the satisfaction of the workman. No element of undue influence etc. appears to be present in arriving at a settlement. I accordingly accept the settlement and pass the following award on the dispute referred to this Tribunal for adjudication :—

(1) That Shri R. S. Kulkarni shall be appointed (In fact he has already been appointed from 21-5-82) as a Head Clerk at the Fort Branch of the United Western Bank Ltd. Satara.

(2) That Shri R. S. Kulkarni shall be paid Head Clerk's Special Allowance @ Rs. 152 p.m. from 1-1-1982.

(3) That for all practical purposes 1-1-1982 shall be treated as the date of his promotion and posting with all consequential benefits.

In view of the mutual settlement between the parties, I direct both the parties to bear their own costs as incurred in these proceedings.

S. R. VYAS, Presiding Officer.
[No. L-12012/197/81-DII(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 18 मई, 1982

का० आ० 2662—इस उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद श्री भगवान दास जोहरी, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के समक्ष लंबित पड़ा है ।

और उक्त श्री भगवान दास जोहरी की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं रही है ।

अतः केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 7क

के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री राम राज लाल गुप्ता होंगे और उनका मुख्यालय जयपुर में होगा तथा उक्त श्री भगवान दास जोहरी पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के समक्ष लंबित पड़े उक्त विवादों से सम्बद्ध कार्यवाही को वापिस लेती है और उपर्युक्त विवादों को श्री राम राज लाल गुप्ता पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, जयपुर को इस निदेश के साथ स्थानान्तरित करती है कि उक्त अधिकरण उस पर आगे कार्यवाही उसी प्रकम से करेगा, जिसपर वह उसे स्थानान्तरित की जाए और विधि के अनुसार उसका निपटान करेगा ।

अनुसूची

क्रम संख्या	आदेश की संख्या और तारीख	पक्षकारों के नाम
1	2	3
1	एल-41011(4)/81-डी II तारीख 8 जुलाई, 1981	प० रेल का प्रबन्धतंत्र और उनके कर्मचारी
2	एल-12012/273/80-डी II ए तारीख 30 जुलाई, 1981	बीकानेर और जयपुर स्टेट का प्रबन्धतंत्र और कर्मचारी
3	एल-42012/61/80-डी II बी तारीख 30 जुलाई 1981	हेवी वाटर प्रोजेक्ट अणुशक्ति का प्रबंधतंत्र और उसके कर्मचारी
4.	एल-12011/10/80-डी II तारीख 30 जुलाई, 1981	न्यू बैंक आफ इंडिया और उसके कर्मचारी
5	एल-12012/144/79-डी.II ए तारीख 30 जुलाई 1981	पंजाब नेशनल बैंक और उसके कर्मचारी

[सं० एल-11025/1/82-डी 4 डी]

ORDER

New Delhi, the 18th May, 1982

S. O. 2662.—Whereas the industrial disputes specified in the Schedule hereto annexed are pending before Shri Bhagwan Das Johri, the Presiding Officer, Industrial Tribunal, Jaipur.

And whereas the services of Shri Bhagwan Das Johri are no longer available;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A read with sub-section (1) of the section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal, the Presiding Officer of which shall be Shri Ram Raj Lal Gupta with headquarters at Jaipur, and withdraws the proceedings in relation to the said disputes pending before the said Shri Bhagwan Das Johri, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Jaipur and transfers the same to Shri Ram Raj Lal Gupta, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Jaipur, with the direction that the said Tribunal shall proceed with the proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Sl. No.	Number & Date of the Order	Name of the Parties
1	2	3
(1)	L-41011(4)/81-D.II B dated 8th July, 1981,	The Management of Western Railway and their Workmen.
(2)	L-12012/273/80-D.II A dated 30th July, 1981.	The Management of State Bank of Bikaner & Jaipur, and their Workmen.
(3)	L-42012(61)/80-D.II B dated 30th July, 1981	The Management of Heavy Water Project, Anushakti and their Workmen.
(4)	L-12011/10/80-D.II.A dated 30th July, 1981.	The New Bank of India and their Workmen.
(5)	L-12012/144/79-D.II.A dated 30th July, 1981.	The Punjab National Bank and their Workmen.

[No. S-11025(1)/82-D.IV(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1982

का० आ० 2663—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स सिंगरेनी कोलियरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ।,

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी० प्रसाद राव होंगे जिनका मुख्यालय हैदराबाद होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स सिंगरेनी कोलियरी कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र की 18 एम डब्ल्यू पावर हाउस, रामागुन्डम में कार्यरत वाटर ट्रीटमेंट अटेन्डेंट को वर्ग-5 में न रखने की कार्रवाई न्यायोचित है, जैसी कि आन्ध्र प्रदेश कोलियरी मजदूर संघ द्वारा अपने पत्र संख्या ए पी सी. एम/जी ओ. के-251/81 तारीख 17 अप्रैल, 1981 द्वारा मांग की गई थी, यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ।

[सं० एल-21011/15/81-डी० 4 बी०)]

ORDER

New Delhi, the 23rd January, 1982

S.O. 2663.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of M/s. Singareni Collieries Co. Ltd., and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri B. Prasada Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the management of M/s. Singareni Collieries Co. Ltd. is justified in not placing the Water Treatment Attendants working at 18 M. W. Power House, Ramagundam in Cat. V, as demanded by Andhra Pradesh Colliery Mazdoor Sangh, in their letter No. APCM/GDK/251/81 dated the 17th April, 1981 ? If not, to what relief are the workmen entitled ?"

[L-21011(15)/81D. IV (B)]

आदेश

नई दिल्ली, 10 जून, 1981

का० आ० 2664—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से संबद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ।

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी० प्रसाद राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र की उनकी एलुरु शाखा के संबंध में श्री एम० वीर राजू, गोदाम चौकीदार की सेवाओं को 31-1-78 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ।

[सं० एल-12012/295/81-डी०-II (ए)]

ORDERS

New Delhi, the 10th June, 1982

S.O. 2664.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed :

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri B. Prasada Rao, shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of State Bank of India in relation to its Eluru Branch in terminating the services of Shri M. Veerraju, Godown Watchman with effect from 31-1-78 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

[No. L-12012/295/81-D.II(A)]

का० आ० 2665—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से संबद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी.एस. बेरोट होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया, स्थानीय मुख्यालय, भादरा, अहमदाबाद के प्रबंधतंत्र की लिपिकीय काडर में प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ 4-10-80 को परीक्षा देने से श्री एम०टी० पुनीता को रोकने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है और किस तारीख से ?

2 क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया, स्थानीय मुख्यालय, भादरा, अहमदाबाद के प्रबंधतंत्र की श्रीमती पी० अभयकुमार, पंच आपरेटर, की दो वेतन वृद्धियां रोकने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12011/17/82-डी II (ए०)]

S.O. 2665.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal which Shri G. S. Barot shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

(1) "Whether the action of the management of State Bank of India, Local Head Office, Bhadra Ahmedabad in debarring Shri M T. Punetha on 4-10-80 to appear in the test for the purpose of promotion to clerical cadre, is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled and from which date ?".

(2) Whether the action of the management of State Bank of India, Local Head Office Bhadra, Ahmedabad in stopping two increments of Mrs. P. Abhaykumar, Punch Operator, is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?".

[No. L-12011/17/82-D.II(A)]

का० आ० 2666—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में पंजाब नेशनल बैंक, जयपुर के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री रामराज लाल गुप्ता होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी संगम की पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कार्यालय बलोतरा के चपरासी, श्री पी० के० सैनी की सेवा को 10-1-78 से 22-10-79 तक अविच्छिन्न रखने और प्रथम छः मास की सेवा को परिवीक्षा अवधि के रूप में मानते हुए उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख से कर्मचारियों की सेवा को नियमित रूप से मानने की मांग न्यायोचित है ? यदि हां, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/268/81-डी II(ए०)]

S.O. 2666.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Punjab National Bank, Jaipur and their workman in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Ram Raj Lal Gupta shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal

SCHEDULE

"Whether the demand of All India Punjab National Bank Employees Association for continuity of service of Shri P. K. Saini, Peon, Punjab National Bank B/o. Balotra from 10-1-78 to 22-10-79 and for treating the service of the employees as regular from the date of his initial appointment taking the first six months services as probationery period, is justified ? If so, to what relief is the workman concerned entitled ?

[No. L-12012/268/81-D. II(A)]

का० आ० 2667.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स एस० सी० कं० लि०, रामागुन्डम डिविजन I के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (i) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एस० वी० रामना रेड्डी होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स सिंगरेनी कालरीज कम्पनी लि०, रामागुन्डम डिवीजन-I के प्रबन्धतंत्र की गोदावरी खानी नं० 3 आनति के सर्वश्री एम० मोहन राव, एम० सत्यामूर्ति तथा जी० गांधी, से ओवरमैन, को 5-6-77, 10-8-77 और 10-8-77 से जबसे उन्होंने खनन सरदार की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए कुछ समय तक लगातार शाटफायरर तथा खनन सरदारों के रूप में कार्य किया था, की बजाय 1-9-78, 1-10-78 और 1-10-78 से श्रेणी 'ग' में रखने की कार्यवाई न्यायोचित है। यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मचारी किस अनुतोष के हकदार हैं।

[सं० एल-21012/3/82-डी. 4(बी०)]

S.O. 2667.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of M/s. S.C. Co. Ltd. Ramagundem Division-1 and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri S. V. Ramana Reddy shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the management of M/s. Singareni Collieries Co. Ltd., Ramagundem Division-1 are justified in placing S/Shri M. Mohan Rao, M. Sastyamurthy and N. Gandhi, Overmen of Godavarikhani No. 3 incline in Grade-C w.e.f. 1-9-1978, 1-10-1978 and 1-12-1978 instead of from 5-6-77. 10-8-1977 and 10-8-1977, the dates on which they had passed Mining Sirdar's Examination and acted as Shotfirers and Mining Sirdars sometimes continuously for more than a year ? If not, to what relief the employees are entitled ?".

[No. L-21012(3)/82-D IV(B)]

New Delhi, the 7th July, 1982

S.O. 2668.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Patmohana Colliery of M/s. Eastern Coalfields Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th July, 1982.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : CALCUTTA.

Reference No. 100 of 1980

PARTIES :

Employers in relation to the management of Patmohana Colliery of Eastern Coalfields Limited.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice M. P. Singh, Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of Employers.—Shri P. C. Roy, Dy. Personnel Manager, Sitarampur Area.

On behalf of Workmen.—Sri Ashes Maiti, Secretary, Colliery Mazdoor Sabha.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Coal

AWARD

This reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 was sent by the Government of India, Ministry of Labour, vide Order No. L-19012(55)/80-D. IV(B) dated 15th December, 1980, to this Tribunal for adjudication of the following dispute existing between the management of Patmohana Colliery of M/s. Eastern Coalfields Limited and their workmen :

"Whether the action of the management of Patmohana Colliery of M/s. Eastern Coalfields Limited, Post Office Sitarampur, District Burdwan, is justified in stopping the work of the following female casual wagon loaders with effect from the dates mentioned against each ? If not, to what relief the workmen are entitled to and from what dates ?".

Name of the workmen	Date from which stopped
1. Smt. Joba Mejhan	April '77
2. Smt. Kelodi Mejhan	April '77
3. Smt. Bedani Mejhan	February '77
4. Smt. Dulali Mejhan	January '77
5.Smt. Sonmoni Mejhan	January '77
6. Smt. Somri Bhuiya	January '77
7. Smt. Tulsi Mejhan	January '77
8. Smt. Chumu Mejhan	January '77
9. Smt. Sonamoni Mejhan	14-5-77
10. Smt. Rebat Mejhan	January '77"

2. When the case was taken up to-day the parties submitted a joint petition of compromise with the prayer that an award be passed in terms of the said compromise petition. I have gone through the terms of compromise and I find the same to be fair and reasonable. I therefore accept the same.

3. I therefore pass an 'Award' in terms of the said petition of compromise which will form part of this award which is marked with the letter Annexure "A".

Dated, Calcutta,
The 28th June, 1982.

Sd/-
M. P. SINGH, Presiding Officer

ANNEXURE A"

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL

CALCUTTA.

Reference 100 of 1980

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Patmohana Colliery of E.C.L.

AND

Their Workmen represented by Colliery Mazdoor Sabha (AITUC) Asansol.

Both the parties abovenamed file joint petition of compromise as per terms mentioned hereunder.

That the Govt. of India Ministry of Labour Order No. L-19012(55) 180-D/IV(B) dated 15th December 1980 referred the alleged dispute for adjudication by the Hon'ble Tribunal.

That the above matter is pending before the Hon'ble Tribunal and the matter has not been heard as yet.

That the Colliery Mazdoor Sabha (AITUC) the concerned Union o fthe Workmen Smt. Jaba Mejhian and other nine have approached the Management for Settlement of the alleged dispute i.e. the termination of Smt. Jaba Mejhan and 9 others from service as Casual Wagon Loader.

That the matter has been discussed between the Management and the concerned Union and the Management without prejudice to its averments made before the Hon'ble Tribunal has agreed to settle the alleged dispute on the following terms and conditions.

1. S/Sreemati Jaba Mejhian, Kelodio Mejhian, Bedoni Mejhian, Dulali Mejhian, Sonmani Mejhian, Somari Bhuiya, Tulshi Mejhian, Chumu Mejhian, Sonamani Mejhian and Rebati Mejhian will be taken into service as casual Wagon Loader within 7 days from the date of signing of the settlement and the Tribunal will be requested to pass the Award on the basis of the terms of settlement. They shall be posted as casual Wagon Loader in any Colliery or establishment of the Company according to the discretion/necessity of the Management. At present they shall report for duty to the Agent MBP Colliery and shall be posted at Patmohana Colliery at the moment.

1(a) The offer shall remain open upto 15 days from the signing the settlement after which the management shall not be responsible.

1(b) Responsibility for given reemployment for producing proof for identity shall be with the Union.

2. The period from the date of termination of service i.e., to the date of joining will be treated as no work no pay basis.

3. The workmen will be employed as and when work is available for them on the same terms and conditions as other casual wagon loaders of the establishment.

4. Srimati Jaba Mejhian and other nine shall have no claim whatsoever on account of back wages otherwise from the management and this settlement resolved all dispute and claims of the concerned workmen including those of the reference of dated 15th December 1980 namely the instant reference No. 100 of 1980.

5. Neither party will be entitled to any cost and the parties will bear their respective cost of this proceeding.

That both the parties submit that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept the aforementioned terms and conditions as agreed by both the parties, for maintaining harmonious relation between the parties and Industrial peace at the Establishment.

That both the parties jointly pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accord approval to the proposed settlement which is considered by both the parties as quite fair and reasonable and pass the award accordingly treating this settlement as part thereof.

And for this your Petitioners shall ever pray.

Dated, the 18th May, 1982.

Prem Chand Ray,
Representative of the Employers.

A. MAITI, Secy. CMS (AITUC)
Representative of the Employees.

[No. L-19012(55)/80-D. (B)]

New Delhi, the 8th July, 1982

S.O. 2669.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ballarpur Colliery of Western Coalfields Limited and their workman, which was received by the Central Government on the 3rd July, 1982.

BEFORE JUSTICE SHRI S. R. VYAS (RETD.) PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(13)/1982

PARTIES :

Employers in relation to the management of Ballarpur Colliery of Western Coalfields Limited and their workman Shri C. N. Nande, Ramnagar Wardha Ward No. 2 in front of Dr. Golawar, Wardha (M.S.)

APPEARANCES :

For workman—None.

For Management—Smt. Indira Nair, Advocate and Shri Rajendra Menon, Advocate.

INDUSTRY : Coal DISTRICT Chandrapur (M.S.)

AWARD

Dated, June 28, 1982

In exercise of the powers conferred by Clause 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, Government of India in the Ministry of Labour has referred the following dispute

to this Tribunal for adjudication vide Notication No. L-18012(13)/81-D.IV(B) dated 28th January, 1982 :—

"Whether the action of the management of Ballarpur Colliery of Western Coalfields Limited P.O. Ballarpur, District Chandrapur in terminating the services of Shri C. N. Nande, Ex-General Mazdoor with effect from 13-3-1981 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. The dispute between the parties is with regard to the retirement of the workman, Shri C. N. Nande, an employee of the Ballarpur Colliery of the Western Coalfields Ltd., P.O. Ballarpur, District Chandrapur. Briefly stated the facts giving rise to this dispute, as they appear from the statements of claims filed by the parties are as under :—

Shri C. N. Nande, hereinafter referred to as the workman, was an employee of the Ballarpur Colliery Pvt. Ltd. On 6-9-1970 his services were terminated by this Colliery because of the closure of the mine. Subsequently, the Coal Mines were nationalised and on 6-2-1979 the workman submitted an application to the present management of the Ballarpur Colliery for being given him an employment. As per management's order dated 27-2-1979 he was appointed as a General Mazdoor for one year subject to his production of a medical certificate about his physical fitness The workman was accordingly medically examined on 13 3-1979 by the management's Medical Board and was found fit and his age was certified at 59 years. Consequent on his appointment his name was entered in the Form B Register maintained by the management wherein on the information given by the workman his age in Col. No. 3 of Form B Register was recorded as 59 years. This entry was signed by the workman. Thereafter on 18-3-1980 his appointment was extended by one year. Finally on 13-3-1981 as the workman had completed the age of 60 years he was retired from service.

3. The workman contends that his date of birth was 1-7-1925; that he had not completed the age of 60 years on 13-3-1981 when he was retired; that according to the School Leaving Certificate and the Certificate of the Civil Surgeon he, on the date of his retirement, had not completed 60 years and that on these grounds his termination of service on the ground of superannuation was not justified.

4. The workman on the aforesaid grounds prayed for an order of reinistatement with all consequential benefits.

5. On the rival statements of claims filed by the parties the following Issues were raised :—

Issues

1. Whether the retirement of the workman, Shri C. N. Nande, was justified on the ground that he had attained the age of superannuation on 13-3-81 ?

2. Relief.

My findings on the aforesaid issues are that :—

(1) the retirement on 13-3-1981 of the workman, Shri C. N. Nande, was fully justified as he had completed the age of 60 years before this date.

(2) the workman is not entitled to any relief

Reasons for the findings :—

6. Issue No. 1.—In this case after the notices of the order of reference were served on both the parties, the workman though submitted his statement of claim through post but not even on one of the date fixed for hearing of this reference, either the workman or his representative appeared. Copies of certain documents were filed by the workman along with the statement of claims, but they were neither tendered in evidence nor he examined himself nor did he examine any witness support of the claim made by him. The management, however, examined M.W. 1, Shri K. G. Dahate, Labour Welfare Officer of the Ballarpur Open Cast Mine where the workman was employed. He also proved certain documents in his statement. Thus in the absence of any oral or documentary evidence by the workman himself, the statements of claims by the workman and the management, the oral evidence of Shri K. G. Dahate and the documentary evidence given by him, is the only material for recording a finding on the aforesaid issues.

7. In his statement Shri Dahate stated that initially vide Ex. M/1 the workman was employed for one year. This order was issued by the Manager of the Ballarpur Open Cast Mine. He, in his capacity as Labour Welfare Officer, was incharge of the Form B Register in which names of all the workmen employed at the mine were entered. Ex. M/2 is the entry relating to the workman. In Col. No. 3 his age has been recorded on the date of appointment (18-3-1979) as 59 years. This age, according to Shri Dahate, was recorded in Col. No. 3 on the information given by the workman himself. According to him, the workman was retired on 13-3-1981 i.e. about two years after 18-3-1979 when he had already completed 60 years of his age.

8. Shri Dahate further stated that enquiries were made by the Head master of Deoli vide Ex. M/3 and the Headmaster in his reply Ex. M/4 reported the date of birth as 1-7-1915. Thus on the basis of these documents it has to be said that on 13-3-1981 when the workman was retired from service by the management he had completed the age of superannuation i.e. 60 years.

9. Before this Tribunal the workman along with the statement of claims has filed certain documents, one of which is a School Leaving Certificate dated 7-3-1979 and the second is Medical Certificate dated 14-3-1980 by the Civil Surgeon, Wardha. These are only copies and not the originals. No witness has been examined to prove these documents. In the School Leaving Certificate the date of birth is shown as 1-7-1925 and the Civil Surgeon's Certificate the age of Shri C. N. Nande on 14-3-1980 is shown as 55 years. The School Leaving Certificate, as already stated above, has not been proved by any witness The Civil Surgeon's Certificate only shows his age as about 55 years. It cannot be the evidence of the date of birth. The School Leaving Certificate also could be used as a corroborative piece of evidence and not as substantive evidence on the question of date of birth. Moreover, documents are only copies endorsed as true copies by the workman who himself did not enter the witness box to prove them. Consequently, even if these two documents, which are of no evidential value, are taken into consideration they would not establish that the date of birth of the workman was 1-7-1925. Consequently, in the absence of any evidence of the workman and on the oral and documentary evidence given by the management, it cannot but be concluded that on the date of his retirement the workman had completed the age of 60 years and the retirement was therefore fully justified.

10. Issue No. 2.—In the light of the findings recorded on Issue No. 1, the workman is not entitled to any relief.

11. Accordingly for the reasons given above, it is held that the retirement of the workman, Shri C. N. Nande, from the Ballarpur Colliery of Western Coalfields Limited P.O Ballarpur, District Chandrapur with effect from 13-3-1981 was fully justified as he had completed the age of 60 years on the aforesaid date. The workman is accordingly not entitled to any relief. In the circumstances of the case both the parties are directed to bear their own costs as incurred.

S. R. VYAS, Presiding Officer

[No. L-18012(13)/81-D.IV(B)]

New Delhi, the 12th July, 1982

S.O. 2670.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Parascole Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Kajoragram (Burdwan) and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th July, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT No. 3, DHANBAD

Reference No. 32/82

PRESENT :

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Parascole Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Kajoragram (Burdwan).

AND

Their workman.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri N. R. Tanuk.

For the Workman—None.

INDUSTRY : Coal STATE : West Bengal

Dated, the 2nd July, 1982

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them, U/s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1949 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-19012(86)/81-D.IV(B) dated the 3rd April, 1982.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Parascole Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., Kajoragram, Dist. Burdwan in terminating the services of Shri Bhupendra Kumar Mehta with effect from 11-9-1981 is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. On receipt of the reference a notice was sent to the parties directing them to file their written statements on 1-6-1982.

3. On 1-6-1982 both the parties have filed a joint petition of compromise duly signed on behalf of the management as also the workman stating the terms of the compromise with a prayer that the settlement be accepted and an award be passed accordingly

4. I have gone through the settlement which is beneficial for the workman.

5. Accordingly an award is passed in terms of the above settlement which shall form part of the award.

J. N. SINGH, Presiding Officer

[No. L-19012(86)/81-D.IV(B)]

Enc. : Settlement.

EASTERN COALFIELDS LIMITED
FORM 'H'

Ref. No. 32 of 1982

On behalf of Management—Sri Arun Prabhakar Sr. P.O. Porascole Colliery.

On behalf of workmen—Sri Bhupendra Kr. Mehta Porascole Colliery.

Short Recital of the case

On being stopped from work a dispute was filed before ALC(C) Asansol by Koyala Mazdoor Congress on behalf of the workman Sri Bhupendra Kumar Mehta vide their letter No. KMC/ALCA/PC|81|121 dated 25-10-81. The dispute finally ended in a failure and a failure of conciliation report No. 1/141/82|E.3 dated 9-12-81 was sent by ALC(C) Asansol and received by the Ministry on 15-12-81. On 2nd January, 1982 an agreement was arrived at by the Central Trade Union and the management of ECL by which alongwith others Sri Bhupendra Kumar Mehta have been allowed on duty on 25-1-82 and the period of absence from work was treated as dies-non. In view of this the workman agreed to withdraw the dispute on the following terms of settlement.

Terms of Settlement

That both the management and the workman are bound by the agreement dated 2-1-82 entered in between the management and the Central trade Unions referred to in the short-recital.

That the workman has been allowed on duty from 25-1-82. That the period of absence as mentioned in the agreement will be treated as dies non.

That this solves the dispute in full.

No other claim apart from the agreement already mentioned will be made by the undersigned and the undersigned has got no dispute with the management of Porascole Colliery which was raised by the Union as mentioned vide their letter dated 25-10-81.

Signature of parties

Management representative

1. Arun Prabhakar.
25-1-82.

Workmen.

1. Bhupendra Kr. Mehta.

Witness :—

1. Panch Kori Sadhu.

2. R. M. Patadia.

S.O. 2671.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kuardih Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Kalipahari, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th July, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 16/81

PRESENT :

Shri J. N. Singh, Presiding Officer

PARTIES :

Employers in relation to the management of Karudih Colliery of Eastern Coalfields Ltd., P.O. Kalipahari, Dist. Burdwan.

AND

Their workman

APPEARANCES :

For the Employers—Shri R.K. Singh, Sr. Personnel Officer.

For the Workman—None.

INDUSTRY : Coal STATE : West Bengal

Dated, the 2nd July, 1982.

AWARD

The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-19012 (23)|80-D. IV(B) dated the 29th April, 1981.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Karudih Colliery under Eastern Coalfields Limited, P.O.

Kalipahari, Dist. Burdwan in dismissing Shri Balaram Nayak, Line Mazdoor with effect from 6-11-1978 is is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. Both parties have filed their written statements in support of their case.

3. On 21-6-1982 both parties have filed a joint petition of compromise duly signed on behalf of the management as also the union stating the terms of the compromise with a prayer that the settlement be accepted and an award be passed accordingly.

4. I have gone through the settlement which is beneficial for the workman.

5. Accordingly an award is passed in terms of the above settlement which shall form part of the award.

J. N. SINGH, Presiding Officer
[No. L-19012(23)/80-D.IV(B)]

FORM H

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

Name of Parties :

Representing Employer(s) :
Sri B. C. Misra,
General Manager,
Satgram Area.
Sri D. R. K. Rao,
Personnel Manager,
Satgram Area.

Representing Workman :
Sri Sunil Sen,
Org. Secretary,
CMS (AITUC),
Asansol, (Burdwan).

Short recital of the case

Sri Balaram Nayak was working as Line Mazdoor at Kuardih Colliery. He was found to have committed misconduct as laid down under the provisions of Standing Orders applicable to the Colliery and accordingly he was chargesheeted with suspension from duty vide No. KC|CS|78|115 dated 8-8-78. An enquiry into the aforesaid chargesheet was conducted and he was found to be guilty of the charges levelled against him and he was dismissed from the services of the Company vide letter No. SAT|GM|78|10518 dated 6th November, 1978. An alleged industrial dispute was raised by the Colliery Mazdoor Sabha (AITUC) which ultimately was referred for adjudication (Ref. No. 16 of 1981) and has been pending before the Honourable Central Government Industrial Tribunal No. 3 at Dhanbad.

Terms of Settlement

On representation by the workman as well as by the sponsoring union (CMS|AITUC) the competent authority has reviewed the case and has agreed to reinstate Sri Balaram Nayak in his existing capacity without any back wages and also without any precedence.

The period of absence will be treated as leave without pay and continuity of service will be treated only for the purpose of gratuity and nothing else.

This has been further decided that a Memorandum of Settlement to be signed with the aforesaid sponsoring union and filed before the Honourable Tribunal praying for an Award.

Sri Balaram Nayak may be posted at Tirat Colliery.

Witness :

1. Sd/- (P. L. Ojha)
Sr. Personnel Officer,
Satgram Area.

2. Signature of the parties :

1. Sd./- (B. C. Misra)
General Manager, Satgram Area.

2. Sd./- (D. R. K. Rao)
Personnel Manager, Satgram Area,

3. Sd/- (Sunil Sen)
Org Secretary,
Colliery Mazdoor Sabha (AITUC).

4. Sd./- (Balaram Nayak)

Dated, 18th June, 1982

G. M's Office, Satgram Area,
P.O. Devchandnagar,
Dt; Burdwan.

Sd/- (J. N. Singh)

Presiding Officer
Central Government Industrial
Tribunal-Cum-Labour Court No. 3,
Dhanbad.

S.O. 2672.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Parbelia Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, and their workman, which was received by the Central Government on the 7-7-82.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 42/81

PRESENT :

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

PRESENT :

Employers in relation to the management of Parbelia Colliery of M|s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Neuteria, Dist. Purulia (W.B.).

AND

Their workman

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B.N. Lala, Advocate.

For the Workman—Union's representative

INDUSTRY : Coal STATE : West Bengal

Dated, the 2nd July, 1982.

AWARD

The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U|s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-19012 (13)|81-D. IV (B) dated the 17th September, 1981.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Parbelia Colliery of M|s. E.C.L., P. O. Neuterua, Dist. Purulia (W.B.) in dismissing Shri Binod Bihari Mondal with effect from 31-10-1980 is justified ? If not to what relief is the concerned workman entitled."

2. Both parties have filed their written statements in support of their case.

3. On 25-6-1982 both parties have filed a joint petition of compromise duly signed on behalf of the management as also the union stating the terms of the compromise with a prayer that the settlement be accepted and an award be passed accordingly.

4. I have gone through the settlement which is beneficial for the workman.

5. Accordingly an award is passed in terms of the above settlement which shall from part of the award.

J.N. SINGH, Presiding Officer
Central Govt. Industrial
Tribunal Cum-Labour Court No. 3,
Dhanbad

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 3, DHANBAD

REFERENCE No. 42 of 1981.

PARTIES

Employers in relation to the management of Arbelia Colliery of M|s. E.C., Ltd., P.O. Neturia, Dt. Purulia.

AND

Their workman.

Joint petition of compromise :

Both the parties above named beg most respectively to submit as under :

1. That the above matter is pending before the Hon'ble Tribunal and the matter has not been heard as yet.

2. That, in the meantime, the Union negotiated the dispute in relation to the above matter with the management and the parties have come to an amicable settlement of the dispute on the following terms :

(i) The management agrees to re-Instate the workman herein concerned in his capacity as existing before the date of dismissal and the concerned workman shall be posted at the Bhamuria Colliery of the employers within seven days from the date, this settlement is accepted by the Hon'ble Tribunal.

(ii) Both the parties agree that the period of non-employment of the concerned workman from the date of his dismissal to the date, the concerned workman reports for duty at the Bhamuria Colliery in terms of paragraph (i) above, will be treated as leave without pay and the concerned workmen's continuity of service will be treated only for the purpose of Gratuity and nothing else.

(iii) Both the parties agree that by this settlement the instant dispute arising out of the aforesaid reference is fully and finally resolved and the workman shall have no claim whatsoever in any matter arising out of the instant reference.

(iv) Both the parties agree that this settlement shall be effective as on the date the Hon'ble Tribunal accepts this settlement.

(v) Both the parties agree that they shall bear this own costs.

3. That both the parties pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this settlement as fair and reasonable and may be pleased to pass an award in terms of this settlement.

And for this act of kindness both the parties, as in duty bond, shall ever pray.

Date this the 25th day of June, 1982.

For and on behalf of the workman :

Madhu Banerjee, General Secretary

For and on behalf of the Employers

Sd.| (Illegible)

Agent|Supdt. Mines,
Arbelia Colliery, ECL.

P.O. Neturia, Dist. Purulia.

[No. Lo. 19012(13)/81-D.IV(B)]

S.O. 2673.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Topa Colliery of Messrs Central Coalfields Limited, Post Office Topa, District Hazaribagh and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th July, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD.

In the matter of a reference under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 35 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of Topa Colliery of Central Coalfields Ltd., P.O. Topa Dist. Hazaribagh.

AND

Their Workmen

PRESENT :

Mr. Justice B. K. Ray (Retd.)

Presiding Officer.

Appearances :

For the Employers—Shri T. P. Choudhury, Advocate.

For the Workmen —Shri C. S. Pathak, Branch Secretary, Topa Colliery Branch, Dhanbad.

State : Bihar—Industry : Coal.

Dhanbad, dated, the 29th June, 1982.

AWARD

By Order No. L-20012(111)|81-B.III.A|D.IV(B) dated the 22nd June, 1981, the Central Governmont being ofopinion than an industrial dispute existed between the employers in relation to the management of Topa Colliery of Central Coalfields Limited, P O. Topa, District Hazaribagh aand their workmen in respect of the matters specified in the schedule attracted to the order, referred the same for adjudication to this Tribunal.

The schedule attached to the order reads thus.

"1. Whether the action of the management of Topa Colliery of Central Coalfields Limited, P.O. Topa Distt. Hazaribagh in stopping the following workmen from work is justified? If not, to what relief are they entitled ?

Sl. No.	Name of the workmen	Designation.	Date of stoppage from work
1.	Sri Shibu Manjhi	Miner	15.2.78
2.	Sri Jitlal Singh	-do-	15.2.78
3	Sri Jagdish Mahto	-do-	31.3.77
4.	Sri Govind Karmali	Lino Mistry	15.2.78
5.	Smt. Richi	Kamin	15.2.78
6.	Smt Tilwa	Kamin	15.2.78

2. Whether the action of the management of Topa Colliery of Central Coalfields Limited, District Hazaribagh in superseding S/Shri Niranjan Prasad Mechanical Fitter Category IV and Tulsi Singh, Mechanical Fitter Category V by their juniors at the time of promotion to the next higher category on 18-6-80 is justified? If not, to what relief are they entitled?"

2. After notice to the parties they have filed their respective written statements and rejoinders. Before the case could be taken up for hearing parties entred into a settlement of their dispute in the case out of court and filed the same before the Tribunal with prayer to pass an award in terms there of to-day. By order of the same day the terms of settlement have been held to be fair and reasonable and an award in terms of the settlement has been ordered to be passed. Accordingly the following award is passed.

In regards to item No. 1 of the schedule to the reference order the Employer shall provide employment to S/Shri Shibu Manjhi, Jitlal Singh and Jagdish Mahto as Miners and Sri Govind Karmali as Line Mistry Cat. III with effect from the date they report for duty after the settlement is accepted by the Tribunal aforesaid persons should however report for duty within 15 days of the settlement and if they fail to do so within the speciiied period they will not be entitled to employment. They will not be entitled to any back wages from the dates indicated against each in the reference order relating to their alleged stoppage from work till they report for duty as aforesaid. They will however be entitled to continuity of service.

Regarding the remaining two workers, namely, Smt. Richi and Tilwa covered by item no. 1 of the schedule to the reference order, the workmen drop their demand for their employment. In consequence, these two workers will not be entitled to employment or any benefit or relief.

As regards item no. 2 of the schedule to the reference order, the Employers will promote to Sri Niranjan Prasad, Mech. Fitter Cat. IV (one of the workers referred to in this item) to the post of Mech. Fitter Cat. V from the date following the day the settlement is accepted by the Tribunal. He will be given national seniority by the Employers in the post of Mech. Fitter Cat. V w.e.f. 18-6-1980 alongwith the fixation benefit but he will not be entitled to any other monetary benefit or after for the past period.

Regarding second workman, Sri Tulsi Singh, Mech. Fitter Cat. V (referred to in item no. 2 of the schedule to the reference order) the employers shall consider his case for selection to the post of Mech. Fitter Cat. VI after four months from the date the settlement is accepted by the Tribunal, on the basis of laid down procedure norms by duly constituted D.P.C. The case shall be decided without prejudice from their side.

The workmen and|or the United Coal Workers Union will not raise any industrial dispute or pursue any industrial dispute already raised in regard to 108 workers of Topa Colliery whose names were struck off the rolls by the management due to long absence from duty as per list attached (Annexure A). These workmen are covered by what is known as Hardwar Singh Committee (one man Committee) report.

The aforesaid settlement covers all the matters issues arising in the present reference and all the claims in respect of the workmen concerned in the reference are deemed to have been satisfied by the settement. The settlement filed shall from past of the award.

The reference is answered accordingly. There will, however, be no order for cost.

B. K. RAY, Presiding Officer

[No. L-20012(III)81-D.IV(B)]

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 DHANBAD.

In the matter of Reference No. 35 of 1981

PARTIES :

Employer in relation to the management of Topa Colliery of Central Coalfields Ltd., P.O. Topa, Distt. Hazaribagh.

Vrs.

Their Workmen

The above mentioned employers as well as the workman most respectfully, bag to submit jointly that both the parties have held direct negotiations for the settlement of the disputes covered by the aforesaid reference and have come to an overall agreement as per the following terms and conditions.

(1) That as regards item 1 of the schedule to the reference order the Employer shall provide employment to S/Shri Shibu Manjhi, Jitlal Singh and Jagdish Mehto at Miners and Sri Govind Karmali as Line Mistry, Cat. III with effect from the date they report for duty after this agreement is accepted by the Hon'ble Tribunal. They should, however, report for duty within fifteen days of this agreement being accepted by the Hon'ble Triblunal. If they fail to do so within the specified period they will not be entitled to employment. They will not be entitled to any back wages from the dates indicated against each in the reference order relating to their alleged stoppage from work till they report for duty as aforesaid but they will be entitled to continuity of service.

(2) That as regards the remaining two workers namely Smt. Richi & Tilwa covered by item 1 of the schedule to the reference order, the workman drop their demand for their employment. In consequence, these two workers will not be entitled to employment or any benefit or relief.

(3) That as regards item 2 of the schedule to the reference order, the Employers agree to promote Sri Niranjan Prasad, Mech. Fitter Cat. IV (one of the workers referred to in this item) to the post of Mech. Fitter Cat. V from the date following the date this agreement is accepted by the Hon'ble Tribunal. He will however, be given notional seniority by the employers in the post of Mechanical Fitter, Cat. V w.e.f. 18-6-80 alongwith the fixation benefit but he will not be entitled to any other monetary benefit or arrear for the past period.

(4) That as regards the second workman, Sri Tulsi Singh Mech. Fitter Cat. V (referred to in item 2 of the schedule to the reference order), the employers shall consider his case for selection to the post of Mech. Fitter Cat. VI after four months from the date this agreement is accepted by the Honble Tribunal, on the basis of laid down procedure/norms by duly constituted DPC. It was agreed that the case will be decided without projudice from their side.

(5) That the workman and or the United Coal Workers Union agree not to raise any industrial dispute or pursue any industrial disputes already raised in regard to 108 ex-workers of Topa Colliery whose names were struck off the rolls by the management due to long absence rrom duty as per list attached (Annexure A) who are covered by what is known as Hardwar Singh Committee's (one man Committee) report.

(6) That this is an over-all agreement covering all the matters/issues covered by the aforesaid reference and all the claims in respect of the workman concerned in the reference.

(7) That both the parties consider that this agreement is fair, just and reasonable.

In view of the above the employers and workman jointly pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept

this agreement pjoint application and given an award in terms thereof.

Supdt. of Mines/Agent
Project Officer, Topa Colliery
Central Coalfields Limited, P O. Topa Colliery
Hazaribagh
For and on behalf of Employer
T. P. CHOUDHURY, Advocate

S. N. JHA,
Area Secretary (Kuju Area)
United Coal Workers Union
For & on behalf of workman
C. S. PATHAK,
Branch Secretary, Topa Colliery
Branch, United Coal Workers Union
For and on behalf of workman.

Part of the Award.

CENTRAL COALFIELDS LIMITED

TOPA COLLIERY

The name of those workers who were not Physically present on their duties on or before 7-3-1978.

Sl. No.	Name	Screening No.
1.	Smt. Parmeshwer	841
2.	Smt. Jethu Orawn	895
3.	Smt. Biglahi Devi	899
4.	Smt. Chando	903
5.	Smt. Munia Dev	949
6.	Smt. Purna Mohto	491
7.	Smt. Kandan Munda	2/W
8.	Smt. Chinta Devi	60/W
9.	Smt. Jhanaku Manjhi	680
10.	Smt. Mangra Orawn	46/P
11.	Sri Khedani Mohto	694/M
12.	Sri Asgar Ali	7/P
13.	Srl Baldev Saw	
14.	Sri Ghuja lal Mistry	719
15.	Sri Kalu Ram	939
16.	Srl Tinku Karmali	23/U
17.	Sri Indra Ganjhu	38/9
18.	Sri Kalu Mohto	696/N
19.	Smt. Joti Kamin	733
20.	Smt. Panpati Kamin	737
21.	Smt. Rupani	738
22.	Smt. Pairo	743/N
23.	Smt. Dhania	744
24.	Smt. Lilmuni	745
25.	Smt. Lal Muni	741
26.	Smt. Sadhani	746
27.	Sri Mirutanjay Choubey	6/V
28.	Sri Kashi Nath	63/W
29.	Sri Sukhadeo Mahto	71
30.	Sri Shoocharan Dusadh	81
31.	Smt. Phuliya Kamin	259
32.	Smt. Tilwa Kamin	65
33.	Smt. Richi Kamin	66
34.	Sri Harendra Pd.	108
35.	Sri L.S.N.P. Sinha	
36.	Sr Jagalu Mistry	379
37.	Sr' Birsa Orawn	
38.	Sri R K. Gupta	
39.	Smt. Sita Devi	292
40.	Smt. Silna Devi	42
41.	Sri Tupla Naik (Sweeper)	
42.	Sri Toli Bhuiya	402
43.	Sri Dubraj Munda	76/51
44.	Smt. Ataweria Devi	45
45.	Smt. Chhotaki	174
46.	Sri Cultan Bhuiya	249
47.	Sri Chaita Ram	883
48.	Sri Jairam Singh	96
49.	Smt. Sanicharya Kamin	144
50.	Sri Narendra Prasad	936
51.	Sri Kartik Prasad	87
52.	Sri Sundari	311
53.	Sr Ghuja Bedia	156
54.	Sri Jadu Ram	114
55.	Sri Ramchandra Karmali	484
56.	Sri Udai Karmali	110
57.	Sri Hankal Manjhi	790
58.	Sri Jitlal Singh	
59.	Sri Govind Karmaji	769
60.	Sri Bina Manjhi	
61.	Srl Banshi Manjhi	38
62.	Sri Doma Manjhi	6/D
63.	Shibu Manjhi	
64.	Sri Rameshwar Pd. Singh, Gr. III	
65.	Sri Jam Pans	1101
66.	Sri Bundia Kamin	1127
67.	Sri Surendra	98/D
68.	Sri Bhulia Naik	177/D
69.	Sri Sri Mahto	
70.	Sri Malter	77/N
71.	Sri Ramadalt Yadav	970
72.	Sri Fulchard Mahto	70/U
73	Sri Bandhu Munda	112
74	Sri Yodha Munda	31/L
75.	Sri Jagdish Mahto	220
76.	Sri Budhan Manjhi	200
77.	Sri Madan Manjhi	183
78.	Sri Sukhdeo Saw	311
79.	Sri Babulal Mahto	151
80.	Sri Rameshwar Mohto	153
81.	Sri Durga Orawn	524
82.	Sri Sri Munda	561
83.	Sri Mahabir Naik	572
84.	Sri Somra Baitha	593
85.	Sri Vijay Munda	611
86.	Sri Dhanewar	649
87.	Smti. Jaswa Devi	654
88.	Smti Jirwa No. II	659
89.	Sri Jay Nath	794
90.	Sri Birbal Manjhi	828
91.	Sri Budhan Manjhi	829
92.	Sri Jhuna Bhuiya	530
93.	Sri Ram Mohan Ram T/L	935
94.	Sri Jag Bahadur Ram T/L	913
95.	Sri Sahebjan Mian	629/T
96.	Sri Ramanuj Ram	696
97.	Sri Harishanker	916
98.	Sri Ramjanam Singh	924
99.	Sri Ramdhani	926
100.	Sri Amar Chand	928
101.	Sri Rajdeo Mohto	938
102.	Sri Methlesh	941
103.	Sri Shoo Pujan Ram	947
104.	Sri Feku Ram	952

105. Sri Bihan Ram	953
106. Sri Sheo Bachan	955
107. Sri Sheo Kumar	958
108. Sri Murali Ram	960
109. Sri Dular Ram	962
110 Sri Hari Pd. Singh	97
111. Sri Rampati Chaoudhary	1141
112. Smt. Soni Kamin	16
113. Sri Jhari Ganjhu	35
114. Sri Kaila Ganjhu	46

Sd/-
Sr. Personnel Officer (T)
Topa Project

Project Officer (T
Topa Project

New Delhi, the 13th July, 1982

S.O. 2674.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 3, Dhanbad in respect of a complaint under Section 33A of the said Act filed by Shri Kali Passi, Night Guard, Bhowra (S) Colliery, against the management of Bharat Coking Coal Limited, which was received by the Central Government on the 7th July, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Complaint Case No. 2/81

PRESENT :

Shri J.N. Singh, Presiding Officer.

PARTIES :

Shri Kali Passi, Night Guard, Bhowra (S) Colliery, C/o. J. D. Lall, Advocate, Dhanbad Court, Dhanbad ...Complainant

—Vs—

M/s. Bharat Coking Coal Ltd., Through the General Manager, Area No. XI, P. O. Bhowra, Dist. Dhanbad. ...Opp. Party

APPEARANCES :

For the Complainant—Shri J. D. Lall, Advocate.

For the Opp. Party—Shri R. S. Murthy, Advocate.

INDUSTRIAL : Coal. STATE : Bihar.

Dated, the 1st July, 1982

AWARD

This is a Complaint U/S 33A of the Industrial Disputes Act, 1947, filed by Sri Kali Passi, Night Guard, Bhowra (S) Colliery against the Bharat Coking Coal Ltd.

2. On receipt of a copy of the complaint the opp. Party filed its written statement on 17th March, 1982.

3. On 22nd June, 1982 both parties have filed a joint petition of compromise duly signed on behalf of the opp. party as also the union and workman stating the terms of the compromise with a prayer that the settlement be accepted and an award be passed accordingly.

4. I have gone through the settlement which is beneficial for the workman.

5. Accordingly an award is passed in terms of the above settlement which shall form part of the award.

Sd/-
J. N. SINGH, Presiding Officer.

Enc. Settlement.

[No. L-24012(1)/82-D. IV(B)]
S. S. MEHTA, Desk Officer

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL NO 3, DHANBAD.

In the matter of complaint No. 2 of 1981

PARTIES :

Sri Kali Pasi, Night Guard, Bhowra(S) Colliery C/o. Sri J. D. Lall, Advocate, Dhanbad Court, Dhanbad. ..Complainant

—Vs—

Messrs. Bharat Coking Coal Ltd. through the General Manager, Area No. XI, Bhowra, Dhanbad ...Opposite Party.

The above mentioned parties most respectfully beg to submit this joint application and state jointly as follows :—

(1) That both the parties have mutually discussed the matter with a view to coming to an amicable settlement keeping in view the Award of this Hon'ble Tribunal in Complaint Case No. 1 of 1977 relating to Shri Jag Narain Koiri, another workman of Bhowra (S) Colliery who was charge-sheeted and dismissed along with the applicant in this case simultaneously in connection with the same case, and agreed to settle the matter as indicated in paras (2) to (6) of this application.

(2) That keeping in view the aforesaid award dated 13th June, 1980 in Complaint Case No. 1 of 1977, the Management (Opposite Party) agreed to reinstate Sri Kali Pasi in service within fifteen days of the Hon'ble Tribunal accepting this joint petition in the post of miner/loader in Bhowra (S) Colliery.

(3) That the Management would pay to the applicant Sri Kali Pasi 20 per cent of back wages with effect from 16th September, 1976 till the date he is reinstated in service in terms of para (2) above, without any other consequential benefits like Attendance Bonus/ and Profit Sharing Bonus/Ex. gratia payment.

(4) That Sri Kali Pasi would have continuity of service.

(5) That Sri Kali Pasi, applicant, has agreed to the over-all settlement of this case and all his claims arising out of the present case as indicated in paras (2), (3) and (4) above.

(6) That both the parties agree that this agreement is fair and reasonable to both of them.

The applicant and the opposite party, therefore, jointly pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this joint application and give his award in terms thereof.

Sd.
(B. N. SARKAR)
General Manager,
Bhowra Area No. XI,
Bharat Coking Coal Ltd. Bowra,
OPPOSITE PARTY.

(KALI PASI)
COMPLAINANT.
Dated 22-6-82.
(J. D. LAL.)
Secretary, BCKU & Advocate
Authorised Representative of
Complainant.
Dhanbad.
Dated 22-6-82

Sd/-
RAL. S. MURTHY.
Advocate of Employer (Opposite Party).

Sd/-
J. N Singh,
Presiding Officer
Central Govt. Industrial Tribunal
Cum-Labour Court. No. 3

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1982

का०आ० 2675.—केन्द्रीय सरकार को प्रतीत होता है कि मैसर्स एम्टी इन्टरनेशनल, 1104 ए-बी, रहेजा चैम्बर्स, 11वीं मंजिल, नारीमन पाइंट, मुम्बई-21, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35018(43)82पी० एफ(ii)]

New Delhi, the 1st July, 1982

S.O. 2675.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Fmtee International 1104 A-B, Raheja Chambers 11th Floor, Nariman Point, Bombay-21, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(43)/82-PF.II]

का०आ० 2676.—केन्द्रीय सरकार को प्रतीत होता है कि मैसर्स स्टूडियो बहार, 23-ए, सेंट्रल चौपाटी बिल्डिंग, चौपाटी, मुम्बई-7 जिसके अन्तर्गत 101/2/3 कल्याणदास उद्योग भवन, प्रभादेवी, मुम्बई-25 स्थित उसकी शाखा भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०35018(44)82-पी० एफ० (ii)]

S.O. 2676.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Studio Bahar, 23A Central Chowpatty Building, Chowpatty, Bombay-7 including its branch at 101/2/3 Kalyandas Udyog Bhavan, Prabhadevi, Bombay-25, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(44)/82-PF II]

का०आ० 2677.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जलगांव दाल एण्ड फ्लोर मिल्स, शिवाजी नगर, जलगांव नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35018(52) 82-पी०एफ० (ii)]

S.O. 2677.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jalgaon Dall and Flour Mills, Shivajinagar, Jalgaon, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(52)/82-PF-II]

का०आ० 2678.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इन्टरनेशनल मेडीटेक (प्राइवेट) लिमिटेड, 6, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली जिसके अन्तर्गत (1) नदर्न इंडिया सन्ट्रल इंडिया रीजन, 80 दरयागंज, नई दिल्ली-2, (2) ईस्टर्न इंडिया रीजन, फ्लेट नं० 6 पांचवी मंजिल, मानसरव 3-बी, कामक स्ट्रीट, कलकत्ता-16 (3) फार ईस्टर्न इंडिया रीजन आकश दीप, लखेटेकिया रोड, पुलिस रिजर्व लाइन्स, गौहाटी-1, (4) वेटस्टन इंडिया रीजन 1106 रहेजा सेन्टर, 214/3, नरीमन पाइंट मुम्बई-21, (5) सदर्न इंडिया रीजन, 106, पैंथीयन रोड, खलीलशीराजी इस्टेट एगमोर, मद्रास-8 और (6) इम्पैक्स डिविजन, 402, गगनदीप, 12, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-8 स्थित उसकी शाखाएं भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019(48) 82-पी०एस० (ii)]

S.O. 2678.—Whereas it appears to the Central Government to the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs International Meditek Private Limited. 6, Netaji Subhash Marg, New Delhi including its branches at (1) Northern India Central Indian Regions, 80, Darya Ganj, New Delhi-2, (2) Eastern India Region, Flat No. 6, 4th Floor 'Manasarvar' 3-B, Camac Street, Calcutta-16 (3) Far Eastern India Region, 'Akash Deep' Lakhotkia Road, Police Reserve Lines, Gauhati-1, (4) Western India Region, 1106, Raheja Centre, 214/3, Nariman Point, Bombay-21, (5) Southern India Region 106, Panteon Road, Khaleel Shirazi Estate, Egmore, Madras-8 and (6) Impex Division, 402, Gagan Deep, 12, Rajendra Place, New Delhi-8 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(48)/82-PF-II]

का०आ० 2679.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्वास्तिक फायलम (प्राइवेट) लिमिटेड, 28 और 37 नजफगढ़ रोड नई दिल्ली-15 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत: केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019(51)/82-पी० एफ० (ii)]

S.O. 2679.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Swastik Foils (Private) Limited, 28 and 37, Najafgarh Road, New Delhi-15, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(51)/82-PF-II]

का०आ० 2680.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एसवी टूल एण्ड डिजाइन इंजीनियर्स, 227-पोल्लाची मार्ग, डाकघर ईचानारी, कोयम्बटूर जिसके अन्तर्गत 3-ए, पालानीस्वामी नायडू स्ट्रीट, अवनासी मार्ग, कोयम्बटूर, 18 स्थित उसका प्रशासनिक कार्यालय भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019(52)/82-पी० एफ(ii)]

S.O. 2680—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Esvee Tool and Design Engineers, 227, Pollachi Road, Eachanari Post Offi e, Coimbatore-641021 including its Administrative Office at 3-A, Palaniswamy Naidu Street, Avanashi Road, Coimbatore-18, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(52)/82-PF-II]

का०आ० 2681.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एशियन वुड्स एण्ड पोलिमर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, केलगेरी, जिला धारवाड़, कर्नाटक नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अत: केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019(53)/82-पी०एफ० (ii)]

S.O. 2681—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Asian Woods and Polymers (Private) Limited, Kelgeri, Dharwar District Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(53)/82-PF-II]

का०आ० 2682.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राजकमल मोटर्स, 145/146, नुगमबक्कम हाई रोड, मद्रास-34 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019(54)/82-पी० एफ० (ii)]

S.O 2682.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rajkamal Motors/145/146 Nungambakkam High Road, Madras-34, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No S-35019(54)/82-PF-II]

का०आ० 2683.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रोलेक्स इन्टरप्राइजेज, 11/12, इण्डस्ट्रियल इस्टेट, कटक-10 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019(55)/82-पी०एफ० (ii)]

S.O. 2683.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rollex Enterprises, 11/12, Industrial Estate Cuttack-10, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No S-35019(56)/82-PF-II]

का०आ० 2684.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स भारतीय पम्पस्, 33, औद्योगिक क्षेत्र, फगवाड़ा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अत: केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019(56)/82-पी० एफ० (ii)]

S.O. 2684.—Whereas it appears to the Cent al Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bharti Pistons, 32, Industrial Area, Phagwara, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(56)/82-PF-II]

का०आ० 2685.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग कम्पनी, विहार टाकीज के पास, पोस्ट बाक्स नं० 159, झरिया, धनबाद, बिहार नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस० 35019/57/82-पी०एफ०(II)]

S.O. 2685.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Industrial Engineering Company, Near Vihar Talkies, Post Box No. 159, Jharia, Dhanbad, Bihar, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(57)/82-PF-II]

का०आ० 2686.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स माथारु एण्ड संस, 350, सोनारी वेस्ट लेआऊट, जमशेदपुर-11 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस० 35019/58/82-पी० एफ०(II)]

S.O. 2686.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Matharu and Sons, 350, Sonary West Layout, Jamshedpur-11, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(58)/82-PF-II]

का०आ० 2687.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रिंटराइट ब्लाक्स, मेन रोड, रांची-1, बिहार नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस० 35019/59/82-पी० एफ०(II)]

S.O. 2687.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Printrite Blocks, Main Road, Ranchi-1 (Bihar), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(59)/82-PF.II]

का०आ० 2688.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सैटलाइट ट्रेवल्स, 3-6-322, हैदरगुडा, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस० 35019/60/82-पी० एफ०(II)]

S.O. 2688.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Satellite Travells, 3-6-322, Hyderguda, Hyderabad-1 (Andhra Pradesh), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(60)/82-PF-II]

का०आ० 2689.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री वेंकटेश्वर राइस एण्ड फ्लौर मिल, पायकराव पेटा, जिला विजाग आन्ध्र प्रदेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस० 35019/61/82-पी० एफ०(II)]

S.O. 2689.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Venkateswara Rice and Flour Mill, Payakaraopeta, Vizag District, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercis of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(61)/82-PF-II]

का०आ० 2690.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स थाजाकुडी को-आपरेटिव एग्रीकल्चरल, बैंक लिमिटेड, सं० 1918 डाकघर थाजाकुडी, जिला कन्याकुमारी नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस० 35019/75/82 पी० एफ० (II)]

S.O. 2690.—Whereas it appears to the Central Government the employer and majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Thazhakudy Co-operative Agricultural Bank Limited, No. 1918, Thazhakudy Post Office Kanyakumari District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(75)/82-PF.II]

का०आ० 2691.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता कि मैसर्स सूसी आटो, 25-तमिल संगम रोड, मदुराई-625001 (तमिल नाडु) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस० 35019(76)/82-पी०एफ० (II)]

S.O. 2691.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Susee Auto, 25, Tamil Sangam Road, Madurai-625001, (Tami' Nadu), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment

Now, therefode, in exercise of the powers cnferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Cenral Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(76)/82-PF.II]

का०आ० 2692.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ऐम्ब्रोसा केमिकल फैक्टरी, इण्डस्ट्रियल इस्टेट, थट्टनचावडी, पांडिचेरी-9 नामक स्थापन सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस० 35019(77)/82 पी एफ० (II)]

S.O. 2692.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment konwn as Messrs Ambrosa Chemical Factory, Industrial Estate, Thattanchavadi, Pondicherry-9,, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019 (77)/82-PF. II]

का०आ० 2693.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बाला मुरुगन ट्रांसपोर्ट्स, 53-डिंडीगुल रोड, पलानी-624601 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस० 35019(78)/82-पी० एफ० (II)]

S.O. 2693.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bala Murugan Transports, No. 53, Dindigul Road, Palani-624601, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019 (78)/82-PF. II]

का०आ० 2694.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सदर्न इंडिया फूड इंडिस्ट्रीज, मैनन-थोडि रोड, नचनहौली पाल्या, मैसूर, जिसके अन्तर्गत 9/394-सी, शालापुर मैसन, चेरूती रोड, कालीकट, केरल स्थित उसकी शाखा भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं एस० 35019(83)/82-पी० एफ० (II)]

S.O. 2694.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Southern India Food Industries, Manmthody Road, Nachanahally Palya, Mysore including its branch at 9/384-C, Sholapur Mansion, Cherooty Road, Calicut; Kerela, have agreed that the provisions of the Empolyees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019 (83)/82-PF. II]

का०आ० 2695.—केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एण्ड सर्विस महाबलिपुरम रोड, ओग्गियम थोराइ पक्कम, मद्रास-96 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/84/82-पी० एफ० (II)]

S.O. 2695.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Engineering Products and Services, Mahabalipuram Road, Oggium Thoraipakkam, Madras-96 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019 (84)/82-PF. II]

का०आ० 2696.—केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आर, पार्वती अम्मल पावरलूम फैक्ट्री, 120-सी-फैक्ट्री, रेलवे फीडर रोड, शंकरनकोइल, तिरुनेलवेली जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/123/82-पी० एफ० (II)]

S.O. 2696.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment konwn as Messrs R. Parvathy Ammal Powerloom Factory, 120-C-Factory, Railway Feeder Road, Sankarankoil, Tirunelveli District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019 (123)/82-PF.II]

का० आ० 2697.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एडवांस कम्पोनेन्टस एण्ड इन्स्ट्रूमेन्टस (प्राइवेट) लिमिटेड, 3-ए-3-ए- 1, बेवाडी इंडस्ट्रियल एरिया, मैसूर-5 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/128/82-पी० एफ० (II)]

S.O. 2697.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment konwn as Messrs Advance Components and Instruments (Private) Limited, 3-A-3AI, Bevadi Industrial Area, Mysore-5, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019 (128)/82-PF.II]

का० आ० 2698.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इंडियन न्यूमैटिक सेल्स एण्ड सर्विसेज, सं० 136, चन्द्रलोक बिल्डिंग्स, सिकन्दराबाद, हैदराबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/129/82-पी० एफ० (II)]

S.O. 2698.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Indian Pneumatic Sales and Services No. 136, Chandralok Buildings, Secunderabad, Hyderabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019 (129)/82-PF. II]

का० आ० 2699.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्टील ट्रीटर्स (मैसूर) (प्राइवेट) लिमिटेड, के० आर० एस० रोड, मैटागल्ली, मैसूर-16 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/153/82-पी० एफ० (II)]

S.O. 2699.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment konwn as Messrs Steel Treaters (Mysore) (Private) Limited, K. R. S. Road, Metagalli, Mysore-16, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019 (153)/82-PF. II]

का० आ० 2700—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स उड़ीसा इंजीनियरिंग वर्क्स पोस्ट आफिस लाठी काटा जिला सुंदरगढ़, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों का बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उ० (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उप उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/154/82—पी० एफ०-2]

S.O. 2700—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Orissa Engineering Works, Post Office Lathikata, District Sundergarh, have agreed that the provisions of the Employees, Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S 35019 (154)/82-PF. II]

का० आ० 2701—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री कालीश्वरी फायर वर्क्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 5-एन० चेयरमैन ए० शनमुगा नाडार रोड, शिवकासी-626123 (तमिलनाडु) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/155/82-पी० एफ० (ii)]

S.O. 2701.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Kaliswari Fire Works (Private) Limited, 5 N, Chairman A. Shanmuga Nadar Road, Sivakasi-626123 (Tamil Nadu), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019 (155)/82-PF. II]

का० आ० 2702.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रिसिज वायर क्लोथ कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 45/1, एथिपेट, मद्रास-58 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/156/82-पी० एफ० (ii)]

S.O. 2702.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Precisa Wire Cloth Company (Private) Limited, 45/1, Athipet, Madras-58, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019 (156)/82-PF. II]

का० आ० 2703—केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि मैसर्स व्यवसाय सेवा सहकारी संघ नियामिथा, होस्पेट नं० 1, होस्पेट-583201, बैलारी (कर्नाटक) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन का लागू करती है।

[सं० एस० 35019/157/82 पी० एफ० (ii)]

S.O. 2703.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vyavasaya Seva Sahakara Sangha Niyamitha, Hospet No. 1, Hospet-583201, Bellary (Karnataka), have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019 (157)/82-PF. II]

का० आ० 2704—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्पीडी सेल्स, ए-5, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली-48, जिसके अन्तर्गत (1) 5/8, अजमल खां रोड, नई दिल्ली स्थित उसका शो रूम और 41, जैम शोपिंग सेंटर, म्यूजियम रोड, बंगलौर स्थित उसका शाखा कार्यालय भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन का लागू करती है।

[सं० एस० 35019/158/82-पी० एफ० (ii)]

S.O. 2704.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Speedy Sales, A-5, Kailash Colony, New Delhi-48 including its show room at (1) 5/8, Ajmal Khan Road, New Delhi and branch office at 41-Gem Shopping Centre, Museum Road, Bangalore, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019 (158)/82-PF. II]

का० आ० 2705 --केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रेणुका एक्सपोर्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड, एस०-24, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-16 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/159/82-पी० एफ० (ii)]

S.O. 2705.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Renuka Exports (Private) Limited, S-24, Green Park Extension, New Delhi-16, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019 (159)/82-PF. II]

का० आ० 2706 --केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इलैक्ट्रो मैकेनिकल इंडस्ट्रीज, एस-11, टी० आई० ई० बालानगर, हैदराबाद-37 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/160/82-पी० एफ० (ii)]

S.O. 2706.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Electro Mechanical Industries, S-11, T. I. E., Balanagar Hyderabad-37, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No. S 35019 (160)/82-PF. II]

का० आ० 2707 --केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री वेत्री विनायगर टिम्बर्स, अंबासामुद्रम, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/161/82-पी० एफ० (ii)]

S.O. 2707.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Vetri Vinayagar Timbers, Ambasamudram, Tirunelveli District, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(161)/82-PF.II]

का० आ० 2708 --केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शिवानन्द टैक्सटाइल प्रासेसर्स, 6-ए रायप्पापुरम, एलीमैन्टरी स्कूल एक्सटेंशन स्ट्रीट, तिरुपुर-638601 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/162/82-पी० एफ० (ii)]

S.O. 2708.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sivananda Textile Processors 6 A, Rayappapuram, Elementary School Extension Street, Tirpura-638601, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019 (162)/82-PF. II]

का० आ० 2709 --केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्पिनर्स, ए-3, पीयरलाइट इंडस्ट्रियल एस्टेट, न्यू तीरथाहल्ली रोड, शिमोगा-577201 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/163/83-पी० एफ० (ii)]

S.O. 2709.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Spinners, A-3, Pearlite Industrial Estate, New Thirthahalli Road, Shimoga-577201, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S 35019 (163)/82-PF. II]

CORRIGENDUM

S.O. 2710.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 517 dated the 27 h January, 1982 published at page 537 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 6th February, 1982 at page 537, line 4, for the words "Machi-Mafa" read "Machi-Mafs".

[No. S. 3018 (20)/81-PF. II]

का० आ० 2711.—मैसर्स अहमदाबाद स्टील क्राफ्ट एंड रोलिंग मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड ओधव रोड, अहमदाबाद-382410, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बताये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापना के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन सब सदस्यों के नामनिर्देशिती या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम के बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एम०-35014/8/82-भ० नि०-(II)]

S.O. 2711.—Whereas Messrs Ahmedabad Steel Craft and Rolling Mills (P) Limited, Odhav Road, Odhav, Ahmedabad-382410 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempts under the said Act, is employed in his establishment; the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and where any amendment is likely to affect advedsely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India

[No. S. 35014 (8)/82-PF. II]

का० आ० 2713.—मैसर्स कुम्बकोनम सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, 149 टी० एम० आर० बिग स्ट्रीट, कुम्बकोनम-612001

(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम (1976) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उक्त फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम को, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से रकम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या वि को जो यदि वह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय त्वरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस० 35014(41)/82-पी० एफ० 2]

S.O. 2712.—Whereas Messrs Kumbakonam City Union Bank Limited, 149, TSR Big Street, Kumbakonam-612001. (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the power, conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Schme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employee' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premimum in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allwoed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014 (41)/82-PF-II]

का० आ० 2713—मैसर्स प्रागा ट्यूल्स लिमिटेड, 6-6-8/32, कवाडी गुड़ा, सिकन्दराबाद-500003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के केन्द्रीय छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और जिसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आंध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आंध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उस मृत सदस्य के नामनिर्देशिती या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होता, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम या सदय तत्स्थानता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस 35014(11)/82-पीएफ०-2]

S.O. 2713.—Whereas Messrs Praga Tools Limited, 6-2-82/32 Kavadiguda, Secunderabad-500003. (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance [illegible] the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said [illegible] heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner [illegible] sonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment [illegible] the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. [illegible] to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled.

11. [illegible] by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased [illegible] covered under the said Scheme [illegible] exemption shall be that of the employer.

12. [illegible] under the Scheme, the establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014 (11) 82-PF. II]

का० आ० 2714.—मैसर्स जुबली [illegible] [illegible] (19) [illegible] 17 [illegible]

[illegible] 1976 [illegible]

[illegible] 17 [illegible]

अनुसूची

1. [illegible]

[illegible]

सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रभार का संदाय [illegible] निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. [illegible] सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. [illegible] कर्मचारी भविष्य निधि का [illegible] [illegible]

6. [illegible]

7. [illegible] करेगा।

8. [illegible] प्रादेशिक [illegible] प्रतिकूल प्रभाव [illegible]

9. [illegible] भारतीय जीवन बीमा [illegible] अपना चुका है [illegible]

10. [illegible] कारणवश [illegible]

11. [illegible] बीमा [illegible]

12. [illegible] नाम निर्देशितियों/ [illegible] प्रत्येक दशा [illegible] प्राप्त होने [illegible]

[सं० एस०-35014(12)/82-पी०एफ०-II]

S.O. 2714.—Whereas Messrs Jubilee Mills Limited Outside Dariyapur Gate P. B. No. 158 Ahmedabad (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for

exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmadabad and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurence Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmadabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adpoted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014 (12)/82-PF-II]

का० आ० 2715—मैसर्स हुगली पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल-12601) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए वे फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा, निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण, प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4 नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक,

सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस०-35014(45)/82-पी० एफ०-2]

S.O. 2715.—Whereas Messrs The Hooghly Flour Mills Co. Limited Calcutta (WB|2601) (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter refrred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of Three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by me employer in payment of premium the responsiblity for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014 (45)/82-PF-II]

का०आ० 2716 मैसर्स इंडियन ऐलुमिनियम कम्पनी लिमिटेड, हीराकुड-768016 जिला संबलपुर (उड़ीसा), (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उड़ीसा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4 नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उड़ीसा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस 35014/127/81-एफ०पी०जी०(ii)]

S.O. 2716.—Whereas Messrs. Indian Aluminium Company Limited, Hirakud-768016, District Sambalpur (Orissa) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Orissa and, maintain such accounts and pdovide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act. within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accouts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee, the amount payable under this scheme be less, than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Orissa and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the esetablishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the time as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014 (127)/82-PF-II]

का०आ० 2717.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वेबेल वीडियो डिवाइसेज लिमिटेड, पी-1, तारातला मार्ग, कलकत्ता-88 जिसके अन्तर्गत 225-ई, ए.जे.सी. बोस मार्ग, कलकत्ता-20 स्थित उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एम-35017/48/82-पी.एफ.(II)]

S.O. 2717.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Webel Video Devices Limited, P-1, Taratala Road, Calcutta-88, including its Registered Office at 225-E A.J.C. Bose Road, Calcutta-20, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017(48)/82-PF. II]

का०आ० 2718.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ओरिएन्टल ट्रैवल विंग्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 3, मिडिलटन मैन्सन्स, 9/1, मिडिलटन स्ट्रीट, कलकत्ता-71, जिसके अन्तर्गत 14-सी, जनपथ, बापूजी नगर, भुवनेश्वर-9, (उड़ीसा) स्थित उसकी शाखा भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एम०-35017/49/82-पी०एफ० (II)]

S.O. 2718.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Oriental Travel Wings (Private) Limited, 3, Middleton Mansions, 9/1, Middleton Street, Calcutta-71 including its branch at 14-C, Janpath, Bapujinagar, Bhubaneshwar-9 (Orissa), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No. S. 35017(49)/82-PF. II]

का०आ० 2719.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एच. के. सेन एंड एसोसिएट्स, 7-ए, नीलाम्बर बिल्डिंग, 28-बी, शेक्सपीयर सरनी, कलकत्ता-17 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए, ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध के उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एम-35017/51/82-पी.एफ (II)]

S.O. 2719.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs H. K. Sen and Associates, 7A, Neelambar Building, 28-B, Shakespeare Sarani, Calcutta-17 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017(51)/82PF II]

का०आ० 2720.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स होमियो लेबोरेटरी, 18 जस्टिस मनमथा मुखर्जी रोड, कलकत्ता-9 जिसके अन्तर्गत 194/1 एस०के० देव रोड, कलकत्ता-48 स्थित उसका प्रयोगशाला भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35017/53/82-पी०एफ० (II)]

S.O. 2720.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Homoeo Laboratory, 18, Justice Manmatha Mukherjee Row, Calcutta-9 including its Laboratory at 194/1, S. K. Deb Road, Calcutta-48, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017(53)/82-PF. II]

का०आ० 2721.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वेद संस एण्ड कंपनी, 15-बी, क्लाईव रोड, कलकत्ता-1, जिसके अन्तर्गत अनंत निवास, 262/70, नरसी नत्था स्ट्रीट, मुम्बई-9 स्थित उसकी शाखा भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35017/54/82-पी०एफ० (II)]

S.O. 2721.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ved Sons and Company, 15-B, Clive Row, Calcutta-1 including its branch at Anant Niwas, 262/70, Narsi Natha Street, Bombay-9, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017(54)/82 PF. II]

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1982

का०आ० 2722.—हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्री कुंवर शमशेर सिंह के स्थान पर श्री आई० के० सूरी, सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 850 (अ), दिनांक 21 अक्तूबर 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "(राज्य सरकार द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद 13, के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"श्री आई०के० सूरी,
सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,
श्रम और रोजगार विभाग,
शिमला।"

[सं० यू-16012/13/82-एच०आई०]

New Delhi, the 7th July, 1982

S.O. 2722.—Whereas the State Government of Himachal Pradesh has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri I. K. Suri, Secretary to the Government of Himachal Pradesh to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri Kanwar Samsher Singh,

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employee's State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. 850(E), dated the 21st October, 1980, namely:—

In the said notification, under the heading ("Nominated by the State Government under clause (d) of section 4)", for the entry against Serial Number 13, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri I. K. Suri,
Secretary to the Government of Himachal Pradesh,
Labour and Employment Department,
Simla".

[No. U-16012/13/82-H.I.]

का०आ० 2723.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रिपैट्रिएटस कोआपरेटिव फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, 142-ए, संथोम हाई रोड, मद्रास-4 जिसके अंतर्गत (1) मद्रास (2) तिरुचिरापल्ली और (3) विशाखापटनम स्थित उसकी शाखाएं भी है । नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019(97) 82-पी०एफ० (II)]

S.O. 2723.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Repatriates Co-operative Finance and Development Bank Limited, 142-A, Santhome High Road, Madras-4 including its branches at (1) Madras, (2) Trichirapally and (3) Visakhapatnam, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central

Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(97)/82-PF. II]

CORRIGENDUM

S.O. 2724.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 716 dated the 30th January, 1982 publised at page 727 of the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 20th February, 1982 for the word "Conclec" read "Conelec".

[No. S. 35019(311)/81-PF. II]

का०आ० 2725.—मैसर्स एच०एम० एम० लिमिटेड, दोवलस्वरम, पूर्वी गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदान या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, का ऐसा विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अवरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्यय का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियम की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत अपेक्षित प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां ऐसा संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का समाधान हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उक्त सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस निश्चित तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निधि से बीमाकृत रकम के प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं एम०-35014/61/82 पी एफ० (ii)]

S.O. 2725.—Whereas Messrs H.M.M. Limited, Dowali Swaram, East Godavari District, Andhra Pradesh, (hereinafter referred to as the said establishment) have be applied for exemption under sub-section (24) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

AND WHEREAS, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establish-

ment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pdadesh and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features there of, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits abailable to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioned. Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any rrason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (61)/82-PF-II]

का०आ० 2766.—मैसर्स जिन्दल ऐलुमीनियम लिमिटेड, 1/6 बी आसफअली रोड, नई दिल्ली-110002 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात (उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी अंशदायी या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए वे फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तनों से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, तो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम का उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम

निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की इस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निधि से, बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस०-35014/37/82-पी०एफ० (ii)]

S.O. 2726.—Whereas Messrs Jindal Aluminium Limited, 1/6, B Asaf Ali Road, New Delhi-110002, (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the privisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner ,the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(37)/82-PF-II]

का०आ० 2727.—मैसर्स पट्टालोमगन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड निशामने नगर टार्नीथाइम नगर कोवल-629001, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध

बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निदिष्ट करे।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निदिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध उन फायदों से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम इस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस० 35014/39/82-पी० एफ-2]

S O. 2727.—Whereas Messrs Kattahomman Transport Corporation Ltd, Nesamony Nagar, Ranithotharm, Nagercoil-629001, (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for the period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits avail-

able under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (39)/82-PF-II]

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1982

का० आ० 2728.—मैसर्स मदास ऐलुमिनियम कंपनी लिमिटेड, मेट्टूर डैम-636402 (टी एन/3546)

(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं को रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की अधिसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी ओर से अपेक्षित प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशिती या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस०-35014/58/82-प्र०नि० (II)]

New Delhi, the 9th July, 1982

S.O. 2728.—Whereas Messrs Madras Aluminium Company Limited, Mettur Dam-636402 (TN/3546), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exmption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(58)/82-PF. II]

का० आ० 2729—मैसर्स दीपक टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, 80-बी, औद्योगिक क्षेत्र आगरा-बम्बई मार्ग, देवास-2155001 (मध्य प्रदेश) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो भविष्यनिधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है,

उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बी स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहा, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपनाचुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसाप्रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती हैं।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

17. उक्त स्थापन के संबध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने क सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014/59/82-पी० एफ-2]

S.O. 2729.—Whereas Messrs Deepak Woollen Pvt. Ltd. 80-B, Industrial Area, Bombay Road, Dewas-455001 (M.P.) (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act,);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administrations of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Lift Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favorable to employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S 35014(59/82-PF. II]

का० आ० 2730.—मैसर्स सेंट्रल मशीन टूल्स इंस्टीट्यूट बंगलौर (कर्नाटक-5672) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा, 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक शहर गया है। 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण और निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त-स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014/123/81-पी० एफ-2]

S.O. 2730.—Whereas Messrs Central Maching Tools Institute, Bangalore (KN-5672) (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Not, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme, for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment (hereinafter referred to as employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts and payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where, the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(123)/81-PF-II]

का०आ० 2731.--मैसर्स ऊषा सेल्स लिमिटेड, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 (डी०एल 2481) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा कया है) में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिये उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनसची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय प निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वह नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने क युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नही रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कमचारियों

को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस० 35014/191/82 भ० नि० (II)]

S.O. 2731.—Whereas Messrs Usha Sales Limited, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi--110001 (DL/2481) hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miseallaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme. 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Delhi and maintain such accounts and Provident or such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including miantenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premimum in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enchance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employess than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premimum the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of decessed members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation.

[No. S-35014(191)/82-PF. II]

का०आ० 2732—मैसर्स होवे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 81, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 (डी०एस० 2372) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिये उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा

निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारो का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययो का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियो की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बात का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नही रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती हैं।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पॉलिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस०-35014/217/82-भ०नि०-II]

S.O. 2732.—Whereas Messrs Home (India) Private Limited, 81, Nehru Place, New Delhi-110019 (DL/2372) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period for threee years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the Employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (217)/82-PF-II]

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1982

का०आ० 2733.—राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अनुसरण में डा० आर०आर० पुरोहित के स्थान पर डा० ज्ञान काश, कार्यवाहक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, जयपुर को चिकित्सा प्रसुविधा परिषद् मे उस राज्य से प्रतिनिधित्व करने के लिये नामनिर्दिष्ट किया है,

अतः, अब केन्द्रीय सरकार कमचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 3329 दिनांक 19 नवम्बर, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "(संबंधित राज्य सरकारों द्वारा धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)", शीर्षक के नीचे मद 19 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"डा० ज्ञान प्रकाश, कार्यवाहक निदेशक,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
राजस्थान सरकार, जयपुर।"

[संख्या यू०-16012/12/82-एच-II]

ए० के० भट्टराई, अवर सचिव

New Delhi, the 7th July, 1982

S.O. 2733.—Whereas the State Government of Rajasthan has, in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated D. GYAN PARKASH, Acting Director, Employees' State Insurance Scheme, Jaipur to represent that State on the Medical Benefit Council in place of Dr. R.R. Purohit;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 10 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3329, dated 19th November, 1981, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Governments concerned under clause (d) of sub-section (1) of section 10)" for the entry against item 19, the following entry shall be substituted, namely :—

"Dr. Gyan Prakash,
Acting Director,
Employees' State Insurance Scheme,
Government of Rajasthan,
Jaipur."

[No. U-16012/12/82-HI]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1982

का०आ० 2734—लोहा अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 3 के उप-नियम, (2) के साथ पठित लोहा अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि, 1976 (1976 का 61) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 4864 तारीख 7 दिसम्बर, 1981 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश के राज्य के लिये एक सलाहकार समिति गठित करती है, जिसमें निम्नलिखिश सदस्य शामिल हैं, अर्थात् :—

1. श्रम मंत्री, आन्ध्र प्रदेश राज्य, हैदराबाद।	अध्यक्ष
2 कल्याण आयुक्त, लोहा अयस्क और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण संगठन, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश, 75, मिलर्स रोड, बंगलौर-560052	उपाध्यक्ष
3. उप श्रमायुक्त, लोहा अयस्क और मैंगनीज अयस्क खान कल्याण संगठन, आन्ध्र प्रदेश, मकान नं० 3-5-804/2/4, राज रैड्डी मार्ग, हैदरगुडा, हैदराबाद-500001	सदस्य पदेन
4 श्री मल्लादी स्वामी, विधायक, जिला खमाम, आन्ध्र प्रदेश,	सदस्य
5 श्री एल०पी० सरवोजी, प्रबन्धक निदेशक, सरवोजी एण्ड कम्पनी, चिपुरूपल्ली, विजियानग्राम	लोहा अयस्क और मैंगनीज अयस्क और खान मालिकों के प्रतिनिधित्व
6 श्री ई० एस० रैड्डी, बी०ई०एम०एस० (यु० एस० ए०) एम०आई० एस०टी० ई०, एम०ई० (इंडिया) ए०पी०ए०एस०, प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश खनन निगम, हैदराबाद।	
7. श्री एस० रमी रैड्डी, राष्ट्रीय मजदूर सभा, नेता, बालिपिट, डाकघर, कोथागुडम कलोनी, जिला खमाम, आन्ध्र प्रदेश	लोहा अयस्क और मैंगनीज अयस्क खानों में नियोजित

8.	श्री एस० अब्बाई नायडु, ट्रेड यूनियन नेता, डाकघर : चिरापुरूपल्ली, विजियानाग्राम-532128	व्यक्तियों के प्रतिनिधि ।
9.	श्रीमती लक्ष्मी रघुराम, गांव, कुंताकापल्ली, जिला : विशाखापतनम	महिला प्रतिनिधि
10.	उप कल्याण आयुक्त, लोहा अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान कल्याण संगठन, हैदराबाद ।	सचिव

2. लोहा अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 16 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त समिति का मुख्यालय हैदराबाद निर्धारित करती है ।

[फाईल सं० यू०-23017/4/80-एम०-4]
अशोक गुप्त, उप-सचिव

New Delhi, the 7th July, 1982

S.O. 2534.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Act 1976 (61 of 1976) read with sub-rule (2) of rule 3 of the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Rules 1978 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 4864 dated the 7th December, 1981, the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee for the State of Andhra Pradesh consisting of the following members, namely:—

1.	Minister for Labour, State of Andhra Pradesh, Hyderabad.	Chairman.
2.	Welfare Commissioner, Iron Ore and Manganese Ore Mines Labour Welfare Organisation, Karnataka and Andhra Pradesh, 75, Millers Road, Bangalore—560052.	Vice-Chairman
3.	Deputy Welfare Commissioner, Iron Ore and Manganese Ore Mines Labour Welfare Organisation, Andhra Pradesh, H. No. 3-5-804/2/4., Raj Reddy Marg, Hyderguda, Hyderabad—500001.	Member Ex-Officio
4.	Shri Malladi Swamy, Member of Legislative Assembly, Parajurapet, Kakanada, East Godawari District.	Member.
5.	Shri L.P. Sarvoji, Managing Director, Sarvoji and Company, Cheepurupalli, Vijianagaram, Andhra Pradesh-532128.	Representatives of Iron Ore and Manganese Ore Mine owners.
6.	Shri E.S. Reddi, B.E.,M.S. (USA), M.I.S.T.E., M.E. (India), A.P.A.S., Managing Director, Andhra Pradesh Mining Corporation, Hyderabad.	
7.	Shri S. Rami Reddy, I.N.T.U.C., Leader, Barlipit, P.O. Kothagudem Colony, District Khamam, Andhra Pradesh.	
8.	Shri M. Abbai Naiadu, Trade Union Leader, P.O. Cheepurupalli, Vijianagaram-532128.	Representatives of persons employed in Iron Ore and Manganese Ore Mines.
9.	Shrimati Laxmi Raghuram, Kuntakapalli Village, Visakhapatnam District.	Women Representative.
10.	Deputy Welfare Commissioner, Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Welfare Organisation, Hyderabad.	Secretary.

2. In pursuance of rule 16 of the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Rules 1978, the Central Government hereby fixes Hyderabad to be the headquarters of the said Advisory Committee.

[File No. U-23017/4/80-M.IV]
ASOK GUPTA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1982

का०आ० 2735.—खान मुख्य निरीक्षक ने, कोयला खान बचाव नियम, 1959 के नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड (I) के अनुसरण में, श्री बी०के० शरण, खान सुरक्षा निदेशक को, श्री एच०के० राय के स्थान पर केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट किया है,

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, कोयला खान बचाव नियम 1959, के नियम 3 के उपनियम (I) के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 811, तारीख 15 मार्च, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, अध्यक्ष शीर्ष के अधीन मद 1 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :—

"श्री बी० के० शरण, खान सुरक्षा निदेशक	(नियम 3 के उपनियम (I) के खण्ड (I) के अधीन खान मुख्य निरीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट निरीक्षक)"

[सं० यू० 23019/1/78-एम०-I]
जे० के० जैन, अवर सचिव

New Delhi, the 7th July, 1982

S. O. 2735.—Whereas the Chief Inspector of Mines has, in pursuance of clause (i) of sub-rule (1) of rule 3 of the Coal Mines Rescue Rules, 1959, nominated Shri B.K. Sharan, Director of Mines Safety, as President of the Central Coal Mines Rescue Stations Committee *Vice* Shri H.K. Roy;

Now, therefore, in pursuance of sub-rule (i) of rule (3) of the Coal Mines Rescue Rules, 1959, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 811 dated the 15th March, 1980, namely:—

In the said notification, under heading President, for the entries, against item 1, the following entries shall be substituted, namely:—

"Shri B.K. Sharan, Director of Mines Safety	(An inspector nominated by the Chief Inspector of Mines under clause (i) of sub-rule (1) of rule 3)"

[No. U-23019/1/78-M.I]
J. K. JAIN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982